सूर्योदय 6.13 सूर्यास्त 6:09

आज का तापमान

शिमला	13.0 न्यू	19.0 अधि
धर्मशाला	16.0 न्यू	23.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	72,772
निफ्टी	22, 781

सोना 1,48,000 चांदी 2,23,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | मंगलवार, 29 सितंबर 2026 | 13 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 155, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

इथियोपिया में तीन भारतीयों का अपहरण

एजेंसी, अहमदाबाद। गैरकानूनी तरीके से अमेरिका जा रहे तीन भारतीयों का इथियोपिया में किडनैप कर लिया गया है। तीनों गुजरात के रहने वाले हैं। इनमें दो लड़कियां और एक युवक शामिल है। तीनों 20 सितंबर को गुजरात से रवाना हुए थे। इसी बीच इथियोपिया पहुंचते ही तीनों का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने तीनों की रिहाई के बदले में इनके परिवार से एक करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। तीनों के परिवार वालों ने फिरौती की रकम दे दी है, लेकिन इसके बाद भी तीनों से परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। यह पूरा मामला तब सामने आया, जब इनके साथ गया एक अन्य युवक फिरौती की रकम देकर लौट आया।

महाराष्ट्र के सोलापुर में तुलशी गांव बेचने का बोर्ड लगा, कीमत सिर्फ पानी

एजेंसी, सोलापुर। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तुलशी गांव में पानी की कमी से परेशान लोग गांव बेचने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक बोर्ड भी लगाया है। हालांकि, गांव की कीमत सिर्फ पानी रखी गई है। बोर्ड में यह भी लिखा है कि आखिर अन्याय कब तक सहन करें। माढा तहसील के तुलशी गांव की आबादी करीब 7 हजार है। अधूरे सीना-माढा लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट के कारण गांव कई साल से टैंकरों पर निर्भर है। ग्रामीणों का दावा है कि गांव के पास से नहरें गुजरती हैं। इसके बावजूद उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। गांव में इस साल बारिश कम होने से संकट और बढ़ गया है। दरअसल, राज्य सरकार ने 26 सितंबर को राज्य की 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित किया है। साथ ही राहत पैकेज की घोषणा भी की है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने 10 राज्यों में किया प्रदर्शन

एजेंसी, नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के 10 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली और केरलम में प्रदर्शन किया। यूपी के आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के घर पर कालिख पोती और लिखा- 'ज्ञानेश कुमार गद्दार, वोट चोर'। राजस्थान के जयपुर में विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। विरोध में पर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल थे।

बैंक हड़ताल टली, 5-डे वर्किंग को कमेटी बनेगी

एजेंसी, नई दिल्ली। देशभर में सभी बैंक आम दिनों की तरह खुले रहेंगे और बैंकिंग से जुड़े सभी काम रोजाना की तरह होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने 28 से 30 सितंबर के बीच बुलाई गई अपनी 3 दिन की हड़ताल टालने का फैसला किया है। रविवार देर रात हुई बैठक में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने 5-डे वर्किंग के लिए कमेटी बनाने पर सहमति बनी है। साथ ही कर्मचारियों की अन्य मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। हड़ताल टलने से इस हफ्ते 5 दिन बैंक खुलेंगे और सिर्फ 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के मौके पर बंद रहेंगे।

क्लास 6 से 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

इस साल 3 भाषा में स्टूडेंट्स फेल नहीं किए जाएंगे; सीबीएसई ने छूट का विरोध किया था

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीएसई की छठी कक्षा के छात्रों को 3-लैंग्वेज पॉलिसी से छूट दी जाए।

कोर्ट का यह आदेश 1 अप्रैल 2027 से लागू किया जाए। यानी अगले साल क्लास 6 में जा रहे स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स छठी क्लास में हैं, उन्हें तीसरी भाषा में पास या फेल नहीं किया जाएगा। उन्हें केवल अपीयरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले केंद्र सरकार ने छठी कक्षा को छूट देने से इनकार किया था। सातवीं, आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों को पहले ही यह राहत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि छठी कक्षा के छात्रों को अचानक भाषा बदलने से परेशानी हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच सीबीएसई के तीन-भाषा फॉर्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।



केंद्र ने कहा- 99% स्कूलों ने 3 भाषा की नीति अपनाई

सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इस साल से छठी कक्षा के छात्रों को छूट देने के पक्ष में नहीं है। केंद्र ने बताया कि करीब 2,800 स्कूलों के आंकड़ों के अनुसार, केवल 1.2% स्कूल प्रभावित हुए हैं। सरकार के मुताबिक करीब 99% स्कूलों ने तीसरी भाषा की नीति अपनाई है और उन्हें जरूरी सुविधाएं दी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट बोला-चुनाव आयोग 4 महीने में टीएमसी विवाद सुलझाए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और 'फूल-पत्ती' चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद पर फैसला देने की समय-सीमा तय की। कोर्ट ने दोनों गुटों को एक महीने में अपनी दलीलें पूरी करने और इसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने में फैसला देने का निर्देश दिया। यानी पूरी प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करनी होगी। चुनाव आयोग ने विवाद को सुलझाने के लिए 6 महीने का समय देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। यह आदेश ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया। उन्होंने चुनाव आयोग के उस अंतरिम फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें टीएमसी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल रोक दिया गया था। शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा विवाद करीब 4 साल से पेंडिंग है, जबकि एनसीपी का मामला भी 3 साल से पेंडिंग है। दोनों मामलों में अलग-अलग गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा किया है।

भारत को एशियन गेम्स के जेवलिन में सिल्वर व ब्रॉन्ज

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने एशियन गेम्स के जेवलिन में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत लिया है।

यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर के पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर हासिल किया। रोहित यादव ने 84.35 मीटर के साथ ब्रॉन्ज जीता। इससे पहले श्रीशंकर मुरली ने लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता। उन्होंने 8.07 मीटर की जंप लगाई। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर रेस में सिल्वर अपने नाम किया। इससे पहले वित्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर हर्डल रेस में ब्रॉन्ज जीतकर पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा था। गुलवीर ने 1500 मीटर रेस 3 मिनट 36.72 सेकेंड में पूरी की। पारुल ने 5000 मीटर में 15:14.61 सेकेंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। वित्या ने 400 मीटर हर्डल रेस 54.75 सेकेंड में पूरी की। इससे पहले यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड पीटी उषा



यशवीर व रोहित ने मेडल जीते; मुरली श्रीशंकर को लॉन्ग जंप में सिल्वर

के नाम था, जिन्होंने 1984 लॉस एंजिल्स ओलिंपिक में 55.42 सेकेंड का समय निकाला था। सोमवार को ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में सिल्वर जीता। फाइनल में ईशा और चीन की जियाओ जियारुइक्सुआन के 38-38 पॉइंट थे। मुकाबला शूटआउट में गया, जहां जियाओ ने जीत दर्ज की।

ईशा ने 580 अंक के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मनु भाकर मेडल इवेंट तक नहीं पहुंच सकीं। भारत को एशियन गेम्स के 9वें दिन 8 मेडल मिले। टीम मेडल टैली में 12वें स्थान पर है।

देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में आठ फीसदी बढ़ा

एजेंसी, नई दिल्ली। देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 8 फीसदी बढ़ा, जबकि जुलाई में इसमें 7.4 फीसदी की वृद्धि हुई थी। यह नई श्रृंखला के तहत जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 5वां मासिक आंकड़ा है। अगस्त, 2025 में देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.7 फीसदी की वृद्धि हुई थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को जारी आंकड़ों में बताया कि विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन और बिजली एवं गैस आपूर्ति में मजबूत वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन को गति मिली है। आईआईपी की इस बढ़ोत्तरी में मध्यवर्ती वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का सबसे अधिक योगदान रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के मुताबिक अगस्त महीने में आईआईपी में सालाना आधार पर आठ फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

सुप्रीम कोर्ट का यूपीआई चार्ज पर रोक से इनकार

2000 से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4 फीसदी चार्ज तय

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

15 अक्तूबर से यह शुल्क 2000 रुपए से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर लागू होगा। हालांकि, कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि इस नए नियम को लागू करने का आधार क्या है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन जजों की बेंच ने वकील अंजन दत्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। एडवोकेट अंजन दत्ता ने जनहित याचिका में सवाल उठाया कि 2,000 रुपए की सीमा क्यों तय की गई? यूपीआई और रूपे कार्ड के लिए नियम अलग क्यों हैं। याचिका में इसे रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में यह भी



कहा गया कि सरकार ने जनता से चर्चा किए बिना और कोई ठोस नियम बनाए बिना ही यह फीस तय कर दी। इसके अलावा, 'पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007' के एक नियम (धारा 10अ) को भी अदालत में चुनौती दी गई। आरोप है कि यह नियम सरकार को अपनी मर्जी से यह फैसला करने की छूट देता है कि कौन-सा डिजिटल पेमेंट फ्री रहेगा और किस पर चार्ज लगेगा। सरकार की तरफ से एएसजी एन. वेंकटरमण ने कहा कि आम लोगों के आपस में पैसे भेजने पर चार्ज नहीं लगेगा। देश के लगभग 96% छोटे-मोटे दुकानदारी वाले भुगतानों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च

पहली बार 26 सैटेलाइट्स छोड़ेगा, पृथ्वी के चक्कर भी लगाएगा; यह 14वां टेस्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सबसे ताकतवर रॉकेट 'स्टारशिप' को 28 सितंबर को भारतीय समयानुसार शाम 6:16 बजे लॉन्च किया गया।

ये स्टारशिप का 14वां टेस्ट है। यह पहली बार है जब स्टारशिप को पृथ्वी की ऑर्बिट में भेजा गया है, जहां यह पृथ्वी के 6 चक्कर लगाएगा और सैटेलाइट्स छोड़ेगा। इसके बाद यह चिली के पास समुद्र में लैंड करेगा। इससे पहले की सभी उड़ानों में रॉकेट को सब-ऑर्बिटल ट्रैजेक्टरी तक ही सीमित रखा गया था, ताकि सुरक्षा बनी रहे और ज्यादा से ज्यादा डेटा जुटाया जा सके। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट (ऊपरी हिस्सा) और सुपर हैवी बूस्टर (निचला हिस्सा) को कलेक्टिवली 'स्टारशिप' कहा जाता है। इस व्हीकल की ऊंचाई 403 फीट है। इस मिशन में स्टारशिप जमीन से



लगभग 275 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा। करीब 10 घंटे लंबे इस सफर में यह पृथ्वी के 6 चक्कर पूरे करेगा।

मिशन खत्म होने के बाद रॉकेट चिली देश के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित पानी पर लैंड यानी स्प्लैशडाउन करेगा। इस उड़ान से पहली बार नई तकनीक वाले 26 'स्टारलिंक V3' सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। इनसे पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड और नेटवर्क काफी बेहतर हो जाएगा। इस नए मॉडल का सिर्फ एक सैटेलाइट ही नेटवर्क में 1 टेराबिट प्रति सेकेंड की डेटा क्षमता जोड़ देगा, यानी इस अकेले मिशन से कुल 26 टीबीपीएस की क्षमता जुड़ जाएगी, जो कि फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजे जाने वाले छोटे सैटेलाइट्स के मुकाबले लगभग 10 गुना ज्यादा है।

नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की आर्थिक स्थिति व केंद्रीय बजट का मुद्दा उठाएंगे सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार को खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए। शिमला में लगातार हो रही बारिश के चलते मुख्यमंत्री का चौपर उड़ान नहीं भर सका।

मुख्यमंत्री के सुबह रवाना होने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण यात्रा का माध्यम बदलना पड़ा और वह दोपहर में गाड़ी से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री 28 और 29 सितंबर को आयोजित होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दों को सामने रख सकते हैं। साथ ही केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रदेश को मिलने वाली



बारिश के चलते सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना हुए सीएम

धनराशि समय पर जारी करने का आग्रह भी किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुक्खू के 29 सितंबर को शिमला लौटने का कार्यक्रम बताया गया है। दिल्ली प्रवास के दौरान वह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे।

इसके अलावा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के कांग्रेस हाईकमान के नेताओं से मुलाकात करने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान हिमाचल मंत्रिमंडल में नए मंत्री को शामिल किए जाने से जुड़े विषय पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिया जाएगा।

उज्जैन शाही मस्जिद मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

पथराव-लाठीचार्ज हुआ, 20 पर एएफआईआर

एजेंसी, उज्जैन। उज्जैन के शाही मस्जिद मामले में दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया।

याचिकाकर्ता शाही मस्जिद कमेटी के एडवोकेट कुलदीप पाठक ने कहा- कमेटी और प्रशासन के बीच समझौते के तहत सड़क के लिए 3 फीट जगह के साथ कुछ दुकानें हटाने पर सहमति बनी है। बड़ी मीनार को दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा। दुकानों के लिए दूसरी जगह दी जाएगी। इससे पहले सोमवार सुबह मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। जवाब में लाठीचार्ज



और आंसू गैस छोड़ी गई। भीड़ को हटाने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं। विवाद के बाद फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन दोपहर होते-होते फिर पथराव होने लगा। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर आंसू गैस छोड़ी। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही। हालांकि, नमाज के समय इसे रोक दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया। पुलिस ने 3 थानों में 20 लोगों के खिलाफ 8 नामजद स्रढ्ढ, दर्ज की हैं। इनमें 5 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। इन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप है। 15 लोगों को हिरासत में लिया है। सिंहस्थ प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन में कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक डेढ़ किलोमीटर एरिया की सड़क 15 मीटर चौड़ी की जाएगी। इसके लिए 323 मकान तोड़े जाएंगे। इनमें 15 धर्मस्थल हैं, अब तक 12 धर्मस्थल हटाए जा चुके हैं। सड़क के दायरे में शाही मस्जिद का भी करीब 9 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा हिस्सा आ रहा है। दस्तावेज में इस मस्जिद के 100 साल से ज्यादा पुरानी होने की पुष्टि होती है। हालांकि, इमाम का दावा है कि यह 600 साल से ज्यादा पुरानी है।

कुपवाड़ा में सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत, छह घायल

एजेंसी, कुपवाड़ा। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह इलाके में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जीएमसी हंदवाड़ा रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और राहत दलों ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में मदद की।

दिल्ली सरकार व आईसीसीआर के बीच एमओयू सांस्कृतिक व शैक्षणिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा

एजेंसी, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में सोमवार को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) और दिल्ली सरकार के बीच सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य दिल्ली सरकार और आईसीसीआर के बीच संस्थागत साझेदारी स्थापित करना है, जिसके माध्यम से सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे दिल्ली की संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ आईसीसीआर को सांस्कृतिक कूटनीति से जुड़े अपने दायित्वों को पूरा करने में भी सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल



सीएम रेखा गुप्ता ने कहा- दिल्ली की कला व संस्कृति को मिलेगा वैश्विक मंच

मिश्रा कपिल मिश्रा सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी दिल्ली की कला, संस्कृति और प्रतिभाओं को देश-दुनिया के व्यापक मंच से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे दिल्ली के कलाकारों और सांस्कृतिक समूहों को अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के अवसर मिलेंगे तथा विदेशी कलाकारों व सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। आईसीसीआर के साथ यह संस्थागत साझेदारी दिल्ली की संस्कृति, पर्यटन व रचनात्मक अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस समझौते के अंतर्गत दिल्ली के स्थापित व युवा कलाकारों को आईसीसीआर की प्रतिष्ठित 'होराइजन सीरीज' और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों में सहभागिता का सीधा अवसर मिलेगा।

सीएम धामी ने उत्तरकाशी में राहत-बचाव अभियान का लिया जायजा, ऑडेन कोल से 29 ट्रैकर्स का हेली रेस्क्यू

एजेंसी, देहरादून। उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के बीच चल रहे राहत एवं बचाव अभियान की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली से जानकारी ली। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर अभियान की स्थिति की समीक्षा की और ट्रैकिंग एवं पर्वतारोहण के लिए गए ट्रैकर्स तथा पोर्टरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रशासन के अनुसार, ऑडेन कोल क्षेत्र में फंसे सभी 29 ट्रैकर्स का सफलतापूर्वक हेली रेस्क्यू कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी ट्रैकर्स को हर्षिल हेलिपैड पहुंचाया गया। वहां उनका प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य जांच की गई। प्रशासन ने सभी ट्रैकर्स का स्वास्थ्य सामान्य बताया है। प्राथमिक उपचार के बाद सभी अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने



अधिकारियों को निर्देश दिया कि बर्फबारी प्रभावित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद प्रत्येक पर्यटक और ट्रैकर को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने रेस्क्यू किए गए लोगों को चिकित्सीय सहायता, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक, ऑडेन कोल क्षेत्र से ट्रैकर्स को सुरक्षित निकालने के बाद अब कालिंदी पास क्षेत्र में भी हेली रेस्क्यू अभियान जारी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य के लिए संबंधित विभागों और एजेंसियों को तैनात किया गया है। बर्फबारी और मौसम की स्थिति को देखते हुए अभियान को आवश्यक समन्वय के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी में हाल में हुई बारिश से हुए नुकसान की भी जानकारी ली।

उन्होंने प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने, बंद सड़कों को जल्द खोलने और क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत का कार्य तेजी से कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

कार्यक्रम

मुख्यमंत्री योगी ने नवचयनित एक हजार 375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को दिया नियुक्ति पत्र

आज बिना भेदभाव के युवाओं को दी जा रही नौकरी: योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक हजार 375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया।

मुख्यमंत्री ने मंच से 11 अभ्यर्थियों को अपने हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने चयनित अभ्यर्थियों और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज हमारी सरकार में बिना भेदभाव के लिए युवाओं को नौकरी दी जा रही है। योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 10 साल पहले जिस उप्र की पहचान एक बीमारू राज्य की थी, आज वह उत्तर प्रदेश



कहा- अगले छह माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य

देश के अग्रणी राज्यों में गिनती हो रही है। बिना लेन-देने के साढ़े नौ लाख युवाओं ने सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। उन्हीं युवाओं की प्रतिभा के कारण आज प्रदेश तरक्की कर रहा है। पहले की सरकारों में योग्यता होने के बावजूद गरीब परिवारों के बच्चों नौकरी मिल ही नहीं सकती थी। माफिया राज में जकड़ा हुआ था। हमने तय किया माफियाराज खत्म करना है। आज माफिया सिर नहीं उठा सकता। आज यूपी के लोगों के सामने पहचान का संकट नहीं है। जिन लोगों ने पहचान का संकट किया था, जिन लोगों ने दलितों, पिछड़ों के हक पर डकैती डालने का काम किया था, आज वे नए रूप, स्लोगन के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलते नजर आ रहे हैं। योगी ने कहा कि 10 साल पहले उप्र की देश के सबसे पिछड़े पांच राज्यों में गिनती होती थी, आज हमारी शीर्ष पांच राज्यों में गिनती हो रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी हुई है। यह बदलाव जो आया है, वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। आज के दिन को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए चयन करने के लिए पंचायती राज विभाग को धन्यवाद देता हूं। आज महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह की जयंती का अवसर है। हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यस्था, नौकरी में भ्रष्टाचार, खराब सड़कें और ध्वस्त बिजली व्यवस्था को लेकर 2017 से पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज उप्र दंगा, कर्फ्यू मुक्त है। 20 सितंबर से लेकर अब तक यह चौथा नियुक्ति वितरण कार्यक्रम है। अगले छह माह में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

उप्र से 2027 के विस चुनाव में सपा को साफ कर देना है : ओम प्रकाश राजभर

पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभार ने चयनित अभ्यर्थियों से कहा कि वे लोग हाथ उठाएं, जिन्होंने बिना घूस दिए नौकरी पाई है। इस पर सभागार में बैठे सभी युवाओं ने हाथ उठाया। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती निकलते ही सपा के लोग बिना पैसे लिए नौकरी नहीं देते थे। यह बदलाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसलिए यहां से जाने के बाद अपने माता पिता को प्रमाण कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि नौकरी पा सको। प्रचार कीजिएगा कि बिना घूस दिए आपको नौकरी मिली है। हनुमान जी ने अकेले रावण की लंका जलाई थी। आप सब मिलकर समाजवादी पार्टी की लंका जलाएंगे। 2027 के चुनाव में सपा को साफ कर देना है और कांग्रेस को आफ करना है।

सिसोदिया ने कांग्रेस सरकार से विकास का मांगा रिपोर्ट कार्ड

रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण सुविधाओं पर जवाब



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सिसोदिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की मांग की है। सोमवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहती है।

सिसोदिया ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसके कार्यकाल में युवाओं के लिए कितने रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। उन्होंने पंचायतों और जिला परिषदों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों तथा विकास कार्यों की स्थिति भी सार्वजनिक करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ी हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी जनता सरकार के कामकाज का आकलन कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायतों और जिला परिषदों को पर्याप्त वित्तीय एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है।

चुनावी प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

सिसोदिया ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक बहस तथ्यों, आधिकारिक अभिलेखों और कानूनी आधार पर होनी चाहिए। एसआईआर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक का मताधिकार सुरक्षित रहना चाहिए।

जल निकासी और सुरक्षा ऑडिट से हिमाचल में सड़कें होंगी अधिक टिकाऊ और सुरक्षित

बहुउपयोगी भूमिगत डक्ट से बार-बार सड़क खोदने की समस्या होगी खत्म

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क को आधुनिक तकनीक, बेहतर जल निकासी व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के कठिन भौगोलिक परिवेश और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए सड़कों को अधिक टिकाऊ और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं।

31 अगस्त तक प्रदेश में सड़कों का कुल नेटवर्क 41,903 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इससे 15,608 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। सरकार का जोर अब मौजूदा सड़क ढांचे को मजबूत करने के साथ निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक सुरक्षा मानकों को लागू करने पर है।

विशेष जल निकासी नीति लागू: पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के दौरान जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसे देखते हुए सरकार ने फरवरी में विशेष सड़क जल निकासी नीति लागू की है। इसके तहत सड़क की योजना और डिजाइन तैयार करते समय वर्षा की तीव्रता, जलग्रहण क्षेत्र और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नालियों और जल निकासी ढांचे का निर्माण अनिवार्य किया गया है।

सड़क किनारे बनी नालियों में अवरोध पैदा करने या उन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रविधान किया गया है। इससे बारिश के पानी को व्यवस्थित तरीके से निकालने और सड़क की संरचना को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

संपर्क मार्गों के लिए भी सुरक्षा मानक : सरकार ने जीप और एंबुलेंस संपर्क मार्गों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें सड़क की निर्धारित चौड़ाई, सतह निर्माण, रिटेनिंग वाल, ब्रेस्ट वाल, ढलान संरक्षण और क्रैश बैरियर जैसे सुरक्षा उपायों के मानक तय किए गए हैं।



आपदा प्रभावित मार्गों की निगरानी और मरम्मत व्यवस्था होगी मजबूत

इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बने संपर्क मार्गों को भी सुरक्षित और लंबे समय तक उपयोगी बनाना है। आपात स्थिति में एंबुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं की आवाजाही सुचारू बनाए रखना भी इन दिशा-निर्देशों का अहम हिस्सा है।

सड़क स्थिति की मिलेगी तत्काल जानकारी : सड़क प्रबंधन को तकनीक से जोड़ने के लिए केंद्रीकृत रोड स्टेटस इन्फार्मेशन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके माध्यम से मानसून और प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों को सड़क बंद होने, वैकल्पिक मार्ग और बहाली कार्य की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

निर्माण कार्यों और वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से माप पुस्तिका और बिल संबंधी कार्यों को डिजिटल बनाया जाएगा।

जुलाई 2026 में स्वीकृत सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति के तहत सड़कों की योजना, निर्माण और वर्तमान स्थिति का नियमित सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य किया गया है। लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है। यह प्रकोष्ठ दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और ब्लैक स्पाट की पहचान कर वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्य सुनिश्चित करेगा।

भूमिगत डक्ट से बार-बार खुदाई पर लगेगी रोक

अक्सर सड़क निर्माण के बाद पानी, बिजली या दूरसंचार की लाइनें बिछाने के लिए दोबारा सड़क की खुदाई करनी पड़ती है। इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ सार्वजनिक धन का भी नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए सरकार मुख्य मार्गों के साथ भूमिगत बहुउपयोगी डक्ट बनाने की योजना पर काम कर रही है। इन डक्ट में विभिन्न सेवाओं की लाइनें एक निर्धारित व्यवस्था के तहत डाली जा सकेंगी। इससे भविष्य में सड़क को बार-बार खोदने की जरूरत कम होगी और सड़क की उम्र बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन



कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रदर्शन किया गया।

◆मतदाता पुनरीक्षण पर कांग्रेस ने जताया विरोध

शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा।

शिमला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल और शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई और पद से हटाने की मांग रखी।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने से उनके मताधिकार पर असर पड़ सकता है। पार्टी ने इस प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन आयोग से पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की है। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सेवाओं और विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी अपने आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद

प्रदर्शन में हिमाचल कांग्रेस के उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, चंद्रशेखर शर्मा, विजय चौहान, देवेंद्र ठाकुर, राजेश शर्मा, जैनब चंदेल, दीपक राठौर, ममता, अनुराधा, सुरेंद्र रेटका, पवन वर्मा, रमेश चंदेल, जितेंद्र ब्रागटा, पवन हिमटा, महेश वर्मा, दिनेश मेहता, राम सिंह जसवाल, राजेश्वर जसवाल, घनश्याम हिमराल, विशाखा मोदी, सत्या वर्मा, दीपक सुन्दरियाल और महेंद्र कुमार सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

थियोग में विद्यार्थियों ने समझी क्वांटम विज्ञान की दुनिया

विशेषज्ञ ने समझाए आधुनिक तकनीक में क्वांटम सिद्धांतों के उपयोग

भारतेन्दु संवाददाता, थियोग। राजकीय महाविद्यालय थियोग में सोमवार को 'द क्वांटम वर्ल्ड' विषय पर विशेष अकादमिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को क्वांटम भौतिकी की रोचक दुनिया और आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसके अनुप्रयोगों से परिचित करवाना था। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के अलावा आसपास के विद्यालयों के शिक्षक एवं विद्यार्थी भी शामिल हुए।



विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी में विज्ञान की नई अवधारणाओं को करीब से जाना।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर एवं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स के अध्यक्ष प्रो. पी.के. अहलूवालिया ने मुख्य व्याख्यान दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को क्वांटम यांत्रिकी की मूल अवधारणाओं की जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म जगत को समझने से आधुनिक विज्ञान के विकास को नई दिशा मिली है।

उन्होंने सेमीकंडक्टर, लेजर, क्वांटम संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्वांटम सिद्धांतों के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया। संवादात्मक प्रस्तुति के माध्यम से विद्यार्थियों को वैज्ञानिक जिज्ञासा विकसित करने और पाठ्यपुस्तकों से आगे बढ़कर विषय को समझने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 'क्वांटम वर्ल्ड' विषय पर प्रदर्शनी भी लगाई गई।

चिड़गांव में सात ग्राम चिट्टे के साथ युवक गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पुलिस थाना चिड़गांव की टीम ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को करीब सात ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थों से संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर को चिड़गांव पुलिस की टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान बडियारा में रोहड़ू-चिड़गांव मार्ग के विभाजन के समीप पुलिस टीम ने अमित पुत्र सुरेश चौहान, निवासी तहसील चिड़गांव, जिला शिमला को जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से करीब सात ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद हुई।

बरामद नशीले पदार्थ को पुलिस ने कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी के आधार पर पुलिस थाना चिड़गांव में अभियोग संख्या 97/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21 के तहत कार्रवाई की गई है।



पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में नशीले पदार्थ की खरीद-फरोख्त और इसके स्रोत सहित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस टीम यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी के पास नशीला पदार्थ कहां से पहुंचा और क्या इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह भी सक्रिय है।

पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपकर संगठन विस्तार पर चर्चा की गई

शिमला ग्रामीण कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शिमला ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष हरिकृष्ण हिमराल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद यह डीसीसी शिमला ग्रामीण की पहली बैठक थी। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।



बैठक के दौरान संगठन के विभिन्न विंगों के पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। विचार प्रहरी को प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से संगठनात्मक विचारधारा को मजबूत करने का दायित्व दिया गया। वहीं सहकार सारथी के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र से जुड़े स्वयं सहायता समूहों, दुग्ध समितियों और स्वयंसेवी संस्थाओं तक संगठन की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया।

प्रचार प्रमुख को राज्य सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। प्रवक्ताओं एवं मीडिया पैनलिस्टों को विभिन्न मीडिया मंचों पर पार्टी का पक्ष रखने तथा केंद्र सरकार की नीतियों पर कांग्रेस का दृष्टिकोण रखने का दायित्व सौंपा गया।

बैठक में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस की विचारधारा को जमीनी स्तर तक पहुंचाने और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ने पर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद स्थापित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर संगठनात्मक तैयारियां शुरू करने का निर्णय लिया गया।

कुत्तों के हमले में घायल बच्ची के इलाज का खर्च उठाए निगम



नागरिक सभा ने परिवार को दो लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला के शांकली क्षेत्र में कुत्तों के हमले में घायल हुई दो वर्षीय बच्ची के इलाज का पूरा खर्च नगर निगम द्वारा उठाने और परिवार को दो लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की गई है। शिमला नागरिक सभा के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अध्यक्ष जगमोहन ठाकुर के नेतृत्व में नगर निगम उपायुक्त भुवन शर्मा से मुलाकात कर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा।

नागरिक सभा ने बताया कि बच्ची अभी उपचाराधीन है। घटना के बाद परिवार को बच्ची की चिंता के साथ उपचार पर होने वाले खर्च का भी सामना करना पड़ रहा है। सभा ने मांग की कि बच्ची के उपचार में अब तक खर्च हुई राशि और आगे होने वाले इलाज का पूरा खर्च नगर निगम वहन करे।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया करने की मांग की

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उपायुक्त शिमला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। समकालीन रिपोर्ट के अनुसार, ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित चुनावी प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर सवाल उठाए। पार्टी की ओर से मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और हटाने तथा निर्वाचन आयोग की डिजिटल एवं सूचना-प्रौद्योगिकी व्यवस्था से संबंधित फैसलों की स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की मांग भी रखी गई।



ज्ञापन सौंपते हुए इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी नियमों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर उठ रहे सवालों का समाधान किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से हटाने तथा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की मांग भी ज्ञापन में रखी। इस अवसर पर पार्षद विनोद भाटिया, उर्मिला, विशाखा मोदी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल, जिला संगठन महासचिव दीपक सुन्द्रियाल, उपाध्यक्ष कुश पाल सिंह, सत्या वर्मा, जय प्रकाश, नरेश गांधी और उमा वर्मा सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किन्नौर सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 साल की कैद

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। किन्नौर जिले में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक पोक्सो/दुष्कर्म न्यायालय, किन्नौर डिवीजन रामपुर बुशहर ने तबरेज आलम उर्फ बिराज (26), निवासी पश्चिमी चंपारण, बिहार और लखिंदर उर्फ लक्की (24), निवासी ग्रांगे, निचार, किन्नौर को दोषी ठहराया। मामला 27 सितंबर 2025 को भावानगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87, 70, 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने धारा 70(1) के साथ धारा 3(5) के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 87 के साथ धारा 3(5) के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 351(2) के साथ धारा 3(5) के तहत दो वर्ष कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

ननखड़ी पुलिस ने वारंट पर भगोड़ा आरोपी किया गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के तहत कार्रवाई करते हुए एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना ननखड़ी की टीम ने न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करते हुए आरोपी मीना राम को 27 सितंबर को शोघी-आनंदपुर से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अभियोग पीएनबी नीरथ बनाम मीना राम में माननीय न्यायालय द्वारा जारी दोषसिद्ध गैर-जमानती वारंट संख्या 1858/5बी के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मीना राम पुत्र कर्म चंद, निवासी तहसील ननखड़ी, जिला शिमला के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 40 वर्ष बताई गई है।



पुलिस के मुताबिक संबंधित मामले में आरोपी को पंजाब नेशनल बैंक, नीरथ को दो लाख रुपये की राशि अदा करनी थी। न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगातार प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी मौजूदगी की जानकारी मिली और टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे शोघी-आनंदपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानियां पहुंचे नॉर्वे आर्कटिक अध्ययन पर करेंगे चर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां 69वें राष्ट्रमंडल अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद अपनी आधिकारिक अध्ययन प्रवास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए फिनलैंड के रोवानीमी से नॉर्वे के ट्रॉम्सो पहुंचे। उनका नॉर्वे में 30 सितंबर तक प्रवास रहेगा। इस दौरान वह कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे।



ट्रॉम्सो नॉर्वे के उत्तरी भाग में स्थित प्रमुख शहर है और इसे अक्सर आर्कटिक की राजधानी कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त के काफी उत्तर में स्थित यह शहर प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले वातावरण, उत्तरी रोशनी और समृद्ध सांस्कृतिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में यहां लंबे समय तक सूर्य दिखाई नहीं देता, जबकि गर्मियों में कई सप्ताह तक सूर्य अस्त नहीं होता। इस प्राकृतिक घटना को मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है।

ट्रॉम्सो शिक्षा और अनुसंधान का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां ट्रॉम्सो विश्वविद्यालय स्थित है, जो आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े अध्ययन और अनुसंधान के लिए जाना जाता है। पठानियां विश्वविद्यालय का दौरा कर भारतीय समुदाय के विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और वहां की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे।

अध्ययन प्रवास के दौरान वह जलवायु परिवर्तन, समुद्री विज्ञान, पर्यावरण और आर्कटिक समाज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शिक्षाविदों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी लेंगे।

प्रतियोगिता चायल-कोटी महाविद्यालय में अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ

जूडो खेल नहीं, अनुशासन और आत्मसंयम का माध्यम है : अनिरुद्ध सिंह

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, चायल-कोटी। राजकीय महाविद्यालय चायल-कोटी में दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि किया। प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों से पुरुष और महिला वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

इस अवसर पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जूडो केवल एक खेल नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मसंयम का माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के युवा जूडो में रुचि ले रहे हैं। खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए और बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए।



प्रतियोगिता में प्रदेशभर के 31 महाविद्यालयों की टीमें कर रहीं प्रतिभागिता

उन्होंने कहा कि चायल-कोटी क्षेत्र में एक दशक पहले उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार के प्रयासों से यहां भव्य महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। उन्होंने महाविद्यालय प्रबंधन, अभिभावकों और विद्यार्थियों से अधिक से अधिक बच्चों का दाखिला करवाने तथा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने का आह्वान किया।

मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय की लगभग सभी आवश्यक मांगें पूरी कर दी गई हैं। प्रवक्ता और सहायक प्रवक्ता के रिक्त पदों को भी जल्द भरने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने जूडो प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए महाविद्यालय प्रबंधन को 50 हजार रुपये देने की घोषणा की।

महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. दीपशिखा भारद्वाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि संस्थान को अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिलना गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 18 और महिला वर्ग की 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ विभिन्न महाविद्यालयों के खिलाड़ियों से संवाद और अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा।

कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश ठाकुर, बीडीसी सदस्य हेमावती, मंडल कांग्रेस अध्यक्ष कसुम्पटी अशोक ठाकुर, प्रतियोगिता पर्यवेक्षक डॉ. सतीश शर्मा, तकनीकी विशेषज्ञ उत्तम दत्त, डीएस चंदेल, संजय कुमार, नवेश कुमार, पंकज शर्मा, वीरेंद्र धौल्टा, जूडो संघ के सचिव हरिंदर ठाकुर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत कोटी की प्रधान प्रतिभा शर्मा, सतलाई के प्रधान जय सिंह, ब्रांडी-पदेची की प्रधान कांता ठाकुर, पूर्व प्रधान कोटी बलदेव पुरी, पूर्व प्रधान दिनेश झागटा और बीडीओ मशोबरा अंकित कोटिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

उत्तराखंड की पारंपरिक जल विरासत को मिलेगा नया जीवन

पहाड़ों की सदियों पुरानी जलधारा सहेजने की तैयारी, , मूल स्वरूप से छेड़छाड़ किए बिना होगा वैज्ञानिक पुनरुद्धार

भारतेन्दु संवाददाता,देहरादून

उत्तराखंड की पारंपरिक जल विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य में 54 ऐतिहासिक एवं पारंपरिक धारा-नौलों का वैज्ञानिक तरीके से पुनरुद्धार किया जाएगा। इसके लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी की ओर से जलागम प्रबंधन निदेशालय, देहरादून में राज्य स्तरीय तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों और तकनीकी कर्मियों को पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण तथा आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया। इसका उद्देश्य जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ उनकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुकलात्मक पहचान को सुरक्षित रखना है।

कार्यशाला में प्रदेश के सभी 13 जिलों से सामाजिक समन्वयकों और कनिष्ठ अभियंताओं ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने पारंपरिक धारा-नौलों के संरक्षण, बिना सीमेंट के निर्माण तकनीक, जलागम क्षेत्र प्रबंधन, जल पुनर्भरण क्षेत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन और जल स्रोतों के पुनरुद्धार से जुड़ी विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी। अधिकारियों को बताया गया कि पुराने जल स्रोत केवल पानी उपलब्ध कराने के साधन नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं।

स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहकशां नसीम ने कहा कि धारा-नौले प्रदेश की जल परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। इनके संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय लोगों के अनुभव और वैज्ञानिक पद्धतियों के बीच समन्वय जरूरी है।



13 जिलों के कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण।

उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दुर्गेश पंत ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय प्रक्रिया है। इसके लिए जलागम क्षेत्र, जल पुनर्भरण क्षेत्रों और आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करना जरूरी है। उन्होंने चाल-खाल और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं को भी धारा-नौलों के संरक्षण से जोड़ने पर जोर दिया।

कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि पुराने नौलों में पत्थरों की चिनाई और भार वहन करने वाली पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए ऐतिहासिक संरचनाओं के संरक्षण के दौरान उनके मूल स्वरूप को बनाए रखना आवश्यक है। निर्देश दिए गए कि पारंपरिक पत्थर की चिनाई में अनावश्यक सीमेंट आधारित बदलाव नहीं किया जाए, ताकि इन जल स्रोतों की मौलिक वास्तुकला सुरक्षित रह सके।

इसके अलावा सामाजिक समन्वयकों को जल स्रोतों की जियो-टैगिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित मानचित्रण और संबंधित आंकड़ों के संकलन का प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम पंचायतों के सहयोग से जल पुनर्भरण क्षेत्रों में चाल-खाल और समोच्च खाइयों के निर्माण पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। अभियान के माध्यम से पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्धता मजबूत करने और भविष्य के लिए जल विरासत सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा।

नौलों के संरक्षण में पत्थर की पारंपरिक चिनाई पर जोर

स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी की अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहकशां नसीम ने कहा कि धारा-नौले प्रदेश की जल परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। इनके संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल स्रोतों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय लोगों के अनुभव और वैज्ञानिक पद्धतियों के बीच समन्वय जरूरी है। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. दुर्गेश पंत ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय प्रक्रिया है। इसके लिए जलागम क्षेत्र, जल पुनर्भरण क्षेत्रों और आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करना जरूरी है। उन्होंने चाल-खाल और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं को भी धारा-नौलों के संरक्षण से जोड़ने पर जोर दिया। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बताया कि पुराने नौलों में पत्थरों की चिनाई और भार वहन करने वाली पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था।

2027 चुनाव की तैयारी में यूकेडी ने कसी कमर

भारतेन्दु संवाददाता,देहरादून

उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को गति देते हुए चार समितियों का गठन किया है। पार्टी की ओर से विशेषाधिकार समिति, कोर कमेटी, दृष्टि पत्र (घोषणा पत्र) समिति और आंतरिक समन्वय समिति गठित की गई हैं। समितियों में शामिल सदस्यों की विस्तृत घोषणा जल्द की जाएगी। केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उक्रांद उत्तराखंड के मूल सवालों और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। पार्टी जल्द अपना वचन पत्र अथवा दृष्टि पत्र जारी करेगी और इसके लिए प्रदेश की जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं।

◆उत्तराखंड के मूल सवालों को केंद्र में रखेगा उक्रांद : सुरेंद्र कुकरेती

उक्रांद ने बदरीनाथ धाम में डीजे कार्यक्रम की अनुमति को लेकर शासन-प्रशासन से जवाब मांगा है। पार्टी ने धामों से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं पर कार्रवाई और स्थानीय कलाकारों के लंबित भुगतान की स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी की। इसके अलावा यूआईआईडीबी, सिडकुल और यूटीडीबी समेत विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश की भूमि के आवंटन और व्यावसायिक उपयोग में पारदर्शिता की मांग उठाई गई। पार्टी ने स्थानीय हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

440 मेगावाट किशाऊ बांध परियोजना को लेकर भी उक्रांद ने सर्वेक्षण, निर्माण, पर्यावरणीय प्रभाव तथा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और अधिकारों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। पार्टी ने परियोजना पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

पूर्व अध्यक्ष एवं संरक्षक काशी सिंह ऐरी ने बताया कि 11 अक्टूबर से 'स्वाभिमान संकल्प यात्रा' शुरू होगी। यात्रा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर पार्टी की विचारधारा और उत्तराखंड के मूल मुद्दों को जनता के बीच रखेगी। 25 अक्टूबर को हल्द्वानी में 'संकल्प नया उत्तराखंड' मंथन कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें समान विचारधारा वाले संगठनों और सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ प्रदेश के भविष्य तथा जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

बदरीनाथ धाम में संगीत पर रोक नहीं : महाराज

धाम में संगीत धार्मिक परंपरा का हिस्सा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक की बात तथ्यहीन

अनिल थपलियाल

देहरादून। श्री बदरीनाथ धाम परिसर के पास आयोजित एक उत्सव में संगीत का वीडियो प्रसारित होने के बाद सामाजिक माध्यमों पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को लेकर पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से यह अफवाह फैलाई जा रही है कि श्री बदरीनाथ धाम में संगीत, नृत्य अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं, जबकि ऐसा कहना पूरी तरह गलत और तथ्यहीन है। उन्होंने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे बिना सत्यापन के प्रसारित होने वाली सूचनाओं पर विश्वास न करें।

सतपाल महाराज ने कहा कि श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के पावन अवसर पर भारतीय सेना का बैंड भी धार्मिक धुनों और मंगल संगीत की प्रस्तुति करता है। यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में यह कहना कि धाम में संगीत या सांस्कृतिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक है, तथ्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उर्वशी पीठ भी है। यहां संगीत के माध्यम से ईश्वर की आराधना और स्तुति की परंपरा रही है। संगीत आध्यात्मिक और वैदिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े कार्यक्रमों को प्रतिबंधित बताना उचित नहीं है।


बदरीनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर सतपाल महाराज ने दी सफाई।

महाराज ने श्रद्धालुओं से जिम्मेदारी की अपील की

महाराज ने प्रदेशवासियों, श्रद्धालुओं और देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की कि वे सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित किसी भी भ्रामक या अपुष्ट सूचना के आधार पर धारणा न बनाएं। उन्होंने कहा कि अफवाहें धार्मिक स्थलों और देवभूमि की छवि को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सभी को जिम्मेदारी के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए। बदरीनाथ धाम की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए श्रद्धालुओं से सहयोग की अपेक्षा है।

उन्होंने सीमांत गांव माणा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां होने वाले वैवाहिक और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी स्थानीय लोग संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये आयोजन क्षेत्र की सनातन परंपराओं और लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने के साथ स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी जरूरी है।

महाराज ने श्री बदरीनाथ धाम की पौराणिक और धार्मिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां नर और नारायण पर्वत विराजमान हैं तथा पूजा पद्धति परम वैष्णव परंपरा पर आधारित है। उन्होंने कहा कि बदरीनाथ मंदिर के अंदर शंख बजाना वर्जित है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता और पूजा पद्धति से जुड़ी विशेष परंपरा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर के भीतर शंखनाद पर रोक को पूरे धाम में संगीत या सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

धाम की मर्यादा सबकी जिम्मेदारी

सतपाल महाराज ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भी श्री बदरीनाथ धाम में विभिन्न अवसरों पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। इसलिए वर्तमान में किसी वीडियो अथवा कार्यक्रम के आधार पर यह दावा करना कि धाम में संगीत या सांस्कृतिक आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, वास्तविक स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत करना है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सामग्री को लेकर लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसके तथ्य की पुष्टि करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक पहचान के साथ यहां की लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत भी महत्वपूर्ण हैं।

बारिश के बाद मसूरी में ठंड की दस्तक, गर्म कपड़ों में नजर आए लोग


दिनभर हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट, ठंड बढ़ने से स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें।

सुनील सोनकर

मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। दिनभर हुई बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे शहर में ठंड ने दस्तक दे दी। मौसम में आए बदलाव का असर जनजीवन पर भी देखने को मिला। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा, वहीं देश-विदेश से पहुंचे पर्यटकों ने सुहावने मौसम और धुंध से ढकी पहाड़ियों का जमकर आनंद उठाया। बारिश के बाद मसूरी की वादियों में ठंडक बढ़ने से मौसम खुशनुमा हो गया। मालरोड, गांधी चौक, लाइब्रेरी बाजार और पिक्चर पैलेस सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटक गर्म कपड़ों में घूमते नजर आए।

पहाड़ों पर छाई धुंध और ठंडी हवाओं ने पर्यटकों को खासा आकर्षित किया। कई पर्यटक इस बदले मौसम को अपने कैमरों में कैद करते दिखे। स्थानीय निवासी रकम गुनसोला ने बताया कि बारिश के बाद तापमान में अचानक गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। मौसम में आए इस बदलाव से अब लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है।

वहीं, एक अन्य स्थानीय निवासी ख्याम, के अनुसार बारिश से जहां मौसम सुहावना हुआ है, वहीं लगातार बदलते मौसम के कारण दैनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। पर्यटकों के लिए हालांकि यह मौसम किसी सौगात से कम नहीं रहा। मैदानी क्षेत्रों से पहुंचे पर्यटकों ने मसूरी की ठंडी हवाओं, बादलों से घिरी पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया।

पर्यटकों ने उठाया मौसम का लुत्फ

पर्यटकों का कहना था कि बारिश के बाद मसूरी की खूबसूरती और निखर गई है तथा यहां का मौसम उन्हें खासा आकर्षित कर रहा है।बारिश के बाद पहाड़ों में बढ़ी ठंड ने जहां पर्यटकों को सुहाने मौसम का अनुभव कराया, वहीं स्थानीय लोगों को बदलते मौसम के साथ अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करना पड़ा। मौसम के इस मिजाज ने संकेत दे दिया है कि मसूरी में अब धीरे-धीरे सर्दियों की आहट महसूस होने लगी है।

पूर्व मंत्री दिनेश धनाई ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं



भारतेन्दु संवाददाता, नई टिहरी। भारी वर्षा के बावजूद पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता दिनेश सिंह धनाई ने टिहरी विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड चंबा की ग्राम पंचायत नकोट, बसाल, स्वाड़ी बमुण्ड और पुरसोल का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और क्षेत्र के विकास को लेकर संवाद किया। स्वाड़ी, बसाल और पुरसोल गांव के ग्रामीणों ने गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग प्रमुखता से रखी। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क सुविधा के अभाव में उन्हें आवागमन सहित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्व मंत्री दिनेश सिंह धनाई ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन को 26 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कई गांव अभी तक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को जिम्मेदार बताया। धनाई ने कहा कि उनके कार्यकाल में चार दर्जन से अधिक सड़कों को स्वीकृति दिलाई गई थी, जिसका श्रेय बाद में आने वाले विधायक भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करीब 21 वर्ष तक अन्य जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल रहा, लेकिन क्षेत्र में विकास की गति अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही।

धनाई ने टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पांच जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रस्ताव मांगे थे, जिसमें टिहरी जिले का नाम भी शामिल था। उनका आरोप है कि टिहरी से प्रस्ताव भेजने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं किए गए, जबकि अन्य चार जिलों में वर्ष 2024 में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होकर कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में संगीत महाविद्यालय नई टिहरी, रोडवेज डिपो बौराड़ी, कोटी कॉलोनी-नई टिहरी रोपवे और क्रिकेट अकादमी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। आरोप लगाया कि बाद में इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में स्थापित संस्थानों में भी नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू नहीं हो पाए हैं। धनाई ने कहा कि जनता ने उन्हें फिर अवसर दिया तो क्षेत्र के लंबित विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।

टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धनाई मुखर

वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस का हल्लाबोल

भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को पौड़ी में प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन को लेकर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को इन मामलों में स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के साथ ही उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों और मतदाता सूचियों में हुए बदलावों की स्वतंत्र एवं व्यापक समीक्षा कराने की मांग की।



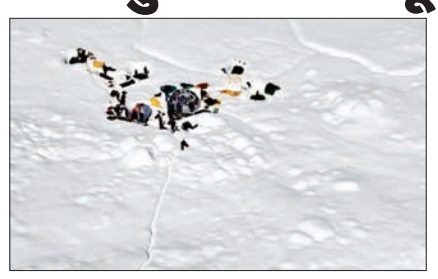
कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन

प्रदर्शन में राजपाल बिष्ट, लता रावत, मोहित सिंह, तामेश्वर आर्य, अजय पटवाल, गजपाल गुसाई, कुलदीप रावत, दिनेश कोहली, यशोदा नेगी, संजय रावत और भरत रावत समेत पौड़ी, श्रीनगर व चौबट्टाखाल के बूथ लेवल एजेंट शामिल रहे।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि लोकतंत्र की बुनियाद निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया पर टिकी है। यदि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के बदलाव को लेकर सवाल उठते हैं तो निर्वाचन आयोग को तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाती रहेगी।

प्रदर्शनकारियों ने निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज और निर्णय सार्वजनिक करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे।

भारी बर्फबारी में फंसे 38 ट्रेकर्स का हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू



भारतेन्दु संवाददाता, उत्तरकाशी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के कारण ऑडेन कोल, कालिंदी पर्वत श्रेणी और आसपास के क्षेत्रों में फंसे ट्रेकर्स को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन का रेस्क्यू अभियान जारी है। अभियान के तहत सोमवार को ऑडेन कोल क्षेत्र से 29 और कालिंदी के पास से नौ ट्रेकर्स को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित हर्षिल पहुंचाया गया। यहां सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें उनकी स्थिति सामान्य पाई गई। इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया।

पिछले 48 घंटे से अधिक समय से लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण कई ट्रेकर्स विभिन्न बेस कैंपों में फंस गए थे। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने हर्षिल हेलीपैड पहुंचकर रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। उन्होंने सेना, वायुसेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमों से ट्रेकर्स की स्थिति और बचाव कार्य की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने रेस्क्यू होकर पहुंचने वाले ट्रेकर्स को तत्काल चिकित्सा सुविधा, गर्म कपड़े, भोजन और पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अन्य फंसे ट्रेकर्स को निकालने का अभियान जारी है।

प्रदर्शन मतदाता अधिकारों की रक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कांग्रेस ने मांग की

मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में किया जोरदार प्रदर्शन

भारतेन्दु संवाददाता,देहरादून

महानगर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी, देहरादून के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रतीकात्मक अर्थी निकालने के साथ केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से प्रतीकात्मक अर्थी और पुतला दहन रोकने के प्रयास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। डॉ. गोगी ने कहा कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक संगठन का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद है।


प्रदर्शनकारी।

ज्ञापन में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और आपत्तियों के निस्तारण से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा कि किसी पात्र मतदाता का नाम उचित सत्यापन और सुनवाई का अवसर दिए बिना सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। साथ ही एसआईआर के दौरान प्राप्त फॉर्म-7 आवेदनों का विधानसभा और बूथवार विवरण सार्वजनिक करने तथा असामान्य संख्या में आवेदन करने वालों की विशेष जांच की मांग उठाई गई। कांग्रेस ने निर्वाचन संबंधी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और महत्वपूर्ण आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग भी की।

पारदर्शिता की मांग

डॉ. गोगी ने कहा कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक और राजनीतिक संगठन का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता लोकतंत्र की बुनियाद है। ज्ञापन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित दोनों निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने, उनके पूर्व निर्णयों की समीक्षा और नए आयुक्तों की नियुक्ति की मांग रखी गई। डॉ. गोगी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है।

न्यूज ब्रीफ

जालंधर पुलिस ने अवैध हथियारों पर सख्ती के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर। जालंधर के पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने शहरवासियों से अवैध हथियारों से दूर रहने और किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी जागरूकता संदेश में कहा गया कि अवैध हथियार रखना, साथ लेकर चलना, इस्तेमाल करना, बनाना या उनका कारोबार करना गंभीर अपराध है। पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों से अपील की कि किसी विवाद या आपराधिक स्थिति में स्वयं कार्रवाई करने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। संदिग्ध गतिविधियों या अवैध हथियारों की जानकारी मिलने पर नागरिक पुलिस को सूचित कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं और अभिभावकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि हथियारों का प्रदर्शन या अवैध इस्तेमाल समाज में हिंसा और अपराध को बढ़ावा दे सकता है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना नागरिक हेल्पलाइन नंबर 112 पर दे सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अवैध हथियारों को न कहने और जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया।

बाबा बागेश्वर ने पंजाब में नशे पर जताई चिंता

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने पंजाब में बढ़ते नशे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवाओं का नशे की ओर बढ़ना गंभीर चिंता का विषय है और समाज के सभी वर्गों को मिलकर इस समस्या के खिलाफ काम करने की जरूरत है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी ताकतें युवाओं को बहकाने का प्रयास कर रही हैं और इसके कारण उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने धार्मिक परिवर्तन को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि पंजाब में नशे तथा धार्मिक परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने पंजाब सरकार और सामाजिक संस्थाओं की ओर से नशे के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए परिवार, समाज और संस्थाओं को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने लोगों से पंजाब की युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता अभियान मजबूत करने का आह्वान किया।

अमेरिकन बुली कुत्ते ने जिम जा रहे छात्र को काटा

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। डाबा इलाके के गुरु नानक नगर में खुले घूम रहे अमेरिकन बुली नस्ल के कुत्ते ने जिम जा रहे बीसीए छात्र अर्पित अग्रवाल पर हमला कर दिया। घटना 26 सितंबर की शाम की है। कुत्ते ने छात्र की टांग और जांघ पर काटकर उसे सड़क पर गिरा दिया। छात्र के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और डंडे से कुत्ते को हटाकर उसकी जान बचाई। अर्पित के अनुसार, कुत्ते को बिना पट्टे के सड़क पर खुला छोड़ा गया था। हमले के दौरान कुत्ता दोबारा उस पर झपटने का प्रयास कर रहा था। आसपास के लोगों ने किसी तरह उसे काबू किया। घायल छात्र को परिजन अस्पताल ले गए, जहां उसके घावों पर टांके लगाए गए और एंटी-रेबीज इंजेक्शन दिया गया। अर्पित ने आरोप लगाया कि इसी कुत्ते ने पहले उसके मामा को भी काटकर घायल किया था। शिकायत के आधार पर थाना डाबा पुलिस ने कुत्ते के मालिक दो भाइयों अमन और रमन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

अमृतसर निगम ने एक दिन में वसूला 70 लाख प्रॉपर्टी टैक्स

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर । प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। रविवार को छुट्टी के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 70.17 लाख रुपये की वसूली की। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक नगर निगम के खजाने में कुल 24.10 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो चुका है। नगर निगम कमिश्नर विक्रमजीत सिंह शेरगिल की निगरानी में विभागीय टीमें रोजाना क्षेत्र में जाकर प्रॉपर्टी मालिकों से बकाया टैक्स जमा करवाने की अपील कर रही हैं। पिछले वर्ष सितंबर तक 35.70 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी। इस वर्ष यह आंकड़ा कम है। अधिकारियों के अनुसार पिछले वर्ष एकमुश्त समाधान योजना के कारण पुराने बकाया टैक्स की भी बड़ी राशि जमा हुई थी। इस वर्ष ऐसी योजना नहीं होने के बावजूद वसूली अभियान जारी है। नगर निगम ने चालू वित्त वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स 30 सितंबर तक जमा करने पर 10 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। लोग निगम के सुविधा केंद्रों के अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी टैक्स जमा कर सकते हैं। महीने के अंतिम दिनों में वसूली बढ़ने की उम्मीद है।

एलपीयू मामले में सीएम मान सख्त दोषियों पर कार्रवाई के दिए कड़े निर्देश

वायरल संदेश के बाद छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर शुरू की जांच

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपों से जुड़ा संदेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद छात्रों के प्रदर्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक गौरव यादव को स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने और पूरे मामले की जानकारी लेने को कहा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने एलपीयू परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर निगरानी बढ़ा दी है। पुलिस महानिदेशक को मौके पर पहुंचकर छात्रों से बातचीत करने, घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति समझने और पुलिस की कार्रवाई की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि



जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाए।

इंटरनेट मीडिया पर संदेश के बाद प्रदर्शन : एलपीयू में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपों से संबंधित एक संदेश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन के लिए बाहर आ गए। छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। इसके कारण जालंधर और लुधियाना के बीच यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। एलपीयू से रामा मंडी होते हुए पीएपी तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। स्थिति को नियंत्रित करने और यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर यातायात मार्ग परिवर्तित किए।

रामा मंडी की ओर आने वाले वाहनों को होशियारपुर मार्ग की तरफ भेजा गया, जबकि जालंधर से छावनी की ओर जाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से छावनी और नकोदर मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर भेजने की व्यवस्था की गई।

यूनिवर्सिटी ने दावों को बताया मनगढ़ंत

एलपीयू की रजिस्ट्रार डा. मोनिका गुलाटी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे संदेशों और दावों को झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तथा विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों से अपील की है कि वे अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें। प्रशासन ने कहा कि किसी भी घटनाक्रम से संबंधित जानकारी के लिए केवल विश्वविद्यालय के आधिकारिक माध्यमों से जारी सूचना पर भरोसा किया जाए।

अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस कांस्टेबल पर टिप्पर चढ़ाने का प्रयास

दो आरोपित गिरफ्तार, पोकलेन जब्त

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट

अशोक ठाकुर। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद रावी दरिया में अवैध खनन का सिलसिला जारी है। रविवार देर रात अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम पर टिप्पर चढ़ाने का प्रयास किया गया। सीनियर कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने समय रहते एक तरफ कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मौके से अवैध खनन में इस्तेमाल पोकलेन मशीन, टिप्पर और एक कार को कब्जे में लेकर दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, थाना सुजानपुर और स्पेशल ब्रांच पठानकोट की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि माधोपुर में रावी दरिया के किनारे श्री बालाजी स्टोन क्रशर के सामने पोकलेन मशीन और टिप्पर से बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने रविवार रात करीब पौने दो बजे मौके पर दबिश दी। वहां अंधेरे में पोकलेन मशीन और टिप्पर से खनन किया जा रहा था। पास में काले रंग की स्कॉर्पियो कार भी खड़ी थी।

पुलिस टीम को देखते ही पोकलेन मशीन का ऑपरेटर मशीन छोड़कर मौके से फरार हो गया। इसी दौरान टिप्पर चालक ने वाहन स्टार्ट कर पुलिसकर्मियों की ओर बढ़ाते हुए उन्हें कुचलने का प्रयास किया। सीनियर कांस्टेबल प्रदीप कुमार ने तेजी दिखाते हुए एक तरफ छलांग लगाकर खुद को बचाया। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर टिप्पर को रोक लिया।

पुलिस ने मौके पर मौजूद स्कॉर्पियो से एक युवक को पकड़ा। उसकी पहचान अमन निवासी पठानकोट के रूप में हुई। वहीं, टिप्पर चालक की पहचान लोकी मसीह निवासी तिब्बड़, जिला गुरदासपुर के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

थाना सुजानपुर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ अवैध खनन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस टीम पर टिप्पर चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास को लेकर भी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने पोकलेन मशीन, टिप्पर और कार को कब्जे में ले लिया है। फरार पोकलेन ऑपरेटर की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले में अवैध खनन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

बाजवा डेवलपर्स सीएमडी जरनैल की जमानत याचिका खारिज

ईडी ने 662 करोड़ की अपराध आय बताई, खरीदारों के धन के दुरुपयोग का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी और बाजवा डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह बाजवा को मनी लांड्रिंग मामले में राहत देने से इन्कार करते हुए उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से जुड़े इस मामले में आरोप है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए घर खरीदारों से प्राप्त धनराशि का कथित तौर पर परियोजनाओं के बजाय अन्य उद्देश्यों में इस्तेमाल किया गया और विभिन्न संस्थाओं के बीच धन का हस्तांतरण किया गया।

जस्टिस मनीषा बत्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा स्तर पर ऐसा कोई उचित आधार नहीं है, जिससे यह संतुष्टि हो कि याचिकाकर्ता संबंधित अपराध का दोषी नहीं है। मामला मोहाली और आसपास बाजवा डेवलपर्स की विभिन्न परियोजनाओं, विशेष रूप से सनी एन्क्लेव, से जुड़ा है।

अदालत के आदेश के अनुसार वर्ष 2017 से



बाजवा डेवलपर्स के खिलाफ खरीदारों की शिकायतें सामने आने लगी थीं। इन शिकायतों के आधार पर कई एफआइआर दर्ज की गईं। इनमें बिक्री विलेख का निष्पादन नहीं करने या इसमें देरी, खरीदारों को समय पर कब्जा नहीं देने, प्लाट नंबर बदलने और एक ही संपत्ति को एक से अधिक खरीदारों को बेचने जैसे आरोप शामिल थे। ईडी के अनुसार जांच के दौरान ऐसी 45 एफआइआर सामने आईं। इन्हीं मामलों के आधार पर अपराध से अर्जित धन का पता लगाने के लिए ईसीआइआर दर्ज की गई और वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू हुई।

पीएमएलए की जमानत शर्तों का हवाला

हाई कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत जमानत देने के लिए अदालत को यह संतुष्ट होना जरूरी है कि आरोपित अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की आशंका नहीं है। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में ऐसी संतुष्टि के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। पीठ ने पीएमएलए की धारा 24 के तहत अपराध की आय से संबंधित वैधानिक धारणा का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि कुछ एफआइआर बाद में रद हुई हों या समझौते के आधार पर समाप्त हुई हों, फिर भी कई अनुसूचित अपराधों से संबंधित मामले लंबित हैं। इसलिए इस स्तर पर उन मामलों के आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जरनैल सिंह बाजवा 28 अक्टूबर 2025 से हिरासत में हैं।

सीबीआई कोर्ट पर घोटालों के साथ ट्रैफिक चालानों का भी बढ़ा बोझ



15 साल पुराने 33 मामले लंबित, वकीलों ने अलग व्यवस्था की मांग उठाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई कर रही चंडीगढ़ की सीबीआई विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत पर अब ट्रैफिक चालानों के निपटारे का भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। अदालत में रोजाना ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले पहुंच रहे हैं, जबकि यहां पहले से करोड़ों रुपये के घोटालों और बैंक धोखाधड़ी के कई बड़े मामले लंबित हैं।

सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में करीब 580 करोड़ रुपये के घोटालों से जुड़े मामले चल रहे हैं। इनमें कुछ मुकदमे एक-दो वर्ष पुराने हैं, जबकि कई मामलों की न्यायिक प्रक्रिया करीब 15 वर्ष से जारी है। वर्तमान में अदालत में धोखाधड़ी से जुड़े 33 मामले लंबित बताए जा रहे हैं। ऐसे में गंभीर आर्थिक अपराधों की सुनवाई के साथ ट्रैफिक चालानों के मामलों की जिम्मेदारी मिलने से अदालत के काम का दायरा बढ़ गया है।

वकीलों का कहना है कि ट्रैफिक चालानों के मामलों में भी दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड तैयार करने और अन्य न्यायिक औपचारिकताओं में अदालत के कर्मचारियों का समय लगता है। इससे पहले से लंबित गंभीर मामलों की सुनवाई प्रभावित होने की आशंका है। कुछ वकीलों ने सुझाव दिया है कि ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए अलग व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि सीबीआई से जुड़े पुराने और गंभीर मामलों की सुनवाई प्रभावित न हो।

अमेरिकी राजदूत के सामने अकाली कार्यकर्ताओं ने लहराए खालिस्तानी झंडे



भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर

भारत में अमेरिकी राजदूत सरजियो गोर के सोमवार को श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचने के दौरान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के कार्यकर्ताओं ने खालिस्तान के झंडे लहराए। कार्यकर्ताओं ने अमेरिकी राजदूत को सिख समुदाय से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें ज्ञापन नहीं सौंप सके। घटना के बाद परिसर के बाहर माहौल गरमा गया।

पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इमान सिंह मान ने बताया कि कार्यकर्ता धार्मिक स्वतंत्रता, लंबे समय से जेलों में बंद सिखों की रिहाई और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के लंबित चुनावों सहित कई मुद्दों को अमेरिकी राजदूत के सामने रखना चाहते थे। उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग में गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी कथित हत्या की साजिश के मामले का भी उल्लेख किया।

इमान सिंह मान ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं, इसलिए सैन्य टकराव से पंजाब की सीमा और वहां रहने वाले लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

यूके से लौटे वारिस पंजाब दे नेता चमकौर सिंह गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, तरनतारन



सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के तरनतारन जिला अध्यक्ष चमकौर सिंह को चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। वह हाल ही में यूनाइटेड किंगडम से लौटे थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पहले से तैनात चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

चमकौर सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ कथित झड़प और हाथापाई के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की बात सामने आई है। इसी मामले में पुलिस को उनकी तलाश थी। विदेश से लौटने की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने एयरपोर्ट पर कार्रवाई की।

चमकौर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ नेता और विधायक मनप्रीत सिंह इयाली ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सक्रिय है और उसे मिल रहे समर्थन के कारण नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इयाली ने दावा किया कि चमकौर सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई का उद्देश्य पार्टी की गतिविधियों को प्रभावित करना है।

सब्जी मंडियों में रंगीन लाइटों पर रोक, उल्लंघन पर लाइसेंस होंगे रद

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



चंडीगढ़ की सब्जी मंडियों में फलों और सब्जियों को अधिक ताजा और आकर्षक दिखाने के लिए रंगीन लाइटों का इस्तेमाल करने वाले विक्रेताओं पर नगर निगम सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। नगर निगम की कमेटी ने हरी, पीली, लाल, नीली या अन्य रंगों की लाइटों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव आगामी सदन की बैठक में रखा जाएगा।

नगर निगम कमेटी के सदस्य एवं पार्षद गुरप्रीत गाबी के अनुसार, कई विक्रेता रंगीन रोशनी का इस्तेमाल कर फलों और सब्जियों की वास्तविक स्थिति छिपाने का प्रयास करते हैं। सब्जियों पर हरी और फलों पर पीली या लाल रोशनी डालने से वे अधिक ताजा और साफ दिखाई देते हैं। ग्राहकों को घर पहुंचने के बाद कई बार सामान खराब मिलता है। इसे ग्राहकों को भ्रमित करने वाला तरीका बताते हुए कार्रवाई की तैयारी की गई है।

प्रस्ताव के अनुसार नियम तोड़ने वाले विक्रेताओं के चालान किए जा सकते हैं। यदि किसी विक्रेता के तीन बार चालान होते हैं तो उसका लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर लाइसेंस रद करने का प्रावधान रखा गया है।

पंजाब के छात्र स्कूल लाएंगे घर का ई-कचरा, पुराने उपकरण होंगे नीलाम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



घरों में पड़े पुराने मोबाइल, खराब चार्जर, केबल, कैलकुलेटर और कीबोर्ड अब कबाड़ में बेचने के बजाय स्कूलों में जमा कराए जा सकेंगे। स्वच्छता अभियान 6.0 के तहत सरकारी स्कूलों में दो से 31 अक्टूबर तक ई-कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति से घरों में पड़े अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक सामान को स्कूल में बनाए गए संग्रह केंद्र पर जमा करा सकेंगे।

अभियान के तहत प्रत्येक स्कूल में अलग ई-कचरा संग्रह केंद्र बनाया जाएगा। यहां जमा ई-कचरे को केंद्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से सुरक्षित तरीके से निपटाया जाएगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों को ई-कचरे से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और इसके वैज्ञानिक निपटान की जानकारी देने के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। पोस्टर, निबंध लेखन और ई-कचरा कला प्रदर्शनी जैसी गतिविधियों से विद्यार्थियों को जोड़ा जाएगा।

स्कूल ईको क्लब के समन्वयक अभियान के दौरान विद्यार्थियों की संख्या, कार्यशालाओं और एकत्र ई-कचरे का वजन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं और उत्पादक उत्तरदायित्व संगठनों के साथ स्कूलों की मैपिंग कराएंगे।

बाइक टैक्सी पर रोक के विरोध में बारिश में राइडर्स का प्रदर्शन



भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एप आधारित बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध में बाइक राइडर्स का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को विश्व मोटरसाइकिल दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में राइडर्स ने तेज बारिश के बीच ट्रिब्यून चौक पर प्रदर्शन किया। राइडर्स ने प्रशासन से बाइक टैक्सी सेवाएं दोबारा शुरू करने की मांग की।

एप आधारित बाइक राइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष साहिल ने कहा कि बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगने से बड़ी संख्या में राइडर्स का रोजगार प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कई राइडर्स ने बाइक खरीदने के लिए ऋण लिया है और अब उनकी किस्तें चुकाना मुश्किल हो रहा है। परिवार का खर्च चलाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदर्शन में शामिल राइडर्स ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें दोबारा एप आधारित बाइक टैक्सी सेवा संचालित करने की अनुमति दी जाए। राइडर्स का कहना था कि वे लंबे समय से प्रशासन के समक्ष अपनी समस्या उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। राइडर्स ने विरोध दर्ज कराने के लिए अपनी बाइक की चाबियां लेकर राज्य परिवहन प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने और अधिकारियों को चाबियां सौंपने का कार्यक्रम बनाया था।

सांसद-विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई सात अक्टूबर 2026 तक हुई स्थगित

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी से संबंधित मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। अदालत ने कहा कि मामले से संबंधित कुछ हलफनामे अभी दाखिल किए जाने बाकी हैं। इसके चलते अब मामले को सात अक्टूबर 2026 को दोबारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सांसदों और विधायकों से जुड़े कई मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) और आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई चल रही है। इन मामलों का पूरा विवरण तत्काल राज्य सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से आवश्यक जानकारी जुटाकर अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं।

पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ के समक्ष पंजाब सरकार के वकील ने बताया था कि सांसदों और विधायकों से जुड़े कुछ मामलों में केंद्रीय एजेंसियां अभियोजन चला रही हैं। राज्य सरकार के पास इन मामलों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण अदालत ने संबंधित एजेंसियों से रिकॉर्ड मंगाने के निर्देश दिए।

हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले केंद्रीय एजेंसियों और संबंधित विभागों से मामलों का पूरा विवरण प्राप्त कर रिकॉर्ड पर रखा जाए। यदि राज्य सरकार और केंद्रीय



एजेंसियों के आंकड़ों में कोई अंतर सामने आता है तो संबंधित अधिकारी उसका मिलान कर स्थिति स्पष्ट करेंगे।

हाई कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मौजूदा तथा पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की प्रगति की निगरानी शुरू की है। अदालत का उद्देश्य ऐसे मामलों की स्थिति स्पष्ट करना और उनकी सुनवाई की प्रगति पर नजर रखना है।

सुप्रीम कोर्ट भी सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को मौजूदा और पूर्व सांसदों-विधायकों के लंबित आपराधिक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करने के निर्देश दे चुका है। खासतौर पर उन मामलों पर ध्यान देने को कहा गया है, जिनकी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश से रुकी हुई है।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने रजिस्ट्री की ओर से तैयार सांसदों और विधायकों से जुड़े लंबित मामलों की रंग-कोड वाली सूची का भी अवलोकन किया।

एलपीयू विवाद पर भाजपा ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप

नशा मुक्ति यात्रा से ध्यान भटकाने का आरोप, विपक्ष ने केंद्रीय जांच की मांग उठाई

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब में भाजपा की ओर से चल रही 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' के बीच लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में हुए विवाद को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि यात्रा से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एलपीयू घटनाक्रम को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

भाजपा की चार नशा विरोधी यात्राएं 18 से 21 सितंबर के बीच शुरू हुई थीं और 30 सितंबर को जालंधर में इनके समापन का कार्यक्रम है। समापन समारोह को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे।

भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने एलपीयू विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा को मिल रहे समर्थन के बीच विवाद सामने आने से अभियान से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती



है। बिट्टू ने मामले की केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग भी उठाई।

शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने भी एलपीयू घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए परिसर में बाहरी लोगों की कथित मौजूदगी की जांच की मांग की। उन्होंने पूछा कि यदि बाहरी लोग वहां पहुंचे थे तो उनकी पहचान और भूमिका की जांच क्यों नहीं की गई। विपक्षी नेताओं ने मामले की जांच सीबीआइ या एनआइए से कराने की मांग की है।

भाजपा नेताओं ने 30 सितंबर को जालंधर में होने वाले अमित शाह के कार्यक्रम के संदर्भ में भी एलपीयू विवाद को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं, एलपीयू घटनाक्रम और भाजपा के कार्यक्रम के बीच किसी संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

एलपीयू घटनाक्रम को लेकर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा

जम्मू-कश्मीर में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव विधानसभा में पारित

उमर अब्दुल्ला ने पेश किया प्रस्ताव, मतदान के दौरान भाजपा विधायकों ने छोड़ा सदन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से पेश पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल और जल्द बहाल करने की मांग की गई है। प्रस्ताव पारित होने के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और भाजपा विधायकों ने वॉकआउट किया।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह प्रस्ताव 25 सितंबर को सदन में पेश किया था। उस समय कई सदस्यों की ओर से चर्चा की मांग किए जाने के कारण प्रस्ताव पर मतदान टाल दिया गया था। सोमवार को चर्चा और बहस के बाद इसे मतदान के लिए रखा गया। प्रस्ताव में 26 जून 2000 और छह नवंबर 2024 को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्तावों का भी उल्लेख किया गया है।



प्रस्ताव पारित, सदन में हुआ हंगामा

भाजपा ने प्रस्ताव की भाषा पर जताई आपत्ति : भाजपा विधायकों ने प्रस्ताव में पुराने संवैधानिक प्रावधानों और विशेष दर्जे से जुड़े संदर्भों पर आपत्ति जताई। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली के पक्ष में है, लेकिन प्रस्ताव में इस्तेमाल की गई भाषा पर उसकी आपत्ति है। उन्होंने सदन में इन संदर्भों को लेकर विरोध दर्ज कराया।

बहस के दौरान भाजपा विधायक सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी की। इसके बाद भाजपा सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रस्ताव पारित होने के बाद दिन का निर्धारित कामकाज पूरा होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी।

370 और 35ए को लेकर भी चर्चा : प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने इसमें अनुच्छेद 370 और 35ए से संबंधित संदर्भ जोड़ने के लिए संशोधन पेश किए। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, कुल दस संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें आठ में विशेष दर्जे से जुड़े संदर्भ शामिल करने की मांग की गई थी। हालांकि, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार का मौजूदा प्रस्ताव मुख्य रूप से पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर है।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को पहले मिला राज्य का दर्जा वापस दिए जाने की मांग कर रही है। उन्होंने भाजपा के विरोध का जिक्र करते हुए कहा कि प्रस्ताव में ऐसे विषयों को शामिल करने से बचने की कोशिश की गई, जिनके आधार पर सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है।

हंगामे के बीच चार विधायक बाहर किए गए : प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में हंगामा बढ़ गया। रिपोर्टों के अनुसार, भाजपा और कांग्रेस के चार विधायकों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की ओर से नारेबाजी जारी रही। सदन में प्रस्ताव को लेकर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।

इससे पहले भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर के खिलाफ भी पद से हटाने का नोटिस दिया। भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने सदन में इस नोटिस का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष से कार्यवाही से अलग रहने की मांग की। अध्यक्ष ने कहा कि नियमों के अनुसार ऐसा प्रस्ताव नोटिस दिए जाने के 14 दिन बाद कार्यसूची में शामिल किया जा सकता है।

पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। विधानसभा की अगली कार्यवाही आज होगी।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति जताया दुख

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करनाह इलाके में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि छह अन्य घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं।



हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल कुछ लोगों को बेहतर उपचार के लिए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (जीएमसी) हंदवाड़ा रेफर किया गया है। हादसे के कारण इलाके में शोक का माहौल है।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में लोगों की जान जाने से वह बेहद दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

उपराज्यपाल ने जिला प्रशासन को घायलों को हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से घायलों के उपचार की व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।

इससे पहले अगस्त में जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र में वाहन के गहरी खाई में गिरने से छह लोगों की मौत हुई थी। हादसे में तीन अन्य घायल हुए थे। सूचना मिलने के बाद आपातकालीन सेवाओं की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत-बचाव अभियान चलाया था।

पुंछ के उस हादसे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया था और अधिकारियों को घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। कुपवाड़ा हादसे के बाद एक बार फिर पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को लेकर चिंता सामने आई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

न्यूज ब्रीफ

श्रीनगर में एक अक्टूबर को कश्मीर मैराथन का आयोजन



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से खेल, फिटनेस और एकता का संदेश देने के उद्देश्य से एक बार फिर कश्मीर मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 'कश्मीर मैराथन 2026-रन फॉर यूनिटी' का आयोजन एक अक्टूबर को श्रीनगर स्थित पुलिस गोल्फ कोर्स में किया जाएगा। पुलिस ने आयोजन को लेकर प्रचार वीडियो भी जारी किया है। प्रचार वीडियो में मैराथन के पिछले आयोजन की झलकियां दिखाई गई हैं। पिछले संस्करण में बड़ी संख्या में धावकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया था। डल झील के किनारे हजारों धावकों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बनाया था। मैराथन में व्हीलचेयर पर पहुंचे खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। उनकी भागीदारी ने आयोजन में समावेशिता और खेल भावना का संदेश दिया। पुलिस के अनुसार, मैराथन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आयोजन के माध्यम से एकता, भाईचारे और सामाजिक भागीदारी का संदेश भी दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने फिलहाल पंजीकरण प्रक्रिया और मैराथन की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

राजौरी में टेम्पो हादसा, बच्चे समेत सात लोग घायल

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी । जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके के मनूर गाला में सोमवार को एक टेम्पो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में दो साल के बच्चे समेत सात लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को वाहन से बाहर निकाला और उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज राजौरी पहुंचाया। घायलों की पहचान मोहम्मद अखलाक (18), मोहम्मद शब्बीर (30), अब्दुल गफूर (65), यास्मीन कौसर (25), बिरता देवी (28), दिलजीत सिंह (2) और मोहम्मद हनीफ (57) के रूप में हुई है। अधिकारी के अनुसार हादसा टेम्पो चालक के वाहन पर नियंत्रण खोने के कारण हुआ। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे लेह के लिलियम फूल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। लद्दाख में पुष्प कृषि को व्यावसायिक स्तर पर बढ़ावा देने की दिशा में पहल की जा रही है। लेह में विश्व के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लिलियम फूलों की खेती की जा रही है। परियोजना की खासियत यह है कि फूलों के उत्पादन में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सिंचाई व्यवस्था भी सौर ऊर्जा आधारित है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रविवार को लेह में लिलियम के खेतों का दौरा कर पहली व्यावसायिक खेप को राष्ट्रीय बाजारों में भेजने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजना में स्थानीय महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। महिलाएं फूलों की तुड़ाई, छंटाई और पैकेजिंग से जुड़कर रोजगार और आय अर्जित कर रही हैं।

बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस की पहली चयन सूची जारी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहले दौर की ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद अस्थायी चयन सूची जारी कर दी है। काउंसलिंग के तहत अभ्यर्थियों से 23 से 25 सितंबर तक ऑनलाइन पसंद और विकल्प मांगे गए थे। इसके आधार पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी व निजी संस्थानों में सीटों का आवंटन किया गया है। चयनित अभ्यर्थी बोर्ड के पोर्टल से अपने लॉगिन के माध्यम से अस्थायी आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें 28 से 30 सितंबर शाम चार बजे तक संबंधित कालेज में मूल दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करना होगा।

रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नोटिस से कारोबारी हुए नाराज



सीएलयू नीति लंबित होने से कारोबारियों ने प्रशासन पर उठाए सवाल

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। रिहायशी कालोनियों में चल रहे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जम्मू नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद कारोबारियों में रोष है। कारोबारियों का कहना है कि जम्मू-कश्मीर में रिहायशी क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को लेकर स्पष्ट नीति नहीं है। पांच साल से चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू) नीति का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब निगम की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

रूपनगर, लोअर रूपनगर, छन्नी हिम्मत, सैनिक कालोनी, गांधी नगर और त्रिकुटा नगर समेत कई रिहायशी कालोनियों में व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि आबादी बढ़ने के साथ इन क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार दुकानें और कार्यालय बने, लेकिन इन्हें नियमित करने के लिए सरकार की ओर से स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई।

चैंबर आफ ट्रेडर्स फेडरेशन ने सोमवार को विभिन्न बाजार संगठनों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करने का निर्णय लिया है। नरवाल फल मंडी के व्यापारी नगर निगम आयुक्त से मुलाकात करेंगे। चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू भी प्रशासन के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। कारोबारियों ने संकेत दिया है कि नोटिस वापस नहीं हुए तो आंदोलन किया जा सकता है।

छन्नी हिम्मत के दुकानदार सचिन गुप्ता ने कहा कि रोजगार के सीमित अवसरों के बीच लोग घरों में दुकान या कार्यालय बनाकर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट नीति बनाकर अनुमति देने की मांग की।

शकुंतला चौक पर बदहाल सड़क से हजारों वाहन चालक परेशान

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। शहर के व्यस्त बीसी रोड पर शकुंतला थिएटर के पास सड़क का करीब 10 मीटर हिस्सा लंबे समय से बदहाल है। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, उखड़ी बजरी और नुकीले पत्थर वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग से रोजाना करीब 10 हजार वाहन गुजरते हैं। सड़क की खराब हालत के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है।

बीसी रोड जम्मू शहर के प्रमुख मार्गों में शामिल है और यह सीधे जनरल बस स्टैंड को जोड़ता है। इसी मार्ग से राजकीय मेडिकल कालेज अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल की ओर एंबुलेंस भी गुजरती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से से गुजरते समय एंबुलेंस की गति धीमी हो जाती है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

दोपहिया वाहन चालकों के लिए सड़क पर बिखरी बजरी और गड्ढे विशेष रूप से जोखिम पैदा कर रहे हैं। वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाने पड़ते हैं, जिससे चौराहे के आसपास यातायात की रफ्तार प्रभावित होती है।



स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने लोक निर्माण विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कुछ दूरी की सड़क की मरम्मत होने से रोजाना गुजरने वाले हजारों लोगों को राहत मिल सकती है।

लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सलीम-उल-सबा ने बताया कि बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों पर तारकोल डालने का काम शुरू किया गया है। विभिन्न सड़कों की चरणबद्ध तरीके से मरम्मत कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि शकुंतला थिएटर के पास क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत भी जल्द पूरी की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में कुत्तों का आतंक चार साल में आए 1.6 लाख मामले

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या के बीच इनके काटने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2025 के बीच प्रदेश में कुत्तों के काटने के 1.63 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2022 में 22,110, 2023 में 34,664, 2024 में 51,027 और 2025 में 55,312 मामले सामने आए। इस वर्ष भी अब तक 35 हजार से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं।

चिंता की बात यह है कि बीते तीन वर्षों में रैबीज के कारण जम्मू-कश्मीर में 18 लोगों की मौत हुई है। चिकित्सकों के अनुसार, समय पर उपचार न करवाना और झाड़-फूंक पर भरोसा करना इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। जम्मू जिले में सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। अकेले जीएमसी जम्मू में हर वर्ष चार से पांच हजार लोग पशुओं के काटने के बाद उपचार के लिए पहुंचते हैं।

चिकित्सकों ने लोगों से कुत्ते के काटने या खरोंच लगने पर तुरंत अस्पताल जाने की अपील की है। विशेषज्ञों के अनुसार, घाव को तत्काल साबुन और बहते पानी से करीब 10 मिनट तक धोना चाहिए और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार एंटी-रैबीज टीका लगवाना चाहिए। घर में पाले गए कुत्ते के काटने पर भी उपचार जरूरी है।

जम्मू-कश्मीर में आवारा कुत्तों की संख्या भी बड़ी चिंता बनी हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र में करीब 64,416 और जम्मू नगर निगम क्षेत्र में करीब 52 हजार आवारा कुत्ते होने का अनुमान है।

स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को हटाने के लिए भाजपा ने दिया नोटिस



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को उस समय राजनीतिक हलचल बढ़ गई, जब भाजपा नेता आरएस पठानिया ने सदन की कार्यवाही के दौरान विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को पद से हटाने के लिए दिए गए नोटिस की जानकारी दी। पठानिया ने स्पीकर के समक्ष पार्टी की ओर से दिए गए इस नोटिस का उल्लेख किया।

जानकारी के अनुसार, भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष के पद पर अब्दुल रहीम राथर के बने रहने को लेकर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी की ओर से दिया गया नोटिस अब विधानसभा की निर्धारित नियमावली और प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। नोटिस पर अंतिम निर्णय से पहले सदन में इससे संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

यह घटनाक्रम विधानसभा की कार्यवाही के संचालन को लेकर भाजपा और सत्ता पक्ष के बीच जारी राजनीतिक मतभेदों के बीच सामने आया है। भाजपा की ओर से स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है।

आरएस पठानिया ने सदन में पार्टी का पक्ष रखते हुए स्पीकर को नोटिस की जानकारी दी। हालांकि, नोटिस में लगाए गए आधारों और आगे की प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अब विधानसभा सचिवालय की ओर से नियमों के अनुसार नोटिस पर आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

अब्दुल रहीम राथर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष हैं और सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। स्पीकर को पद से हटाने संबंधी किसी भी प्रस्ताव पर विधानसभा के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भाजपा के नोटिस के बाद इस मामले में आगे होने वाली कार्यवाही पर सभी की नजर है।

कारोबार सुगमता और वस्तु एवं सेवा कर कानून में संशोधन का भी प्रस्ताव

उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में वेतन संशोधन समेत पांच किए विधेयक पेश

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को विधानसभा में पांच विधेयक पेश किए। इनमें मंत्रियों और विधायकों के वेतन व भत्तों में संशोधन से जुड़े तीन विधेयक शामिल हैं। इसके अलावा कारोबार में सुगमता और जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन से संबंधित विधेयक भी सदन में पेश किए गए।

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम, 1960 और राज्य विधानमंडल सदस्यों के पेंशन अधिनियम, 1984 में संशोधन से संबंधित अलग-अलग विधेयक भी रखे गए। उमर अब्दुल्ला ने कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से एक अन्य विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य अनुमति आधारित नियंत्रण की जगह नियम आधारित शासन को बढ़ावा देना है।



नए प्रावधानों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर दिया गया जोर

वस्तु एवं सेवा कर कानून में संशोधन

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए भी विधेयक पेश किया। इसके माध्यम से संबंधित कर कानून में आवश्यक बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है। पांचों विधेयकों को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान पेश किया गया। अब इन पर सदन में आगे चर्चा और विधायी प्रक्रिया के तहत विचार किया जाएगा। इनमें जनप्रतिनिधियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधानों के साथ-साथ प्रशासनिक एवं कारोबारी व्यवस्था को सरल बनाने से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं। प्रस्ताव के अनुसार इससे नागरिकों और कारोबारियों को योजनाएं बनाने, निवेश करने और विभिन्न गतिविधियां संचालित करने में अधिक सुविधा मिल सकेगी। सरकार की ओर से विधेयक का उद्देश्य कारोबार और जीवनयापन में सुगमता बढ़ाना बताया गया है।

वायुसेना का कन्याकुमारी-कारगिल साइकिल अभियान उधमपुर रवाना

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू । भारतीय वायुसेना का कन्याकुमारी से कारगिल तक साइकिल अभियान सोमवार को जम्मू पहुंचने के बाद उधमपुर के लिए रवाना हुआ। 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आयोजित यह अभियान भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों का हिस्सा है। अभियान का अंतिम चरण 22 सितंबर को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से शुरू हुआ है और आठ अक्टूबर को कारगिल युद्ध स्मारक पर संपन्न होगा।

अभियान के दल प्रमुख ग्रुप कैप्टन एके सिंह ने बताया कि 18 सदस्यीय टीम जम्मू में तवी पुल के पास महाराजा हरि सिंह चौक से उधमपुर के लिए रवाना हुई। उन्होंने बताया कि कन्याकुमारी से कारगिल तक का यह अभियान तीन चरणों में आयोजित किया गया है। इसके पहले दो चरण पूरे हो चुके हैं और वर्तमान में अंतिम चरण जारी है।

उन्होंने कहा कि दल ने 22 सितंबर को नई दिल्ली से यात्रा शुरू की थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आठ अक्टूबर को कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर कारगिल



◆ कारगिल युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि देने आठ अक्टूबर को पहुंचेगा दल

युद्ध के वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यह दिन भारतीय वायुसेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ का अवसर भी होगा।

ग्रुप कैप्टन सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य युवाओं से संवाद स्थापित करना और उन्हें भारतीय वायुसेना के कार्यों तथा उसकी भूमिका के बारे में जानकारी देना है। इसके माध्यम से युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

विधानसभा 2019 की घटनाओं की निंदा करे: वहीद पारा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद पारा ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सरकार से प्रस्ताव में अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली का स्पष्ट उल्लेख करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विधानसभा को पांच अगस्त 2019 को हुए घटनाक्रम की भी निंदा करनी चाहिए। विधानसभा में बहस के दौरान पारा ने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक दलों के बावजूद जम्मू-कश्मीर के लोगों से जुड़े कुछ साझा मुद्दे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली को भी इन्हीं मुद्दों में शामिल बताया। पारा ने विधानसभा में बार-बार प्रस्ताव लाए जाने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर कितने प्रस्तावों के बाद समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा के प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छाओं को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम अपना रुख स्पष्ट रूप से दर्ज करना चाहिए, भले ही वह तत्काल संवैधानिक प्रावधानों को बहाल करने की स्थिति में न हो। उनके अनुसार, विधानसभा तथ्यों को दर्ज कर सकती है और पांच अगस्त 2019 को हुए घटनाक्रम पर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती है।

लोन ने 2019 के बजाय ऐतिहासिक वादों को बताया प्राथमिक संदर्भ

जम्मू-कश्मीर चर्चा का आधार 1947 होना चाहिए: सज्जाद लोन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद लोन ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कहा कि प्रदेश के राजनीतिक दर्जे और भारत के साथ संबंधों पर चर्चा का आधार वर्ष 1947 में किए गए वादे होने चाहिए, न कि 2019 की घटनाएं। उनके बयान की समकालीन रिपोर्टिंग भी यही बताती है।

लोन ने कहा कि प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनका पूरा सम्मान है, लेकिन जम्मू-कश्मीर का भारत के साथ संबंध 1947 में यहां के लोगों से किए गए वादों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा को चर्चा के दौरान अपने ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं बदलना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि मूल व्यवस्था में जम्मू-कश्मीर के लोगों की शासन में सार्थक भागीदारी, स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्तियों की परिकल्पना की गई थी। लोन ने जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किए जाने के संवैधानिक और कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से जुड़े सभी सवालों का उत्तर अभी नहीं



मिला है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां और सरकारें समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं बदला जाना चाहिए।

लोन ने दोहराया कि विधानसभा में जम्मू-कश्मीर से जुड़े विषयों पर चर्चा का संदर्भ बिंदु 1947 होना चाहिए। उनका बयान ऐसे समय आया है जब विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकारें और राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन 1947 में किए गए वादों को जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक विमर्श का ऐतिहासिक आधार बनाए रखना चाहिए।

सिधरा में मवेशी तस्करी नाकाम ट्रक से 35 मवेशी सुरक्षित बचाए

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। मवेशियों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जम्मू ग्रामीण पुलिस ने सोमवार रात सिधरा ब्रिज पर कार्रवाई करते हुए 35 मवेशियों को बचाया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे एक ट्रक को भी जब्त कर लिया। हालांकि, ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई ऑपरेशन कामधेनु के तहत की गई। नगरोटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिधरा ब्रिज नाके पर पुलिस टीम रात के समय वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान पंजतीर्थी की तरफ से आ रहे ट्रक को पुलिस ने जांच के लिए रोका। ट्रक का पंजीकरण नंबर जेके-05जे-7521 बताया गया है।

वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 35 मवेशी पाए गए। पुलिस के अनुसार, मवेशियों को निर्धारित कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए

◆ फरार चालक की तलाश जारी, नगरोटा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू

ले जाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सभी मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला और ट्रक को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान ट्रक चालक मौके से भाग निकला।

पुलिस ने इस मामले में नगरोटा थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी संख्या 229/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब फरार चालक की पहचान और उसके ठिकाने का पता लगाने में जुटी है।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और तस्करी में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि मवेशियों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

श्रीकृष्ण के वरदान से हिडिंबा को मिला देवी स्वरूप, आज भी श्रद्धा से होती है पूजा





तुलसी राम डोगरा
स्वतंत्र लेखक, पालमपुर

पश्चिमी हिमालय की गोद में अवस्थित हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला का मनाली देश-विदेश में पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से प्रचलित है। मनाली अपनी अनुपम और अद्भुत सुंदर छटा से हमेशा शोभायमान रहता है। यहां की सुरम्य चांदी सरीखी पर्वतमालाएं वर्षभर सैलानियों को जहां आत्म-विभोर करती हैं, वहीं कुल्लू जिला पर्यटन, धर्म और संस्कृति के समावेश से अलंकृत है। राज्य में अनेकों ऐतिहासिक व पुरातन मंदिर हैं जो अपने पौराणिक गरिमामयी सभ्यता एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखे हुए है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली को कुदरत ने असीम व वैभव सौंदर्य का थाल परोसा हुआ है,जहां पर्यटकों का वर्षभर तांता लगा रहता है। मनाली से कुछ ही दूरी पर अवस्थित मां हिडिंबा मंदिर, जिसके इर्द-गिर्द की सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना शायद कठिन होगा। श्रद्धालु मंदिर के भित्ति स्थापित हिडिंबा माता की अलौकिक मूर्ति को देखकर अचंभित हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है,जैसे देवी के उन्हें साक्षात व दिव्य दर्शन हों रहे हैं।

इस समस्त धार्मिक स्थल के नयनाभिराम दृश्य मन को अनंत श्रद्धाभाव से आनंदित कर देते हैं। आराधकों को अपनी चमत्कारिक शक्तियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाली मां हिडिंबा जन-जन की श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतिबिंब है। हिडिंबा एक दानव हिडिंब की बहन थी। महाभारत महाकाव्य के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में थे तो ये सभी अपनी मां कुंती के साथ ढूंगरी के जंगल से गुजर रहे थे। जब थककर सोने लगे तो भीम उस समय पहरे पर थे। उस दौरान इस क्षेत्र का अधिकांश राज्य हिडिंब और हिडिंबा नामक दो राक्षस भाई-बहन के वर्चस्व में था। जंगल में मानव गंध पाकर हिडिंबा पांडवों तक आ पहुंची।

महाबली भीम के पुरुषार्थ को देखते हुए हिडिंबा ने राक्षसी स्वरूप त्याग कर मानवी रूप धारण कर उससे विवाह याचना की। भीम ने उसे आसुरीवृत्ति छोड़ने को कहा और उसके हां कहने पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन हिडिंबा का भाई हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा को अपने यहां न पाकर उसे ढूंढता हुआ वहां आ पहुंचा। वहां की स्थिति को भांपते हुए अत्यंत क्रोधित हो गया तथा क्रोध के आवेश में आकर उसने अपने भयंकर राक्षस रूप में आकर भीम को युद्ध के लिए ललकारा। भीम और हिडिंब में जमकर भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में हिडिंब बुरी तरह से भीम से परास्त हुआ और अंत में हिडिंब मारा गया। तत्पश्चात हिडिंबा भीम की अर्धांगिनी बनी।

बाद में श्रीकृष्ण ने उसे हिडिंबा को आसुरीवृत्ति छोड़ने के लिए प्रेरित किया और उसे कल्याणकारी कार्यों में संलग्न होने का वरदान दिया और कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो आने वाले समय समय उसे भविष्य में एक देवी के रूप में पूजा जाएगा। हिडिंबा ने श्रीकृष्ण के वरदान को शिरोधार्य करने के उपरांत देवी हिडिंबा एक ऐसी प्रभावपूर्ण देवी बनी जो राक्षस कल की होते हुए भी अपने मानवीय एवं दैविक गुणों से हिडिंबा एक देवी स्वरूप प्राप्त कर सकीं जो आज भी सम्मानित तथा पूजित है। हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ, जिससे वीर घटोत्कच का जन्म हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनाली के ढूंगरी वन क्षेत्र में स्थित हिडिंबा देवी मंदिर समुद्र तल से लगभग 2150 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के वृक्षों के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र है।

यह मंदिर काष्ठकुणी और पैगोडा शैली में निर्मित है, जिसका निर्माण 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में देवी के चरणचिह्न और कांस्य प्रतिमा विराजमान है। स्थानीय मान्यता है कि यह स्थान कुल्लू घाटी के देवताओं की सभा स्थल जैसा है। ज्येष्ठ संक्रांति पर यहां विशाल मेला लगता है, जबकि कुल्लू दशहरा की शुरुआत भी माता हिडिंबा के आगमन से होती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

माहवारी के दिनों में पाबंदियां नहीं, महिलाओं के स्वास्थ्य और मानसिक शांति का रखा जाए पूरा ध्यान





डॉ. दमन आहूजा
सामुदायिक विकास विशेषज्ञ

अलग थाली, अलग बिस्तर, अलग सबसे बिठाया है मां ने आज उसको, सबको बीमार बताया है। पूरा दिन उसने अलग कमरे में बिताया है। मंदिर में भी जाना उसका कुछ दिन निषेध करवाया है। सुनो सुनो सुनो आज फिर महीना आया है।

एक विचार एक धुरी होता है जिसके इर्द-गिर्द पूरी एक सोच बन जाती है। उपरोक्त विचार नौ हजार किशोरी एवं महिलाओं में महावारी के संदर्भ में जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी देने हेतु एक कार्यक्रम में सुना। इस प्रोजेक्ट में हिमाचल की कई सुदूर पंचायतों में जा कर इनसे प्रचलित भ्रांतियों को दूर कर एक ऐसा माहौल तैयार करना था जिसमें चुप्पी टूट जाए और विषय पर खुल कर बात की जाए।

एक तरफ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं, हमारी क्रिकेट टीम की बेटियां विश्व कप भी ले आई हैं, दूसरी तरफ हम एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया को भेदभावों से बचाने में प्रयासरत हैं। कैसी विडंबना है कि आज भी 70 से 85 प्रतिशत किशोरियां एवं महिलाएं पीरियड्स के दौरान किसी न किसी भेदभाव की शिकार होती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी आप स्वयं किसी सरकारी अथवा सरकारी वित्तपोषित स्कूल में चक्कर लगाकर देख लीजिए , कितने स्कूलों में सैनिटरी पेड्स उपलब्ध हैं।

कार्यक्रम में मिली सीखों को लर्निंग एवं शेयरिंग कार्यक्रम के तहत बांटा गया। कविताएं, लघु नाटिकाएं, गिद्दा, बोलियों एवं चार्ट बनाने जैसी कलाओं के माध्यम से किशोरियां अभिव्यक्ति की सुंदर प्रस्तुतियां दे रही थीं। सब भूरि भूरि प्रशंसा भी कर रहे थे। पूरा माहौल ऊर्जा से भरपूर था। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, जीवन की लय घर की किशोरियों और महिलाओं के बैगर कितनी सूनी सूनी होगी अगर महावारी के दिनों में उनकी भागीदारी सीमित कर दी जाए।

उनके शारीरिक परिवर्तन के चलते उन्हें कुछ समय आराम देने के नाम पर शुरू हुई प्रथा से ये क्या विद्रूप हासिल कर लिया गया है कि गांवों में उन्हें किचन के भीतर घुसने, मंदिर में या पूजा स्थल में जाने, खाने पीने की चीजों को छूने, घर के बाहर जानवरों वाले बाड़ों में सोने को मजबूर किया जाता है। हां, महावारी वाली किशोरियों एवं महिलाओं पर पशुओं का काम करने पर मनाही नहीं होती। घर पर किसी बच्चे, लड़के अथवा पुरुष के किसी अंग से जब जरा भी खून निकलने की घटना घटती है, तो सब कोई त्वरित प्रतिक्रिया के अंतर्गत उस पर पट्टी बांधने, और उसे आराम देने की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन किशोरियों एवं महिलाओं के प्रजनन अंगों से पांच सात दिन तक खून चलना हम में से बहुतों को अखरता नहीं है। ऐसे समय में तो उनकी सेवा करने, उन्हें उनकी मनपसंद खाना खाने और घर के अन्य लोगों के साथ ज्यादा समरसता की जरूरत होती है। हार्मोनल परिवर्तनों के चलते स्वभाव में थोड़ी तेजी,थोड़ा चिड़चिड़ापन व तबीयत में थोड़ा हल्कापन को संवेदनशीलता से लिए जाने की जरूरत होती है।

यदि सृष्टि के कण-कण में ईश्वर का वास है, तो क्या माहवारी के दिनों में महिलाओं में ईश्वर नहीं रहते, जो उन्हें मंदिर जाने और पूजा करने से रोका जाता है? ऐसे समय में तो उन्हें मानसिक शांति और संबल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तुलसी भी अन्य पौधों की तरह एक औषधीय पौधा है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से महिलाओं के इन दिनों में केवल आराम की जरूरत होती है। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाएं सभी कार्य करती हैं, फिर यह भेदभाव गांवों में ही अधिक क्यों दिखाई देता है? कुल मिलाकर ऐसी मान्यताएं रूढ़िवादी सोच का परिणाम हैं। महिलाओं का मनोबल बढ़ाना और उन्हें सहयोग देना परिवार व समाज की जिम्मेदारी है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर भारत की चिंताओं को स्पष्ट और दृढ़ता के साथ सामने रखा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को सामान्य बनाने या उसके परिणामों से बचने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। उनका संदेश केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह उन वैश्विक व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न उठाता है, जिनमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए अलग-अलग मानदंड दिखाई देते हैं। भारत लंबे समय से यह रुख रखता आया है कि आतंकवाद को किसी राजनीतिक, धार्मिक या रणनीतिक तर्क के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।

आतंकवाद किसी एक घटना या संगठन तक सीमित समस्या नहीं है। इसके पीछे धन, हथियार, प्रशिक्षण, सुरक्षित ठिकाने, प्रचार तंत्र और कई बार राजनीतिक संरक्षण का पूरा ढांचा काम करता है। इसलिए केवल आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं हो सकता। यदि आतंकवाद को सहायता देने वाले वित्तीय और अन्य नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो समस्या दोबारा उभर सकती है। यही कारण है कि भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ साझा और निरंतर कार्रवाई की अपेक्षा करता रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग तभी प्रभावी हो सकता है जब सभी देशों के लिए समान सिद्धांत लागू हों। किसी देश के लिए आतंकवाद को सुरक्षा का माध्यम और दूसरे देश के लिए उसी गतिविधि को गंभीर अपराध मानने वाला रवैया वैश्विक प्रयासों को कमजोर करता है। आतंकवाद के मामलों में राजनीतिक सुविधा के आधार पर रुख बदलने के बजाय उसके वित्तपोषण, प्रशिक्षण और सुरक्षित ठिकानों पर कार्रवाई के लिए साझा व्यवस्था मजबूत करनी होगी।

इसी दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाया और भारत की नीतियों पर सवाल किए। इसके जवाब में जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद के संदर्भ में कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद का लगातार अभ्यास करने वाला देश बताया और कहा कि आतंकवाद को सामान्य बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी। यह घटनाक्रम बताता है कि भारत-पाकिस्तान के बीच कश्मीर और आतंकवाद को लेकर मतभेद संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी बने हुए हैं।

कश्मीर का मुद्दा उठाते समय आतंकवाद से जुड़े प्रश्नों को अलग नहीं किया जा सकता। भारत का लगातार यह कहना रहा है कि सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियां दोनों देशों के संबंधों के लिए बड़ी बाधा हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर को लेकर अपना पुराना रुख दोहराता रहा है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय विमर्श को केवल राजनीतिक दावों और प्रतिदावों तक सीमित रखने के बजाय वहां के लोगों की सुरक्षा, विकास और नागरिक अधिकारों से जुड़े व्यापक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

सिंधु जल संधि भी इस समय भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा संधि को निलंबित किए जाने को लेकर कड़ा रुख व्यक्त किया था। भारत ने अपने कदम को सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में रखा है। पानी जैसे संवेदनशील संसाधन का प्रश्न करोड़ों लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। इसलिए इस विषय पर भावनात्मक या धमकी भरी भाषा के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून, द्विपक्षीय व्यवस्थाओं और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तथ्याधारित संवाद की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान भारत की वैश्विक भूमिका का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा भी रहा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया और एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना में पांच स्थायी सदस्य और दस अस्थायी सदस्य हैं। भारत लंबे समय से इसमें सुधार और अधिक प्रतिनिधिक व्यवस्था की मांग करता रहा है। भारत की स्थायी सदस्यता का प्रश्न केवल किसी एक देश की आकांक्षा नहीं, बल्कि वैश्विक संस्थाओं में बदलती आर्थिक, जनसंख्या और राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रतिनिधित्व से भी जुड़ा है। हालांकि सुरक्षा परिषद के सुधार पर सदस्य देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं और इसका रास्ता अभी भी लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है।

आतंकवाद और वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व, दोनों विषय एक-दूसरे से जुड़े व्यापक प्रश्न की ओर संकेत करते हैं। आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां बदल रही हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की संरचना कई मामलों में पुराने वैश्विक समीकरणों को प्रतिबिंबित करती है। आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, साइबर अपराध, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अधिक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है।

-शिवांश धाकड़

कविता

अस्तित्व विहीन

डॉ. राजीव डोगरा, गांव जनयानकड़ (कांगड़ा)

मिट्टी-मिट्टी चिल्लाता यहां आया,
मानते थे खुद को बड़ा बलशाली, धुरंधर,
सत्ता, शोहरत, धन के पीछे भागे,
समझते रहे खुद को सबसे बेहतर।
फिर भी बचा न सके अपना अस्तित्व,
समेट लिया मिट्टी ने अपने अंदर,
जिसे समझते थे मुट्ठी में दुनिया,
वही रह गया मुट्ठी भर धूल बनकर।
खुद को खुदा जानना आसान था,
दूसरों को सदा गधा समझते थे,
अपने आगे किसी को न मानते,
हर चेहरे में अपना ही रुतबा देखते थे।
पर वक्त ने ऐसा आईना दिखाया,
जिसमें कोई चेहरा अपना न था,
न ताज रहा, न नाम की चमक,
न साथ कोई अपना सपना था।
खुदा ने उनको भी अपना अस्तित्व दिखाया,
जो जीवन भर दूसरों को तुच्छ समझते थे,
मिट्टी से उठे थे, मिट्टी में लौटे,
फिर भी खुद को आसमान समझते थे।
मिट्टी ने कोई भेद नहीं किया,
न राजा देखा, न रंक पहचाना,
जिसने जीवन भर ऊंचाई मांगी,
उसे भी अपना आंचल पड़ा ओढ़ाना।
मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही कर दिया,
अहंकार का हर एक निशान,
जो कल तक खुद को सबसे बड़ा समझता था,
आज वही बन गया प्रकृति की पहचान।

ऑपरेशन क्लीन से सोशल मीडिया को स्वच्छ सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की प्रशासनिक पहल





वसुंधरा धर्माणी
घुमारवीं, बिलासपुर (हि.प्र)

डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह विचारों, संस्कृतियों और जीवनशैली को प्रभावित करने वाला एक शक्तिशाली मंच बन चुका है।

इस मंच पर उभरे 'इन्फ्लुएंसर' आज लाखों करोड़ों लोगों के व्यवहार,सोच और पसंद को दिशा दे रहे हैं, लेकिन जिस तेजी से यह प्रभाव बढ़ा है उसी तेजी से इसके दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। अश्लीलता, अभद्र भाषा, फर्जी प्रचार और नैतिकता से गिरते कंटेंट ने समाज को चिंतित कर दिया है। ऐसे में 'ऑपरेशन क्लीन' एक सराहनीय प्रयास है जो सोशल मीडिया को स्वच्छ , जिम्मेदार और एक सभ्य समाज निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है।

'इन्फ्लुएंसर' वह व्यक्ति होता है, जो अपने कंटेंट के माध्यम से लोगों को प्रभावित करता है। यह प्रभाव फैशन, फिटनेस, शिक्षा, राजनीति, मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहले जहां समाज में हमारे आदर्श-शिक्षक, लेखक, वैज्ञानिक या समाज सेवी होते थे, वहीं आज एक वीडियो या रील बनाने वाला व्यक्ति भी लाखों लोगों का आदर्श बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारे 'इन्फ्लुएंसर' सकारात्मक कार्य कर रहे हैं और वे जागरूकता फैलाते हैं, शिक्षा देते हैं और समाज के अच्छे पहलुओं को उजागर करते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो केवल लोकप्रियता और पैसे के लिए किसी भी स्तर तक गिरने को तैयार है।

हिमाचल में 'ऑपरेशन क्लीन' अभियान प्रशासन और पुलिस का संयुक्त प्रयास है। इस अभियान को आगे बढ़ाने में प्रशासनिक स्तर पर भी पहल हुई है और इसमें खास तौर पर सहायक लोक संपर्क अधिकारी अजय बन्याल की भूमिका भी मुख्य रूप से दिखाई दे रही है। हिमाचल में चल रहे इस 'ऑपरेशन क्लीन' के तहत प्रशासन और पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रहे अश्लील, भड़काऊ और गैर जिम्मेदार कंटेंट पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। यह कार्रवाई किसी एक दो लोगों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर पर की गई है। कई अकाउंट्स को पुलिस द्वारा नोटिस भेजे गए और उन्हें अपना कंटेंट हटाने के निर्देश भी दिए गए। कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करने तक की भी नौबत आई। खासकर तब जब कंटेंट में गाली गलौज, धार्मिक टिप्पणी, या देशहित के विरुद्ध दिया गया बयान हो।

'ऑपरेशन क्लीन' इसी विकृत प्रवृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास है। इसके अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी, आपत्तिजनक सामग्री पर चेतावनी और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इस पहल का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी के दायरे में लाना है। यह एक स्पष्ट संदेश है, कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ सामाजिक मर्यादाओं की अनदेखी नहीं हो सकता।

ऑपरेशन क्लीन हिमाचल एक सामाजिक और प्रशासनिक डिजिटल स्वच्छता अभियान है, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित कर सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाना है। इसमें नागरिकों की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना गया है, जहां लोग गलत या भ्रामक सामग्री की रिपोर्ट कर सक्रिय सहयोग देते हैं और जिम्मेदारी निभाते हैं। साथ ही सकारात्मक, शिक्षाप्रद और सांस्कृतिक सामग्री को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे डिजिटल माध्यमों पर स्वस्थ वातावरण विकसित हो सके।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के साथ मानवीय मूल्यों और संस्कारों को बचाए रखना जरूरी





हेमराज ठाकुर,प्रदेशाध्यक्ष हि.प्र.
राजकीय भाषाई अध्यापक संघ

हर राष्ट्र की आत्मा उसकी शिक्षा व्यवस्था में बसती है। विद्यालय केवल भवन नहीं, बल्कि ऐसे केंद्र हैं जहां भविष्य की पीढ़ियों का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षा से जुड़ा प्रत्येक निर्णय केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व का विषय है। बदलते समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार आवश्यक है, लेकिन हर सुधार का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाना होना चाहिए।

हाल के वर्षों में शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिले हैं। नई नीतियां, नए शिक्षण मॉडल और चयन की नई प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना बताया जाता है। बदलते समय के साथ शिक्षा को नई आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना जरूरी है, लेकिन यह भी विचार करना होगा कि क्या प्रत्येक बदलाव वास्तव में विद्यार्थियों और शिक्षकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते समय उसके मूल उद्देश्य और व्यापक सामाजिक प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है।

आज शिक्षकों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने, विशेष विद्यालयों के लिए अलग चयन प्रक्रियाएं अपनाने और अलग-अलग सेवा शर्तें निर्धारित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि शिक्षक समान शैक्षणिक योग्यता और चयन प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त हुए हैं, तो उनके बीच अत्यधिक अंतर पैदा करने की आवश्यकता क्यों महसूस की जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन केवल शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया या परीक्षा परिणामों से नहीं किया जा सकता। शिक्षक का अनुभव, विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार, कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता और समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के बावजूद कई शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। इसलिए यदि शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल परीक्षाओं, जांच प्रक्रियाओं या औपचारिक चयन मानकों से किया जाएगा तो शिक्षण के मानवीय पक्ष को पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाएगा। शिक्षा केवल सूचना और कौशल प्रदान करने का माध्यम नहीं है। इसका उद्देश्य संवेदनशील, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक तैयार करना भी है।

भारत की शिक्षा परंपरा में शिक्षक को केवल विषय विशेषज्ञ के रूप में नहीं देखा गया। शिक्षक समाज के मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाता रहा है। इसलिए शिक्षा नीति बनाते समय ज्ञान-विज्ञान और नैतिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। विज्ञान, तकनीक और आधुनिक भाषाओं का ज्ञान आज की आवश्यकता है, लेकिन यदि विद्यार्थियों में मानवीय मूल्य, सामाजिक संवेदनशीलता और सांस्कृतिक चेतना कमजोर पड़ने लगे तो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य प्रभावित होगा।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार केवल बड़े शहरों या चुनिंदा विद्यालयों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ग्रामीण, दुर्गम और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी समान अवसर मिलना आवश्यक है। दूरदराज के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सामने कई बार संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं और पर्याप्त शैक्षणिक सामग्री की कमी जैसी चुनौतियां होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में शिक्षक केवल कक्षा में पढ़ाने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करते समय इन वास्तविक परिस्थितियों को समझना जरूरी है।

शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों के लिए केवल सरकार या प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना भी उचित नहीं होगा। शिक्षक समुदाय को भी आत्ममंथन करना होगा। शिक्षक की प्रतिष्ठा उसके ज्ञान के साथ-साथ उसके आचरण, अनुशासन, कार्यनिष्ठा और विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार से बनती है। यदि शिक्षक स्वयं अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगे।

आज आवश्यकता है कि शिक्षक अपने आचरण और कार्यसंस्कृति को और मजबूत करें। समय की पाबंदी, नियमित अध्यापन, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना, कमजोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना और अभिभावकों के साथ संवाद बनाए रखना शिक्षक की जिम्मेदारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षक को बदलती तकनीक और नई शिक्षण पद्धतियों के साथ स्वयं को भी निरंतर विकसित करना होगा।

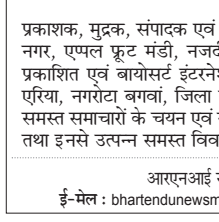
विद्यालयों को ज्ञान, अनुशासन और संस्कार के केंद्र के रूप में विकसित करना भी जरूरी है। विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम पूरा कराने के बजाय उनमें प्रश्न पूछने, विचार करने, सहयोग करने और समाज के प्रति जिम्मेदारी समझने की क्षमता विकसित की जानी चाहिए। खेल, कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य गतिविधियां भी बच्चों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार का अंतिम उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जहां शिक्षक सम्मान के साथ काम कर सके और विद्यार्थी भयमुक्त होकर सीख सके।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

अभिनय में बनाई पहचान

मनसा राधाकृष्णन दक्षिण भारतीय मनोरंजन जगत की उभरती हुई अभिनेत्री हैं। उनका जन्म 29 सितंबर 1998 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था।



मनसा राधाकृष्णन
जन्म : 29 सितंबर 1998

अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने कम समय में दर्शकों के बीच पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मनसा ने विभिन्न परियोजनाओं में काम करते हुए अपने अभिनय कौशल को प्रस्तुत किया है। उनकी अभिनय यात्रा दक्षिण भारतीय सिनेमा और धारावाहिकों से जुड़े दर्शकों के बीच विशेष रुचि का विषय बनी हुई है।

मनसा राधाकृष्णन ने अपने अभिनय करियर में अलग-अलग प्रकार के किरदार निभाने का प्रयास किया है। उनकी फिल्मों और अन्य अभिनय परियोजनाओं में कहानी के अनुरूप पात्रों को सहजता से प्रस्तुत करने की कोशिश दिखाई देती है। अभिनय के क्षेत्र में किसी भी कलाकार के लिए चुनौती केवल संवाद बोलना नहीं, बल्कि किरदार की भावनाओं और परिस्थितियों को समझकर उसे पर्दे पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। मनसा ने भी अपने काम के माध्यम से इसी दिशा में अपनी पहचान विकसित करने का प्रयास किया है।

उनकी चर्चित अभिनय परियोजनाओं में वर्ष 2023 में आई 'सेंगालम' का नाम शामिल है। इस परियोजना ने उन्हें दर्शकों के बीच पहचान दिलाने में भूमिका निभाई। इसके अलावा 'नंदनवनम 120 किलोमीटर' जैसी परियोजना भी उनके अभिनय सफर का हिस्सा रही है। इन कार्यों के माध्यम से उन्हें अलग-अलग प्रकार के पात्रों और कहानी की परिस्थितियों के साथ काम करने का अवसर मिला।

मनसा राधाकृष्णन की अभिनय यात्रा यह भी दर्शाती है कि दक्षिण भारतीय मनोरंजन उद्योग में नई प्रतिभाओं के लिए लगातार अवसर बढ़ रहे हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों और धारावाहिकों को देशभर में मिलने वाली लोकप्रियता के कारण कलाकारों को व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने भी अभिनय की दुनिया को नई संभावनाएं दी हैं। ऐसे में युवा कलाकारों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने के कई मंच उपलब्ध हैं।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

अपस्टार्ट-26 में स्टार्टअप्स को 18 लाख तक पुरस्कार और फंडिंग का मौका

एजेंसी, कानपुर

शुरुआती चरण के स्टार्टअप को निवेश, इनक्यूबेशन और उद्योग जगत से जोड़ने के लिए आईआईटी कानपुर का अपस्टार्ट-26 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संस्थान के एंटरप्रेन्योरशिप सेल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की बिजनेस मॉडल पिचिंग प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्टार्टअप संस्थापकों को अपने विचार और बिजनेस मॉडल निवेशकों तथा उद्योग विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। अपस्टार्ट-26 के तहत बिजनेस मॉडल पिचिंग प्रतियोगिताएं दिल्ली, बेंगलुरू, हैदराबाद और मुंबई में आयोजित की जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में शुरुआती चरण के स्टार्टअप हिस्सा लेकर अपने उत्पाद, सेवाओं और कारोबारी मॉडल को प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित प्रतिभागियों को अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर सहयोग मिलने की संभावना है।

कार्यक्रम में स्टार्टअप्स के लिए 18 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि और फंडिंग का अवसर रखा गया है। इसके अलावा इनक्यूबेशन और मार्गदर्शन के माध्यम से उद्यमियों को अपने कारोबार को विकसित करने में मदद दी जाएगी। उद्योग जगत से जुड़ाव होने से स्टार्टअप्स को संभावित निवेशकों और विशेषज्ञों तक पहुंच बनाने का अवसर भी मिलेगा। आईआईटी कानपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल की ओर से इस पहल का उद्देश्य शुरुआती चरण के उद्यमों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। पिचिंग प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों को अपने बिजनेस मॉडल की व्यवहारिकता, बाजार की संभावनाओं और उत्पाद या सेवा की उपयोगिता को सामने रखने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप्स को निवेश के साथ अपने नेटवर्क का विस्तार करने और उद्योग जगत के अनुभवी लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

न्यूज ब्रीफ

गांवों में सौर ऊर्जा से रोशन होंगे घर, बिजली बिल में भी होगी बचत

एजेंसी, आगरा। आगरा मंडल के गांवों में अब बैटरी बैकअप वाले सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर योजना 2.0 के तहत लगाए जाने वाले इन सिस्टम से ग्रामीण परिवारों को बिजली की बचत के साथ पावर बैकअप भी मिलेगा। बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैटरी के जरिए घरों में रोशनी की सुविधा बनी रहेगी। हाइब्रिड इनवर्टर वाले सोलर सिस्टम से घर की जरूरत के लिए बिजली तैयार की जा सकेगी। इससे बिजली बिल में कमी आने की उम्मीद है। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ लोगों को बिजली के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त बिजली को बेचने की सुविधा भी मिल सकती है।

आगरा में सीईसी ज्ञानेश कुमार के आवास पर कांग्रेस का प्रदर्शन

एजेंसी, आगरा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजय नगर कॉलोनी स्थित पैतृक आवास पर सोमवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव अनिल यादव और मथुरा के जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर के नेतृत्व में करीब 11 बजे प्रदर्शनकारी बैनर लेकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आवास के गेट पर कालिख पोती और वहां आपत्तिजनक नारा लिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान एसआईआर और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपनी आपत्तियां रखीं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर उनकी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही।

कानपुर क्लब की बैठक में चुनाव का मुद्दा गरमाया, कमेटी फिर मंजूर

एजेंसी, कानपुर। कानपुर क्लब, कैंट की वार्षिक आम सभा सोमवार को आयोजित हुई। बैठक महज 15 मिनट में औपचारिकताओं के साथ समाप्त हो गई। इस दौरान सदस्यों ने पिछले आठ साल से क्लब में चुनाव नहीं होने को लेकर रोष जताया। सदस्यों ने वर्तमान कमेटी के सामने चुनाव कराने की मांग रखी। हालांकि, अधिकांश सदस्य वर्तमान कमेटी के पक्ष में खड़े रहे। इसके चलते चेयरमैन आरसी सेठ और सचिव ऋषि कत्याल के नाम को अगले दो साल के लिए सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। बैठक में चुनाव का मुद्दा उठने के बावजूद कमेटी में बदलाव नहीं हुआ। आम सभा के दौरान क्लब की आगामी व्यवस्था को लेकर सदस्यों के बीच चर्चा भी हुई।

कानपुर में बारिश से कच्चे मकान की दीवार गिरी, आठ लोग मलबे में दबे

एजेंसी, कानपुर। सचेंडी के कैधा नयापुरवा गांव में लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार भोर पहर एक कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। हादसे के समय छप्पर के नीचे सो रहे परिवार के आठ लोग मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। लोगों ने मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला। हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें चार की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया। बारिश के कारण कच्ची दीवार कमजोर होने के बाद अचानक गिरने से हादसा हुआ। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित परिवार की मदद की मांग की। मौके पर पहुंची टीम ने घटना की जानकारी जुटाई और घायलों के उपचार की व्यवस्था कराई।

दिव्यांशी यादव की मौत के मामले में छात्रों ने फिर शुरू किया धरना



एजेंसी, लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) की बीएससी नर्सिंग 2025 बैच की छात्रा दिव्यांशी यादव की मौत के मामले में सोमवार सुबह छात्र दोबारा नर्सिंग कालेज परिसर में धरने पर बैठ गए। छात्र डीन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने मामले की जांच के लिए गठित आंतरिक समिति पर भी अविश्वास जताया है। छात्रों की मांग है कि घटना की निष्पक्ष जांच के लिए बाहरी समिति गठित की जाए। उनका कहना है कि मामले की जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। दिव्यांशी के परिजनों ने भी मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की अपील की है। छात्रों के धरने के चलते नर्सिंग कालेज परिसर में गहमागहमी का माहौल रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। प्रशासन की ओर से छात्रों से बातचीत कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

मारपीट और रुपए छीनने की शिकायत पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के मिले निर्देश

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने सुनीं फरियादें

एजेंसी, लखनऊ



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में फरियादियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी शिकायतें रखीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दर्शन में रायबरेली से पहुंचे एक बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री को मारपीट और रुपये छीनने से जुड़ी अपनी परेशानी बताई। शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए और आरोपितों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की जमीन पर कब्जे की शिकायतों में भी अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन पर दबंगों या अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जे की शिकायत सामने आती है तो मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

साथ ही पात्र व्यक्ति को उसकी जमीन से संबंधित समस्या में राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने फरियादियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से मामलों की स्थिति पर भी जानकारी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति, खुशहाली और मजबूत कानून-व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पहचान है। कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों की सुरक्षा और उनके अधिकारों से जुड़े मामलों में गंभीरता बरती जाए। जनता दर्शन में आए लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं।

इनमें जमीन से जुड़े विवाद, पुलिस कार्रवाई और अन्य शिकायतें शामिल रहीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की देरी न हो। फरियादियों को अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसका भी ध्यान रखा जाए।

वेतन न मिलने से आर्थिक संकट, रेलवे अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों का प्रदर्शन



एजेंसी, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज स्थित केंद्रीय चिकित्सालय में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने छह महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में सोमवार को धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुरक्षाकर्मियों का आरोप है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है और कई कर्मचारियों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है।

सुरक्षाकर्मियों ने बताया कि वे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने संबंधित निजी एजेंसी पर वेतन भुगतान में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई महीनों से भुगतान को लेकर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। सुरक्षाकर्मियों ने वेतन के साथ पीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई। उनका कहना है कि इन बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

इससे कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। धरने पर बैठे सुरक्षाकर्मियों ने मांग की कि छह महीने का बकाया वेतन जल्द दिलाया जाए और भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पीएफ और ईएसआईसी की सुविधा भी उपलब्ध कराने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक वे अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और जिम्मेदार अधिकारियों से हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान कराने की अपील की।

76 लाख की चांदी चोरी में एमसीए ग्रेजुएट गिरफ्तार, 24 किलो चांदी बरामद

एजेंसी, कानपुर



पटकापुर के चटाई मोहाल में सर्राफ के घर से करीब 76 लाख रुपये कीमत की 30 किलो चांदी की सिल्लियां और 75 हजार रुपये नकद चोरी करने के मामले में फीलखाना थाना पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपित की पहचान एमसीए ग्रेजुएट सुधांशु अग्रवाल के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 24 किलो से अधिक चांदी बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक, सर्राफ के घर की अलमारी के लाकर से चांदी की सिल्लियां और नकदी चोरी होने की शिकायत मिली थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे 50 से अधिक सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और उसकी पहचान की। इसके बाद पुलिस टीम ने किला तिराहा फलमंडी के पास कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान पुलिस ने चोरी की गई चांदी में से 24 किलो से अधिक चांदी बरामद करने का दावा किया है। बरामद चांदी की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। पुलिस जांच में आरोपित के एमसीए ग्रेजुएट होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब उससे चोरी की वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ कर रही है।

42 किमी रेस वॉक में उतरीं प्रियंका, चार रेड कार्ड के बाद हुईं बाहर

एजेंसी, मेरठ



एशियाई खेलों में पदक की उम्मीद लेकर 42 किलोमीटर मैराथन रेस वॉक में उतरीं मेरठ की ओलंपियन प्रियंका गोस्वामी का सफर रविवार को महज नौ किलोमीटर में समाप्त हो गया। लंबे अंतरराष्ट्रीय अनुभव और दो ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुकीं प्रियंका से इस नए इवेंट में पदक की उम्मीद थी, लेकिन तकनीकी नियमों के उल्लंघन के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

प्रियंका को रेस के दौरान कुल चार रेड कार्ड मिले। इनमें दो रेड कार्ड ग्राउंड से संपर्क टूटने यानी 'लॉस आफ कांटैक्ट' और दो घुटने के मुड़ने यानी 'नी फ्लेक्शन' के कारण दिए गए। चार रेड कार्ड मिलने के बाद उन्हें तकनीकी नियम के तहत प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। इस तरह 42 किलोमीटर की रेस में वह केवल नौ किलोमीटर का ही सफर पूरा कर सकीं।

प्रियंका गोस्वामी लंबे समय से 20 किलोमीटर रेस वॉक में भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। इस बार उन्होंने 42 किलोमीटर मैराथन रेस वॉक के नए इवेंट में चुनौती पेश की। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा को लेकर उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी। प्रतियोगिता में उतरते समय उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर का लंबा अनुभव भी था।

हालांकि रेस के शुरुआती चरण में ही उन्हें तकनीकी नियमों के उल्लंघन को लेकर चेतावनियां मिलने लगीं। अधिकारियों की ओर से दिए गए रेड कार्ड के बाद उनकी स्थिति मुश्किल होती गई। चार रेड कार्ड पूरे होने के बाद नियमों के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। प्रियंका ने रेस में करीब नौ किलोमीटर तक हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। इस तरह पदक की दौड़ में शामिल होने की उनकी उम्मीद शुरुआती चरण में ही खत्म हो गई।

42 किलोमीटर की लंबी स्पर्धा में वह बाकी दूरी पूरी नहीं कर सकीं। रेस वॉक में खिलाड़ियों के लिए तकनीकी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें खिलाड़ी के एक पैर का जमीन से संपर्क बना रहना और घुटने की निर्धारित स्थिति में रहना जरूरी होता है। इन नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों की ओर से रेड कार्ड दिए जाते हैं।

तकनीकी नियमों के कारण प्रतियोगिता से बाहर होने के बाद प्रियंका गोस्वामी का पदक अभियान अधूरा रह गया। प्रतियोगिता में मिले चार रेड कार्ड के बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अब उनका ध्यान आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर रहेगा। 42 किलोमीटर की इस स्पर्धा में उनका अनुभव भले ही अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, लेकिन नए इवेंट में उतरकर उन्होंने एक अलग चुनौती स्वीकार की।

विश्व हृदय दिवस : विशेषज्ञों ने दी स्क्रीन टाइम घटाने और पूरी नींद की सलाह

एजेंसी, मेरठ। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाएगा। इस बार दिवस की थीम 'डोंट मिस ए बीट' यानी दिल की धड़कन से न चूकें रखी गई है। इसके तहत लोगों को हृदय रोग के लक्षणों की पहचान करने और दिल के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जा रहा है। हृदय रोग विशेषज्ञों ने बदलती जीवनशैली के बीच युवाओं में भी बढ़ रहे हृदय संबंधी जोखिम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है।

विशेषज्ञों के अनुसार देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन देखने की आदत नींद के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित कर सकती है। स्क्रीन के अधिक इस्तेमाल से मेलाटोनिन का स्तर प्रभावित होने और जैविक घड़ी में बदलाव की बात कही गई है। इससे नींद पूरी नहीं होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेषज्ञों ने सोने से करीब दो घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है।

हृदय रोग विशेषज्ञों का कहना है कि आजकल 30 से 40 वर्ष की उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसके पीछे तनाव, अनियमित दिनचर्या, कम शारीरिक गतिविधि, खानपान में बदलाव और पर्याप्त नींद नहीं लेना जैसे कारक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को नियमित दिनचर्या अपनाने, पर्याप्त नींद लेने और शारीरिक गतिविधि बढ़ाने की सलाह दी है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर खानपान और लंबे समय तक बैठे रहने जैसी आदतों से बचने की सलाह दी गई है।

अवैध निर्माण की शिकायत करने वाले अधिवक्ता को ही नोटिस, पीडीए में हंगामा

एजेंसी, प्रयागराज। अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत करने वाले अधिवक्ता को ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के जोनल अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता को नोटिस दिए जाने के विरोध में सोमवार को अधिवक्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित इंदिरा भवन के पीडीए कार्यालय में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा किया। अधिवक्ताओं का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की गई थी। उनका कहना है कि शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय संबंधित अधिकारी की ओर से शिकायतकर्ता अधिवक्ता को ही नोटिस जारी कर दिया गया। इससे अधिवक्ताओं में नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में अधिवक्ता पीडीए कार्यालय पहुंचे और मामले में कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में नियमों के विपरीत निर्माण की शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। उनका आरोप है कि शिकायतकर्ता को ही नोटिस जारी किए जाने से शिकायत करने वाले लोगों में भी असंतोष पैदा हो सकता है। पीडीए कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने संबंधित अधिकारी से मामले में स्पष्टीकरण देने और शिकायत पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि अवैध निर्माण से जुड़े मामलों में नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए और शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस के सवालों का भाजपा ने किया पलटवार

महापौर प्रमिला पांडेय ने कांग्रेस से तथ्यों के साथ आपत्ति रखने को कहा

एजेंसी, कानपुर



निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। सोमवार को पत्रकार वार्ता में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडेय ने कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी दल को आपत्ति है तो उसे तथ्यों और उपलब्ध लोकतांत्रिक व न्यायिक मंचों के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए।

प्रमिला पांडेय ने कहा कि राजनीतिक असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार-जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके मुताबिक, निर्वाचन आयोग और अन्य संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के साथ राजनीतिक दलों को अपने संगठन और रणनीति की भी समीक्षा करनी चाहिए। महापौर ने 26 सितंबर को निर्वाचन आयोग की ओर से एसआइआर समेत प्रमुख निर्णयों को सर्वसम्मति से लिए जाने संबंधी स्पष्टीकरण का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि किसी संस्था या चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगाने से पहले संबंधित तथ्यों को सामने रखना जरूरी है। इस दौरान भाजपा नेता स्वप्निल वरुण ने भी चुनावी और प्रशासनिक मामलों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने आंतरिक प्रशासनिक मामलों को राजनीतिक रंग नहीं देने की बात कही। भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित किसी भी आपत्ति को उचित लोकतांत्रिक और न्यायिक मंच पर उठाया जा सकता है।

वादा अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने की भी घोषणा की, सरकार बनने का जताया भरोसा

अखिलेश यादव का दावा, सरकार बनी तो लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना

एजेंसी, लखनऊ



उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को लेकर कई घोषणाएं कीं। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी की योजनाओं की जानकारी भी दी। सपा अध्यक्ष ने 2027 में प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने का भरोसा जताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार स्तर पर आवश्यक फैसले लिए जाएंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी कर्मचारियों और शिक्षकों के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा को उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रमुख मुद्दों में शामिल किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी अपने घोषित फैसलों को लागू करने की दिशा में काम करेगी। अखिलेश यादव की घोषणाएं ऐसे समय में सामने आई हैं, जब प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं।

राजनीतिक दलों की ओर से अलग-अलग वर्गों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नीतियां और घोषणाएं सामने रखी जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने पार्टी की आगामी रणनीति और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना और शिक्षामित्रों से संबंधित घोषणाओं को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सपा अध्यक्ष के इन बयानों के बाद पुरानी पेंशन और शिक्षामित्रों का मुद्दा प्रदेश की चुनावी चर्चा में फिर प्रमुखता से सामने आया है।

पुरानी पेंशन का वादा

इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने से संबंधित निर्णय सरकार बनने के बाद प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। शिक्षामित्रों के संबंध में भी उन्होंने कहा कि उन्हें शिक्षक बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और इससे जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार स्तर पर फैसले किए जाएंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। अखिलेश यादव की घोषणाओं के बाद कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षामित्रों से जुड़े मुद्दे प्रदेश की राजनीतिक चर्चा में प्रमुखता से सामने आए हैं।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेरठ के उत्पादों ने देशी-विदेशी ग्राहकों का खींचा ध्यान

एजेंसी, मेरठ

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेरठ के उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और कारोबार विस्तार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। ट्रेड शो के तीसरे दिन देश-विदेश से पहुंचे ग्राहकों ने मेरठ के विभिन्न उत्पादों में रुचि दिखाई। ग्राहक उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता, कीमत और व्यापारिक संभावनाओं को लेकर जानकारी लेते नजर आए। उद्यमियों को उम्मीद है कि पांच दिवसीय आयोजन से उन्हें नए खरीदारों के साथ जुड़ने और बड़े ऑर्डर हासिल करने का अवसर मिलेगा।

ट्रेड शो में मेरठ की पारंपरिक मिठाइयों और खाद्य उत्पादों ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गजक, रेवड़ी और नान खटाई जैसे उत्पादों को देखने और खरीदने के लिए ग्राहक स्टालों तक पहुंच रहे हैं। एक जिला एक व्यंजन के तहत लगाए गए स्टाल पर मेरठ के पारंपरिक स्वाद को प्रदर्शित किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के साथ विदेशी ग्राहकों ने भी इन उत्पादों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा मेरठ के खेल उत्पाद भी ट्रेड शो में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेरठ लंबे समय से खेल सामग्री के निर्माण के लिए जाना जाता है।

यहां तैयार होने वाले खेल उत्पादों को लेकर खरीदारों ने कारोबार की संभावनाओं पर चर्चा की। हस्तशिल्प क्षेत्र में लिप्पन आर्ट ने भी लोगों का ध्यान खींचा। शिप्रा शर्मा के स्टाल पर प्रदर्शित कलाकृतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ग्राहकों ने कला के निर्माण और उत्पादों की कीमत समेत अन्य जानकारी ली। उद्यमियों का कहना है कि ऐसे आयोजन उन्हें स्थानीय बाजार से बाहर नए ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर देते हैं।

गुरुग्राम में रिहायशी इलाकों में कमर्शियल गतिविधियों पर रोक, पीजी और गेस्ट हाउस सील

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम



रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विपरीत चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ गुरुग्राम में कार्रवाई तेज होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग ने ऐसे परिसरों पर सीलिंग कार्रवाई को प्राथमिकता देने की तैयारी की है। रिहायशी भू-उपयोग वाले क्षेत्रों में पीजी, गेस्ट हाउस, होटल और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामलों की जांच की जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार, जिन संपत्तियों में स्वीकृत भू-उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित पाई जाएंगी, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पहले से की गई कार्रवाई के तहत गुरुग्राम में करीब 150 इमारतों को सील किया जा चुका है। इनमें बड़ी संख्या में पीजी और गेस्ट हाउस भी शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण और भू-उपयोग नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, रिहायशी क्षेत्रों में अनधिकृत कमर्शियल गतिविधियों के मामलों में संबंधित परिसर को सील करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस निर्देश के बाद गुरुग्राम में ऐसे मामलों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। गुरुग्राम के कई रिहायशी इलाकों में पीजी और गेस्ट हाउस संचालित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसके अलावा कुछ संपत्तियों में होटल, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित किए जाने के मामले सामने आए हैं। प्रशासन की ओर से इन संपत्तियों के भू-उपयोग और निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। विभाग की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य स्वीकृत भू-उपयोग के अनुसार ही संपत्तियों का इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संपत्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

न्यूनतम वेतनमान पर सरकार की अपील खारिज

हाई कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ जारी रखने का रास्ता हुआ साफ

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



न्यूनतम वेतनमान के लाभ को लेकर हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया है, जिनमें एकल पीठ के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिए जाने का आदेश बरकरार रहेगा।

मामला कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने से जुड़ा है। एकल पीठ ने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। सरकार की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए विभिन्न आधारों पर अपना पक्ष रखा गया। हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कर्मचारियों की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए। एकल पीठ के आदेश में भी कर्मचारियों को इस लाभ का अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी। सरकार की अपीलों पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने से संबंधित एकल पीठ का आदेश प्रभावी रहेगा। इससे संबंधित कर्मचारियों के वेतन और सेवा लाभ पर इसका असर पड़ेगा। मामले में वरुण गुसा से जुड़े फैसले का भी उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट की ओर से अपीलें खारिज किए जाने के बाद इस मामले में एकल पीठ के आदेश की स्थिति बरकरार हो गई है। न्यूनतम वेतनमान से जुड़े मामलों में कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से अपने अधिकारों और निर्धारित वेतनमान के अनुसार लाभ दिए जाने की मांग की जाती रही है। इस मामले में भी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने के आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार के सामने एकल पीठ के आदेश के अनुरूप आगे की प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति है।

न्यूनतम वेतनमान मामले में सरकार को निर्देश

हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले में राज्य सरकार को एकल पीठ के निर्देश के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संबंधित कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान और सेवा लाभ से जुड़े दावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से निर्धारित वेतनमान के अनुसार लाभ देने की मांग की जा रही थी। अपीलें खारिज होने के बाद अब इस मामले में आगे की कार्रवाई आदेश के अनुरूप होगी।

झज्जर में रोजगार के मुद्दे पर सीजेपी सक्रिय पुलिस समेत लंबित भर्तियां जल्द कराने की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर



हरियाणा में सरकारी भर्तियों और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर सीजेपी ने सोमवार को सक्रियता दिखाई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर लंबित भर्तियों को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है, जिससे नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) से संबंधित लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कराने की मांग की गई। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस भर्ती, स्टाफ नर्स और जूनियर इंजीनियर (जेई) सहित विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। पार्टी की ओर से युवाओं से जुड़े रोजगार के अन्य मुद्दों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने संबंधित विभागों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित करने की मांग की। सीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने के साथ भर्ती परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कार्य समय पर किए जाने चाहिए। ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकर्ताओं ने युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती होने से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और विभागों में कर्मचारियों की कमी भी दूर हो सकेगी।

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से लंबित भर्ती प्रक्रियाओं पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी से अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग की गई कि विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए। साथ ही भर्ती परीक्षाओं, परिणाम जारी करने और नियुक्ति से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें और विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर हो।

पानीपत में 19 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर दी जान

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। पानीपत जिले के गांव फरीदपुर में 19 वर्षीय युवक शिवम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय शिवम घर पर अकेला था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मिली जानकारी के अनुसार, शिवम के पिता राकेश रात के समय ड्यूटी पर गए हुए थे। सुबह ड्यूटी पूरी कर जब वह घर वापस लौटे तो कमरे में बेटे को फंदे पर लटका देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने पड़ोसियों की मदद से शिवम को फंदे से नीचे उतारा और तुरंत पानीपत के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक युवक के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की।

हरियाणा पुलिस में अगले साल होंगी 20 हजार नई भर्तियां

सरकार से दो साल में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1300 करोड़ खर्च करने की मिली मंजूरी

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम



हरियाणा पुलिस अगले दो वर्षों में आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर करीब 1300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने सोमवार को गुरुग्राम में सेक्टर 17-सी स्थित नवनिर्मित सेक्टर 17-18 थाने की नई बिल्डिंग के उद्घाटन के दौरान यह जानकारी दी।

डीजीपी ने बताया कि हरियाणा पुलिस में इस वर्ष अब तक 5500 भर्तियां हो चुकी हैं। नवंबर में चार हजार जवानों की और भर्ती की जाएगी। इसके बाद अगले वर्ष 20 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के साथ ही आधुनिक संसाधनों और बेहतर सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में आठ नए पुलिस थाने, तीन पुलिस चौकियां, नौ पुलिस भवन और 313 पुलिस आवासों का निर्माण किया गया है। पुलिस के आधुनिकीकरण पर इस वर्ष करीब 650 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। अगले दो वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्यों के लिए प्रस्तावित 1300 करोड़ रुपये से पुलिस व्यवस्था को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।

गुरुग्राम में नवनिर्मित सेक्टर 17-18 थाना भवन का निर्माण करीब साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसका निर्माण पुलिस हाउसिंग बोर्ड ने कराया है। इससे पहले थाना पुरानी बिल्डिंग से संचालित हो रहा था। नई बिल्डिंग में पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बेहतर कार्यस्थल उपलब्ध होगा। डीजीपी ने कहा कि पुलिस की प्राथमिकताओं में नशे के खिलाफ कार्रवाई, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटना भी शामिल है। इन क्षेत्रों में पुलिस की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक संसाधनों और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नशे, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध से निपटने पर रहेगा पुलिस का विशेष फोकस।

◆ डीजीपी अजय सिंघल ने गुरुग्राम में नवनिर्मित सेक्टर 17-18 थाने का उद्घाटन किया

मोहना एलिवेटेड रोड की ड्राइंग बदली, अब दो जगह सीढ़ियों से सीधे बाजार उतरेंगे लोग

भारतेन्दु संवाददाता, बल्लभगढ़

◆ मोहना एलिवेटेड मार्ग का 65 प्रतिशत काम पूरा, दो सीढ़ियों का प्रावधान

◆ मोहना एलिवेटेड मार्ग की नई ड्राइंग में लोगों की सुविधा का रखा ध्यान

मोहना एलिवेटेड मार्ग की ड्राइंग में बदलाव किया गया है। अब मार्ग पर लोगों के चढ़ने-उतरने की सुविधा के लिए दो जगह सीढ़ियां बनाई जाएंगी। इससे वाहन से उतरने के बाद बाजार के अंदर किसी काम से जाने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। नए प्रावधान के तहत लोग एलिवेटेड मार्ग से नीचे उतरकर सीधे बाजार की ओर जा सकेंगे। परियोजना की ड्राइंग में यह बदलाव हाल ही में किया गया है। अधिकारियों और संबंधित एजेंसी की ओर से लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मार्ग पर दो स्थानों पर सीढ़ियां बनाने का प्रावधान किया गया है।

इससे आसपास के बाजार और अन्य स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों को एलिवेटेड मार्ग से उतरने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। मोहना एलिवेटेड मार्ग का निर्माण कार्य फिलहाल जारी है। परियोजना का करीब 65 प्रतिशत काम पूरा किया जा चुका है, जबकि लगभग 35 प्रतिशत काम अभी शेष है। निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित समय सीमा को लेकर भी स्थिति सामने आई है। ठेकेदार की ओर से शेष काम पूरा करने के लिए डेडलाइन मार्च तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि, डेडलाइन बढ़ाने के संबंध में ठेकेदार ने अभी तक विभाग को लिखित आवेदन नहीं दिया है। ऐसे में परियोजना की समय सीमा बढ़ाने को लेकर औपचारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। एलिवेटेड मार्ग की ड्राइंग में किए गए बदलाव का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की आवाजाही को आसान बनाना है।

मार्ग पर दो सीढ़ियां बनने से बाजार में खरीदारी या अन्य काम से जाने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, जो अपने वाहन से एलिवेटेड मार्ग के आसपास पहुंचने के बाद बाजार की ओर जाना चाहते हैं। परियोजना का निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल निर्माण कार्य के कारण मार्ग पर विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। शेष 35 प्रतिशत काम पूरा होने और नई ड्राइंग के अनुसार सीढ़ियों के निर्माण के बाद परियोजना का उपयोग स्थानीय लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

ट्रैक, सोलर लाइट समेत कई सुविधाएं विकसित, जल संरक्षण पर भी दिया गया जोर

कविता चौधरी की पहल से बुंगा डैम को मिली नई पहचान

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला



चंडीगढ़ की बेटी और पंचकूला के बरवाला ब्लॉक के गांव बुंगा की सरपंच कविता चौधरी ने गांव के विकास के लिए पहल करते हुए डैम की तस्वीर बदलने का काम किया है। गांव में पहले से मौजूद डैम को अब सुखना लेक की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पहाड़ों के बीच स्थित इस डैम के आसपास कई सुविधाएं विकसित होने के बाद यहां का नजारा लोगों को आकर्षित करने लगा है। डैम के आसपास सैर करने के लिए ट्रैक विकसित किया गया है। इसके अलावा क्षेत्र में सोलर लाइट समेत अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इससे शाम के समय भी लोगों को यहां घूमने में सुविधा मिल रही है।

डैम के आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित करने के साथ-साथ इसे ग्रामीणों के लिए सैर-सपाटे के स्थान के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। गांव की सरपंच कविता चौधरी का उद्देश्य डैम के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है। उनका कहना है कि गांव में मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर लोगों के लिए सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं।

इसी दिशा में डैम के आसपास विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। पहाड़ों से घिरे होने के कारण डैम का प्राकृतिक वातावरण पहले से ही आकर्षक है। अब ट्रैक और सोलर लाइट जैसी सुविधाएं जुड़ने से इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। स्थानीय ग्रामीण भी डैम के विकास को लेकर उत्साहित हैं। उनका कहना है कि पहले जहां लोग केवल डैम और आसपास के प्राकृतिक दृश्य देखने आते थे, वहीं अब यहां सैर करने के लिए भी बेहतर जगह उपलब्ध हो रही है। डैम के विकास से जल संरक्षण के साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आने वाले समय में यहां और सुविधाएं विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

◆ पहाड़ों के बीच बुंगा डैम में विकसित हुईं ट्रैक और सोलर लाइट सुविधाएं

न्यूज ब्रीफ

रेवाड़ी में डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी, पांच लाख की रंगदारी मांगी

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा स्थित ईएसआईसी डिस्पेंसरी नंबर-2 में धमकी भरी चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया। दो पन्नों की इस चिट्ठी में डॉक्टरों से पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। पत्र में धमकी देने वाले ने खुद को यमराज बताते हुए लिखा कि जिसे वह चिट्ठी लिखता है, उसका मरना तय है। चिट्ठी में कहा गया है कि यदि डॉक्टरों को रंगदारी की रकम देने पर सहमति हो तो डिस्पेंसरी के गेट पर '+' का निशान बना दिया जाए। पत्र मिलने के बाद डिस्पेंसरी में मौजूद कर्मचारियों और डॉक्टरों में चिंता का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धमकी भरी चिट्ठी किसने भेजी और इसके पीछे किसका हाथ है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है। पुलिस पत्र की भाषा और उसमें लिखी धमकी के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

करनाल में बेकाबू आर्मी ट्रक ने एक्टिवा और ईको को मारी टक्कर

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। मेरठ रोड पर शेखपुरा गांव के नजदीक स्पीड ब्रेकर के पास आर्मी ट्रक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रक की चपेट में आने से एक्टिवा सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। इसके बाद ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी ईको वैन को भी टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार, आर्मी ट्रक स्पीड ब्रेकर से गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक ट्रक का टायर फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। बेकाबू ट्रक पहले एक्टिवा से टकराया। एक्टिवा पर पिता और पुत्र सवार थे। टक्कर लगने से दोनों घायल हो गए। इसके बाद ट्रक सड़क किनारे खड़ी ईको वैन से जा टकराया और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गया। हादसे की सूचना मिलने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। क्षतिग्रस्त आर्मी ट्रक को खाई से बाहर निकालने की कार्रवाई भी की गई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

कैथल में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल। जिले के गांव सोलू माजरा के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान राममेहर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राममेहर मोटरसाइकिल पर सवार होकर ढांड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गांव सोलू माजरा के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे की सही वजह और वाहन चालक की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

रेवाड़ी लौटे एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कमलजीत का एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले निशानेबाज कमलजीत के भारत लौटने पर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। गांव सुलखा से रेवाड़ी कोचिंग के लिए जाते समय वर्ष 2019 में हुए सड़क हादसे में उनका पैर टूट गया था। हादसे में दो लोगों की मौत भी हुई थी। गंभीर चोट के बावजूद कमलजीत ने निशानेबाजी का अभ्यास नहीं छोड़ा। उन्होंने बिस्तर पर रहते हुए भी अभ्यास जारी रखा। हादसे के महज 20 दिन बाद कमलजीत ने ट्रायल दिया और सफल रहे। इसके बाद उन्होंने मेहनत और लगन से निशानेबाजी में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया। अब एशियन स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। भारत लौटने पर परिजनों, समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उपलब्धि पर खुशी जताई।

भिवानी में पेड़ पर काली थैली में मिला नवजात, रोने की आवाज सुन जुटी भीड़

भारतेन्दु संवाददाता, भिवानी



शहर की बिजली बोर्ड कॉलोनी में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नवजात शिशु पेड़ पर काली थैली में लटका हुआ मिला। नवजात के रोने की आवाज सुनकर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को थैली से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नवजात लड़का करीब एक दिन का बताया जा रहा है। उसके शरीर पर जन्म के बाद की नाल भी बंधी हुई थी। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की। फिलहाल उसकी हालत स्वस्थ बताई जा रही है। बिजली कर्मचारी संघ के प्रधान एवं प्रत्यक्षदर्शी धर्मवीर भाटी ने बताया कि सुबह करीब पांच बजे तक मौके पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। इसके बाद करीब साढ़े पांच बजे कॉलोनी से गुजर रहे लोगों को पेड़ पर काली थैली दिखाई दी। थैली से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। लोगों ने पास जाकर देखा तो उसमें नवजात शिशु लटका हुआ था।

इसके बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को सूचना दी। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नवजात को पेड़ पर थैली में छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, आरोपी की पहचान के प्रयास जारी हैं।

विरोध | कांग्रेस सांसद ने धर्म और जाति के नाम पर समाज में वैमनस्य फैलाने का लगाया आरोप

यमुनानगर में गरजे दीपेंद्र हुड्डा, भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर



कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को यमुनानगर में आयोजित विरोध प्रदर्शन और कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में वोट नहीं, बल्कि सत्ता की चोरी हुई है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लघु सचिवालय के सामने सरकार का पुतला भी फूंका।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह लड़ाई किसी चुनाव को जीतने या हारने की नहीं, बल्कि देश के संविधान और आम नागरिक के मतदान के अधिकार को बचाने की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक संघर्ष करेगी। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर 'झूठ, फूट और लूट' के तीन सिद्धांतों पर चलने का आरोप लगाया।

हुड्डा ने कहा कि जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने के लिए भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है और धर्म तथा जाति के नाम पर समाज में वैमनस्य फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की बहुमूल्य संपत्तियां चुनिंदा बड़े उद्योगपति घरानों को सौंपी जा रही हैं। हुड्डा ने यमुनानगर सहित पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के मंत्री और विधायक अवैध कालोनियां काटने तथा माइनिंग में अपनी हिस्सेदारी तय करने में लगे हैं, जबकि आम जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव में परेशान है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। सम्मेलन में दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लोकतांत्रिक अधिकारों और मतदान के अधिकार को लेकर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।

हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण आम लोगों से जुड़े मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को रोजगार, महंगाई, विकास और मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों पर जवाब चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाज में धर्म और जाति के आधार पर विभाजन की राजनीति की जा रही है। हुड्डा के मुताबिक कांग्रेस का संघर्ष नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए है।

17,598 फीट पर पहुंचीं आईएएस सोनल गोयल, युवाओं को दिया नशामुक्ति का संदेश

14 दिन में करीब 140 किलोमीटर का ट्रेक पूरा कर एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचीं सोनल गोयल

एजेंसी, नई दिल्ली

त्रिपुरा कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सोनल गोयल 17,598 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचीं। करीब 14 दिन की इस यात्रा के दौरान उन्होंने लगभग 140 किलोमीटर का ट्रेक पूरा किया। बेस कैंप पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराया और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। सोनल गोयल ने इस यात्रा को नशामुक्त भारत और स्वस्थ जीवनशैली के संदेश से जोड़ा।

उन्होंने एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगे के साथ कैंसर जागरूकता का प्रतीक रिबन और 'ड्रग्स नहीं, ड्रीम्स चुनो' का संदेश प्रदर्शित किया। उन्होंने युवाओं से नशे की बजाय अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर सोनल गोयल ने कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश भी दिया। उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने पर जोर दिया। उनका कहना था कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जाना जरूरी है। उन्होंने



नशामुक्त भारत अभियान में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। अभियान के माध्यम से उन्होंने युवाओं को अपने भविष्य और लक्ष्यों के प्रति गंभीर रहने का संदेश दिया। एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा के दौरान उन्होंने कठिन परिस्थितियों में ट्रेक पूरा किया और वहां तिरंगा फहराकर अभियान का संदेश लोगों तक पहुंचाया। सोनल गोयल की इस यात्रा का उद्देश्य केवल पर्वतीय ट्रेक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे सामाजिक जागरूकता से भी जोड़ा गया। उन्होंने युवाओं को स्वस्थ आदतें अपनाने, नशे से दूरी बनाए रखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली के साथ युवा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

सोनल गोयल ने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की

उन्होंने कहा कि एवरेस्ट बेस कैंप तक की यात्रा ने उन्हें यह संदेश देने का अवसर दिया कि युवाओं की ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं से खेल, शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों और समाजसेवा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। सोनल गोयल ने कहा कि नशे से दूरी बनाकर युवा अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने परिवार और समाज के भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने कैंसर से बचाव के लिए जागरूकता और नियमित स्वास्थ्य जांच को भी जरूरी बताया। अभियान के दौरान उन्होंने लोगों से स्वस्थ आदतों को अपनाने और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का आग्रह किया। एवरेस्ट बेस कैंप से दिया गया उनका संदेश युवाओं को नशे से दूर रहने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करने पर केंद्रित रहा।

पीएचडी रिसर्च के लिए कंप्यूटर एक्सेस पर हाई कोर्ट सख्त

2020 से हिरासत में हैं शरजील इमाम, पीएचडी पूरी करने की मांग

एजेंसी, नई दिल्ली



पीएचडी पूरी करने के लिए जेल में मौजूद रिसर्च सामग्री को कंप्यूटर के माध्यम से एक्सेस करने की अनुमति मांगने वाली शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। इमाम ने अदालत से अनुरोध किया है कि उन्हें पेन ड्राइव में मौजूद शोध सामग्री का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह अपनी पीएचडी पूरी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकें।

याचिका में बताया गया है कि शरजील इमाम पीएचडी के अंतिम वर्ष में थे और जेल में रहने के कारण उनका शोध कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अपनी अकादमिक पढ़ाई और शोध को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री तक सीमित पहुंच की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर तिहाड़ जेल प्रशासन का पक्ष जानने के लिए जवाब मांगा है। अब जेल प्रशासन को अदालत के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि जेल में बंद व्यक्ति को पेन ड्राइव में उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री देखने के लिए कंप्यूटर की सुविधा देने के संबंध में क्या व्यवस्था और नियम हैं। अदालत के समक्ष जेल प्रशासन का जवाब आने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।

शरजील इमाम वर्ष 2020 से हिरासत में हैं और उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी हैं। जेल प्रशासन के जवाब में कंप्यूटर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, सुरक्षा प्रावधान और शोध सामग्री तक पहुंच से जुड़े नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हाई कोर्ट याचिका पर आगे विचार करेगा। मामले की अगली सुनवाई में प्रशासन के जवाब के आधार पर अदालत आगे का निर्देश जारी कर सकती है।

शरजील इमाम की याचिका पर तिहाड़ प्रशासन से जवाब तलब

मामले की अगली सुनवाई में तिहाड़ जेल प्रशासन के जवाब पर अदालत का ध्यान रहेगा। प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि जेल में बंद व्यक्ति को शैक्षणिक कार्य के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराने की क्या प्रक्रिया है और इस संबंध में किन सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता है। इसके अलावा पेन ड्राइव में मौजूद शोध सामग्री को कंप्यूटर पर एक्सेस करने की अनुमति देने से जुड़े प्रावधानों की जानकारी भी अदालत के समक्ष रखनी होगी। याचिका में शरजील इमाम ने कहा है कि वह अपनी पीएचडी के अंतिम वर्ष में थे और हिरासत में रहने के कारण शोध कार्य प्रभावित हुआ है। उनका कहना है कि शोध सामग्री तक सीमित पहुंच मिलने से वह अपनी अकादमिक प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। अदालत प्रशासन के जवाब और लागू नियमों पर विचार करने के बाद याचिका पर आगे सुनवाई करेगी। फिलहाल हाई कोर्ट ने कंप्यूटर सुविधा देने का कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। अदालत ने केवल तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद अदालत यह तय करेगी कि मामले में आगे क्या निर्देश दिए जाने हैं। अगली सुनवाई में याचिका से जुड़े नियमों और सुरक्षा पहलुओं पर भी विचार हो सकता है। शरजील इमाम वर्ष 2020 से हिरासत में हैं और उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में आरोपी हैं।

नौसेना के कमांडर नई दिल्ली में करेंगे कॉन्फ्रेंस, ऑपरेशनल तैयारियों पर होगा मंथन

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ रक्षा मंत्री साझा करेंगे समुद्री सुरक्षा पर अपना विजन



साल में दो बार होने वाली नौसेना कमांडरों की कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में शुरू होगी। तीन दिवसीय यह सम्मेलन एक अक्टूबर तक चलेगा। इसमें नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी सैन्य रणनीतिक स्तर पर ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन में आउटस्टेशन ऑपरेशनल और एरिया कमांडर भी संस्थागत प्रणाली के माध्यम से वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व से जुड़ेंगे।

नौसेना के कैप्टन विवेक मधवाल ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के बीच भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका सम्मेलन का अहम विषय होगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से नौसेना के मौजूदा अभियानों को मजबूत करने और हिंद महासागर क्षेत्र तथा उससे आगे एक भरोसेमंद समुद्री सुरक्षा साझेदार के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने पर चर्चा होगी। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन रक्षा मंत्री देश के समुद्री नजरिए और नौसेना से अपेक्षाओं को लेकर अपना विजन और मार्गदर्शन साझा करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे।

इसमें तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और बेहतर तालमेल बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। आगे के दिनों में नौसेना प्रमुख कमांडरों के साथ ऑपरेशन्स, मटेरियल, लॉजिस्टिक्स, राहत एवं बचाव और प्रशिक्षण से जुड़े विषयों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, ऑटोनॉमस और अनक्रूड सिस्टम तथा साइबर ऑपरेशंस जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा। भविष्य की युद्धक अवधारणाओं को अपनाने और तकनीक के तेजी से इस्तेमाल पर जोर रहेगा।

एक करोड़ की रंगदारी न देने पर फाइनेंसर को मारने पहुंचा बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी के एक फाइनेंसर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और रकम नहीं देने पर उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश के आरोप में हरेंद्र नागर उर्फ केडी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपित ने फाइनेंसर से सुरक्षा देने के नाम पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। मांग पूरी नहीं होने पर वह फाइनेंसर को निशाना बनाने पहुंचा था। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से दो अवैध पिस्तौल और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, समय रहते कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे संभावित वारदात को टाला जा सका। मामले में आरोपित से पूछताछ कर रंगदारी की साजिश और उसके संपर्कों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि हरेंद्र नागर अंबाला में हुई सोने की लूट के मामले में भी वांछित था। वहां करीब 1.5 किलो सोना लूटे जाने की वारदात में उसकी तलाश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस अब अंबाला पुलिस से भी आरोपित के संबंध में जानकारी जुटा रही है। गिरफ्तारी के दौरान बरामद दोनों पिस्तौल और कारतूसों के स्रोत की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपित को हथियार कहां से मिले और क्या उनका इस्तेमाल किसी अन्य वारदात में किया गया था।

◆ दिल्ली में रंगदारी की साजिश नाकाम, अंबाला सोना लूट का आरोपित गिरफ्तार

यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

एजेंसी, नई दिल्ली

◆ यूपीआई शुल्क मामले में केंद्र सहित संबंधित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

◆ यूपीआई शुल्क पर सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह में केंद्र से मांगा जवाब



उच्चतम न्यायालय ने दो हजार रुपये से अधिक के वाणिज्यिक यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

हालांकि, न्यायालय ने फिलहाल दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीरो-एमडीआर वाली कानूनी सुरक्षा वापस लेने के सरकार के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से यह बताने को कहा कि यूपीआई लेनदेन के लिए जीरो-एमडीआर व्यवस्था को समाप्त करने का आधार क्या है। वकील अंजनी दत्ता की ओर से दायर याचिका में 15 अक्टूबर से प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाने का फैसला रुपे डेबिट कार्ड को बिना किसी मौद्रिक सीमा के जारी नो-चार्ज सुविधा की तुलना में भेदभावपूर्ण है।

याचिकाकर्ता ने शुल्क से जुड़े लागत अध्ययन और ग्राहकों पर इसका बोझ पड़ने से रोकने के उपायों की जानकारी सार्वजनिक नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठाया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि भले ही व्यापारियों को ग्राहकों से शुल्क वसूलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन इसका असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में शामिल होकर अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। कम मार्जिन वाले व्यापारी यूपीआई भुगतान लेने से बच सकते हैं या बड़े भुगतान को कई हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दो हजार रुपये से अधिक के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर लगेगा।

नौ साल बाद खुलेगा बारापुला फेज-3 कॉरिडोर

मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक सिग्नल-फ्री सफर का रास्ता होगा साफ

एजेंसी, नई दिल्ली



अमित शाह करेंगे बारापुला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन।

राजधानी दिल्ली में लंबे इंतजार के बाद बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर आज जनता के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। करीब नौ साल की देरी के बाद कॉरिडोर के शुरू होने से मयूर विहार से सराय काले खां तक आवागमन आसान होने की उम्मीद है। इसके चालू होने के बाद इस मार्ग पर सिग्नल-फ्री सफर की सुविधा मिलेगी।

बारापुला फेज-3 एलिवेटेड कॉरिडोर मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक बनाया गया है। इसकी लंबाई करीब साढ़े तीन किलोमीटर है। कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने के बाद इसे यातायात के लिए खोलने की तैयारी की गई है। इसके शुरू होने से पूर्वी दिल्ली की ओर से सराय काले खां और आसपास के क्षेत्रों की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा।

कॉरिडोर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके जरिए मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल-फ्री यात्रा का रास्ता तैयार होगा। इससे यात्रियों को कई प्रमुख चौराहों पर रुकने की जरूरत कम होगी। हालांकि, वास्तविक यातायात प्रभाव कॉरिडोर के संचालन के बाद ही स्पष्ट होगा। बारापुला फेज-3 के उद्घाटन के साथ मुकरबा चौक रेलवे अंडरपास को भी जनता को समर्पित किया जाएगा। अंडरपास के शुरू होने से संबंधित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दोनों परियोजनाओं के संचालन से दिल्ली के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन को सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा।

बारापुला कॉरिडोर से सफर होगा आसान

कॉरिडोर के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली और मध्य दिल्ली के बीच आवाजाही के लिए एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा। इससे सराय काले खां और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन चालकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के संचालन के बाद यातायात के वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों की ओर से उद्घाटन से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं। मुकरबा चौक रेलवे अंडरपास के शुरू होने से भी संबंधित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने में मदद मिलने की संभावना है। कॉरिडोर से दिल्ली में यातायात सुगम होने की उम्मीद है।

जेएनयू मेस के खाने में कीड़े मिलने से हंगामा

एजेंसी, नई दिल्ली। डिलीवरी के जरिए खाना मंगाते समय उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार, ग्राहक को ऑर्डर करने से पहले रेस्टोरेंट की रेटिंग, ग्राहकों की प्रतिक्रियाएं और उपलब्ध फूड सेफ्टी संबंधी जानकारी जरूर देखनी चाहिए। रेस्टोरेंट का एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भी जांचा जा सकता है। खाना पहुंचने पर पैकेजिंग की स्थिति पर ध्यान दें। पैकेट खुला, फटा या असामान्य दिखाई देने पर उसे स्वीकार करने से बचें। खाने की गंध, रंग और बनावट में बदलाव नजर आए तो भी उसे खाने से बचना चाहिए। खाने में किसी तरह की गंदगी, कीड़ा या अन्य संदिग्ध वस्तु मिलने पर उसकी तस्वीर और वीडियो सुरक्षित रखें। इसके बाद संबंधित रेस्टोरेंट और डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद डीयू के तीन एलएलबी छात्र निलंबित

एजेंसी, नई दिल्ली



दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर-2 में पढ़ने वाले तीन एलएलबी छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दिल्ली पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निलंबित छात्रों में अभिमन्यु कुमार, अभिनव कुमार और नमन शामिल हैं। विश्वविद्यालय ने तीनों के दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। प्रॉक्टर कार्यालय की ओर से तीनों छात्रों के लिए अलग-अलग निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, तीनों छात्र लॉ सेंटर-2 में एलएलबी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं।

उनके खिलाफ यह कार्रवाई 23 सितंबर 2026 की शाम हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस में दर्ज एफआईआर के बाद की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एफआईआर में दर्ज मामले को आधार बनाते हुए छात्रों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। निलंबन अवधि के दौरान तीनों छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही उनके शैक्षणिक गतिविधियों और परिसर में मौजूदगी पर भी प्रशासनिक स्तर पर रोक लागू रहेगी। प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेशों में छात्रों के नाम और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से मामले में आगे की प्रक्रिया संबंधित नियमों के तहत किए जाने की बात कही गई है।

एफआईआर में दर्ज आरोपों और पुलिस जांच की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच भी महत्वपूर्ण होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई फिलहाल एफआईआर के आधार पर की गई है। छात्रों के खिलाफ दर्ज आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अपने स्तर पर आगे बढ़ेगी।

बृजभूषण मामले में चार महिला पहलवानों की अपील, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया नोटिस

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के खिलाफ चार महिला पहलवानों ने सत्र अदालत का रुख किया है। पहलवानों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। उन्होंने मामले में सह-आरोपित रहे विनोद तोमर के बरी होने को भी चुनौती दी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने सोमवार को अपील पर नोटिस जारी किया। अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है। अब संबंधित पक्षों के सामने आने के बाद अदालत अपील से जुड़े तथ्यों और ट्रायल कोर्ट के फैसले पर आगे सुनवाई करेगी। महिला पहलवानों की ओर से दायर अपील में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इससे पहले भी पहलवानों ने फैसले पर सवाल उठाते हुए दिल्ली की अदालत का रुख किया था। उनकी ओर से फैसले को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई गई



थीं। मामला भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर से जुड़ा है। दोनों को ट्रायल कोर्ट ने मामले में बरी किया था। अब चार महिला पहलवानों की अपील के बाद मामला सत्र अदालत के समक्ष पहुंच गया है।

अपील पर नौ अक्टूबर को होगी सुनवाई

अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत संबंधित पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद तथ्यों पर विचार करेगी। महिला पहलवानों की ओर से ट्रायल कोर्ट के फैसले में उठाए गए बिंदुओं को चुनौती दी गई है। वहीं, मामले में बरी किए गए दोनों आरोपितों का पक्ष भी अदालत के सामने रखा जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। नौ अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में अपील से जुड़े प्रारंभिक पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद अदालत मामले के रिकॉर्ड और ट्रायल कोर्ट के फैसले का परीक्षण करेगी।

निर्माणबंदी नए नियमों के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों पर भी असर पड़ेगा

दिल्ली में 1 नवंबर से निर्माण पर रोक, 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम

एजेंसी, नई दिल्ली



दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 2026-27 के सर्दी के मौसम को देखते हुए सरकार ने निर्माण कार्यों, कार्यालयों और पार्किंग व्यवस्था को लेकर कई बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक कुछ निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक रहेगी।

सरकार के अनुसार, इस अवधि में धूल उड़ाने वाले निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। बाहर किए जाने वाले सिविल कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ के ऐसे कार्य, जिनसे धूल का स्तर बढ़ता है, उन्हें निर्धारित अवधि में रोक दिया जाएगा। इसका उद्देश्य सर्दियों के दौरान हवा में धूल के कणों की मात्रा को नियंत्रित करना है। प्रदूषण नियंत्रण की योजना के तहत सरकारी और निजी कार्यालयों के संचालन में भी बदलाव किया जाएगा। कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे, जबकि बाकी 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था होगी। इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करने और आवागमन से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क भी दोगुना किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत पार्किंग शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना और सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। निर्माण कार्यों से संबंधित प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। इस दौरान संबंधित विभाग नियमों के पालन की निगरानी करेंगे।

दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए नए नियम लागू

कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया जाएगा। एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को ही ईंधन देने का प्रावधान किया गया है।1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। हालांकि सीएनजी, इलेक्ट्रिक, आपातकालीन सेवाओं और सरकारी कार्यों से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी जाएगी। खुले में कूड़ा और बायोमास जलाने पर भी सख्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि पहले से नियम तय करने से विभागों, निर्माण एजेंसियों और आम लोगों को तैयारी का पर्याप्त समय मिलेगा।

न्यूज ब्रीफ

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना समिति की बिलासपुर इकाई के तत्वावधान में सोमवार को प्रांचल पैलेस, पट्टा घुमारवीं में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त उपनिदेशक अमर सिंह ठाकुर मुख्यातिथि रहे, जबकि अध्यक्षता प्रांत कार्यकारिणी के मार्गदर्शक गणेश दत्त शर्मा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान दिवंगत पूर्व प्रांताध्यक्ष डॉ. देवराज शर्मा और जिला कार्यकारिणी सदस्य जगवीर सिंह की पत्नी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य वक्ता प्रो. डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन-दर्शन, एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भाखड़ा बांध के ऐतिहासिक एवं विकासात्मक पक्ष तथा पारंपरिक घराट पद्धति पर शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए। मुख्यातिथि अमर सिंह ठाकुर ने इतिहास को तथ्यपरक बनाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने भारतीय ज्ञान परंपरा, स्थानीय संस्कृति और गौरवशाली विरासत के संरक्षण की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारी, शोधकर्ता और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सरकारी योजनाओं व सब्सिडी की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर ने रेशम विभाग के सहयोग से निटकॉन लिमिटेड के माध्यम से आरएएमपी परियोजना के सामाजिक समावेशन घटक के तहत घुमारवीं में फंडिंग एवं नेटवर्किंग मीट का आयोजन किया। कार्यक्रम में करीब 54 रेशम पालन लाभार्थियों एवं उद्यमियों ने भाग लिया। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक एवं रेशम विभाग प्रभारी मनोज, रेशम विकास अधिकारी वंदना शर्मा, एनएसआईसी मंडी के मुख्य प्रबंधक लोकेश भाटिया सहित संबंधित अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहे। प्रतिभागियों को रेशम कोकून बाजार मंच, कोकून बिक्री के बाद उपलब्ध लाभ, सरकारी योजनाओं एवं सब्सिडी, उद्यम पंजीकरण, उद्यम विकास और बाजार संपर्क के बारे में जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने रेशम पालन को उद्यम के रूप में विकसित करने और उपलब्ध वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के तरीके बताए। लाभार्थियों ने विशेषज्ञों से वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं और उद्यम विस्तार से जुड़े सवाल पूछे। विशेषज्ञों ने मौके पर उनकी शंकाओं का समाधान किया। बैठक का उद्देश्य रेशम पालन से जुड़े लोगों को वित्तीय संसाधनों और बाजार से बेहतर जोड़ना रहा।

सिविल अस्पताल अर्की में आशा कार्यकर्ताओं को रेबीज से बचाव की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। विश्व रेबीज सप्ताह के तहत सिविल अस्पताल अर्की में आशा कार्यकर्ताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम 22 से 28 सितंबर तक मनाए जा रहे विश्व रेबीज सप्ताह के तहत खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में डॉ. विजय कुमार शांडिल ने आशा कार्यकर्ताओं को रेबीज के संक्रमण, बचाव और रोकथाम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संक्रमित पशु के काटने, खरोंचने या लार के संपर्क में आने से रेबीज फैल सकता है और समय पर उपचार न मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। उन्होंने बताया कि पशु के काटने या खरोंच लगने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से करीब 15 मिनट तक धोना चाहिए और बिना देरी स्वास्थ्य संस्थान पहुंचना चाहिए। उन्होंने घाव पर मिर्च, तेल, मिट्टी या राख लगाने से बचने की सलाह दी। आशा कार्यकर्ताओं से समुदाय में जागरूकता फैलाने और पालतू पशुओं के टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया गया।

स्वच्छता ही सेवा अभियान में छात्राओं ने वेस्ट टू आर्ट से दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। 'स्वच्छता ही सेवा-2026' अभियान के तहत नगर परिषद बिलासपुर द्वारा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में नगर परिषद की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी वर्षा चौधरी ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने छात्राओं की रचनात्मक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थी समाज में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। प्रधानाचार्या सीमा देवी ने भी छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में आरुषि ठाकुर प्रथम, हिमानी शर्मा द्वितीय और अमिशी तृतीय रहीं। चित्रकला में जैस्मिन शर्मा प्रथम, सजरून द्वितीय और शाहिद अंसारी तृतीय रहे। वहीं वेस्ट टू आर्ट प्रतियोगिता में गायत्री देवी प्रथम, रितिका द्वितीय और प्रिया तृतीय स्थान पर रहीं। छात्राओं ने बेकार सामग्री के पुनः उपयोग और स्वच्छता के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। नगर परिषद ने युवाओं को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने की दिशा में ऐसे आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया।

वॉलीबाल प्रतियोगिता में कराड़ाघाट टीम ने जीता खिताब



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की उपमंडल के कराड़ाघाट में वॉलीबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की नौ टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत ढानोघाट के प्रधान ढुनी चंद शर्मा ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कराड़ाघाट वार्ड सदस्य चमन लाल विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रतियोगिता में कराड़ाघाट की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। विजेता टीम को 4100 रुपए नकद और ट्रॉफी, जबकि उपविजेता टीम को 2100 रुपए नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मुख्यातिथि ढुनी चंद शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से युवाओं में अनुशासन, खेल भावना और आपसी भाईचारा विकसित होता है। युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।

नादौन में सुख आश्रय योजना के लाभार्थियों को दी 21.93 लाख रुपए की सहायता



भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए खंड स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समिति की बैठक सोमवार को एसडीएम निशांत शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नादौन में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। एसडीएम ने बताया कि नादौन खंड के 290 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छह माह से छह वर्ष तक के 4483 बच्चों तथा 929 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। बेटी है अनमोल योजना के तहत 93 बेटियों के नाम 19.44 लाख रुपये की एफडीआर तथा 640 बेटियों को 9.88 लाख रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 35 बच्चों को 18.96 लाख रुपये की सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा, वोकेशनल कोर्स, गृह निर्माण और कोचिंग के लिए भी सहायता प्रदान की गई, जिससे कुल सहायता 21.93 लाख रुपये रही। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत 262 बच्चों को 18.40 लाख और 28 युवाओं को 4.75 लाख रुपये दिए गए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 31 विवाहों के लिए 15.81 लाख तथा मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 100 लाभार्थियों को 31 लाख रुपये प्रदान किए गए। रुबरूने योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए।

एशियाई खेलों के हिमाचली मेडल विजेताओं को 5.33 करोड़ मिलेंगे

सावन बरवाल को 2.50 करोड़, सीमा 1.50 करोड़, चार कबड्डी खिलाड़ियों को मिलेंगे 33-33 लाख

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार कुल 5.33 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मेडल विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की।

महिला कबड्डी टीम में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल की चार खिलाड़ियों को 33-33 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर शामिल हैं। चारों खिलाड़ियों को कुल 1.32 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं, पुरुषों की मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपए और महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इस तरह कबड्डी, मैराथन और 10 हजार मीटर दौड़ के पदक विजेताओं को मिलाकर प्रदेश सरकार की ओर से कुल 5.33 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। प्रदेश से बाहर खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की यात्रा सुविधा में भी बढ़ोतरी की गई है। 200 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए एसी 3-टियर ट्रेन का किराया देने का प्रावधान है। वहीं, 200 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ी इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले हिमाचली खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।



एशियाई खेलों के गोल्ड पर 4 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है। एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 4 करोड़, रजत के लिए 2.50 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 1.50 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 करोड़, रजत पर 3 करोड़ और कांस्य पर 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि दी जा रही है। राष्ट्रमंडल और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़, रजत के लिए 2 करोड़ और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है।

भगत सिंह क्रांतिकारी ही नहीं, बल्कि युवा राष्ट्रनायक भी रहे: अनुराग ठाकुर



सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती के अवसर पर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइसरीगल लॉज स्थित ऐतिहासिक कक्ष में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसार, वाइसरीगल लॉज के बेसमेंट में स्थित यह कक्ष भगत सिंह की हिरासत से जुड़ी ऐतिहासिक स्मृति के रूप में संरक्षित है। अनुराग सिंह ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर भगत सिंह के चित्र के समक्ष नमन किया। उन्होंने ऐतिहासिक कक्ष में संरक्षित वस्तुओं और भगत सिंह के जीवन, संघर्ष एवं विचारों से संबंधित साहित्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह अदम्य साहस और गहन चिंतन वाले युवा क्रांतिकारी थे। उनके विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान युवाओं में राष्ट्रीय चेतना और कर्तव्यबोध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को भगत सिंह के साहस, बौद्धिक क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से देश के विकास और आत्मनिर्भरता में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में भगत सिंह से जुड़े इस ऐतिहासिक कक्ष को श्रद्धांजलि और स्मरण के स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है।

महिलाओं और युवाओं से किए वादे पूरे करे सरकार: पवन काजल

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक पवन काजल ने सोमवार को खोली पंचायत में करीब पांच लाख रुपए की लागत से निर्मित शिव महिला मंडल भवन का शुभारंभ किया।



इस दौरान उन्होंने कहा कि खोली पंचायत के 27 महिला मंडलों को विधायक निधि से 20-20 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। काजल ने महिलाओं से क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध एकजुट होकर आगे आने की अपील की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर महिलाओं और युवाओं से किए चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से महिलाओं को लंबित आर्थिक सहायता का भुगतान करने की मांग भी उठाई। विधायक ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कई युवा नौकरी की प्रतीक्षा करते हुए ओवरएज हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बेरोजगारों को सरकारी रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अब विभिन्न विभागों में अस्थायी नियुक्तियों के माध्यम से युवाओं के हितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। काजल ने बताया कि उनके कार्यकाल में खोली पंचायत में 32 हैंडपंप लगाए गए हैं तथा करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की नई पेयजल योजना का निर्माण अंतिम चरण में है। पंचायत के 53 गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान भी स्वीकृत हुए हैं। इस अवसर पर बीडीसी अध्यक्ष अनूप चांगरा सहित भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

बैजनाथ पुलिस ने पकड़े चार उद्घोषित अपराधी

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा पुलिस द्वारा उद्घोषित अपराधियों को पकड़ने संबंधित चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना बैजनाथ की टीम ने पिछले दो दिनों में चार उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में चकर राम, निवासी लुलांजी, धरेड़, बैजनाथ, रीना देवी, निवासी लुलांजी, धरेड़, बैजनाथ, जसपाल, निवासी ननवार, बैजनाथ तथा रमन कुमार, निवासी ननवार, बैजनाथ शामिल हैं। उक्त सभी आरोपियों को सक्षम न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। कांगड़ा पुलिस ने उक्त अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। एसपी कांगड़ा ने बताया कि यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा।

जिलाधीश ने तय किए खाद्य वस्तुओं के दाम

सादी थाली 100 और आधी थाली 60 रुपए, मीट-चिकन के भी तय हुए दाम

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। डीसी गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण आदेश-1977 के तहत अधिसूचना जारी करके जिला में विभिन्न खाद्य वस्तुओं एवं भोजन के खुदरा दाम निर्धारित किए हैं।



इस अधिसूचना के अनुसार जिला में सादे भोजन की थाली के दाम 100 रुपए और आधी थाली के 60 रुपए तय किए गए हैं। दो पुरी एवं चना या सब्जी-दही की प्लेट के दाम 80 रुपए, परांठा के 30 रुपए, तवा चपाती 8 रुपए, तंदूरी रोटी 11 रुपए, चावल फुल प्लेट 50 रुपए, दाल फ्राई 70 रुपए, रायता 50 रुपए, मीट करी 150 रुपए, चिकन करी 120 रुपये, पनीर प्लेट 100 रुपये, स्पेशल मिक्स वैज 80 रुपये, समोसा 15 रुपये, चना-दो समोसा 60 रुपये, चना-एक समोसा 40 रुपये, पैक्ड दूध, दही और पनीर अंकित मूल्य के अनुसार, खुला पनीर 380 रुपये प्रति किलोग्राम, दही 80 रुपये, लोकल दूध 70 रुपये, मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर का मीट 300 रुपये, चिकन 260 रुपये, मछली 220 रुपये, फ्राइड मछली 400 रुपये और जिंदा मुर्गे का दाम 150 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। लोकल सोडा की बोतल 20 रुपए और सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक्स अंकित मूल्य के अनुसार बेचे जा सकते हैं। मीट करी और चिकन करी की फुल प्लेट में कम से कम 200 ग्राम पीस होने चाहिए। इसी प्रकार, पनीर और स्पेशल मिक्स वैज की प्लेट में 100 ग्राम पनीर होना चाहिए। जिलाधीश ने सभी दुकानदारों और ढाबा संचालकों से इन दामों की सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

मेजर जनरल अमर रामदसानी ने सैनिक स्कूल का किया दौरा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। मेजर जनरल अमर रामदसानी, एवीएसएम, वाईएसएम, सीओएस, मुख्यालय 9 कोर एवं चेयरमैन, एलबीए ने सैनिक स्कूल सुजानपुर का दौरा किया। चेयरमैन, एलबीए का कार्यभार संभालने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक दौरा रहा। स्कूल पहुंचने पर प्रधानाचार्या ग्रुप कैप्टन प्रीति चोपड़ा ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूल बैंड ने देशभक्ति गीत 'सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा' की धुन प्रस्तुत की। दौरे के दौरान मेजर जनरल को स्कूल की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों तथा कैडेट्स के प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। उन्होंने स्कूल की विभिन्न सुविधाओं और व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। मेजर जनरल अमर रामदसानी ने स्कूल स्टाफ और अपॉइंटमेंट कैडेट्स से संवाद किया।

कछियारी स्कूल में भगत सिंह की जयंती पर बच्चों को बांटे पेन और फल

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर कछियारी स्कूल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को पेन और फल वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को भगत सिंह के जीवन, विचारों और देश के प्रति उनके त्याग से प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर पंचायत प्रधान कपिल कुमार, उपप्रधान विकास चौधरी, यूथ क्लब प्रधान मनोज कुमार तथा शहीद भगत सिंह ग्रुप के अध्यक्ष शिव चरण मौजूद रहे। क्षेत्र के युवाओं ने भी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने कहा कि शहीद भगत सिंह के विचार, साहस और देश के लिए किया गया त्याग हमेशा समाज और युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने बच्चों से भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का आह्वान किया।

बारिश में निजी बसों की मनमानी यात्रियों को कछियारी से पहले उतारा

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। लगातार हो रही बारिश के बीच निजी बसों की मनमानी ने यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है।

सोमवार को 53 मील से कांगड़ा, मटौर, पावर हाउस और वीरता की ओर जाने वाले कई यात्रियों को उस समय भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जब निजी बसों में उन्हें 53 मील से बैठाने के बाद कछियारी से पहले बाईपास मार्ग पर ही उतार दिया गया। यात्रियों का आरोप है कि बस परिचालकों ने उनसे निर्धारित किराया तो वसूल लिया, लेकिन उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के बजाय कछियारी से पीछे बाईपास रोड पर ही उतार दिया। इस दौरान तेज बारिश हो रही थी और कई यात्रियों के पास छाता तक नहीं था। मजबूरन उन्हें बारिश के बीच पैदल चलकर कछियारी पहुंचना पड़ा और वहां आगे जाने के लिए बस का इंतजार करना पड़ा। इस घटना को लेकर यात्रियों में खासा रोष देखने को मिला। परेशान यात्रियों प्रदीप कुमार, सुलोचना देवी, वीणा देवी, पप्पू कुमार, नितिन कुमार और रश्मी देवी सहित अन्य लोगों ने कहा कि यदि निजी बसों को आगे नहीं जाना था, तो उन्हें 53 मील से बस में बैठाया ही क्यों गया। यात्रियों का कहना था कि किराया लेने के बाद बीच रास्ते में उतार देना लोगों के साथ अन्याय है।

यात्रियों ने परिवहन विभाग और प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस मामले का संज्ञान लेकर निजी बस संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।



इस संदर्भ में प्रदेश एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस बाबत उनके पास कोई शिक नहीं आई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई श आती है तो उस पर कठोर कार्रवाई अमल मैं लाई जाएगी ताकि लोगों को कोई भी परेशानी न हो।

पांवटा साहिब में रेबीज दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, 300 वैक्सीन डोज उपलब्ध

रेबीज नियंत्रण के लिए सामुदायिक सहभागिता जरूरी: डीसी

भारतेन्दु संवाददाता, पांवटा साहिब। उपमंडलीय पशु चिकित्सालय पांवटा साहिब में विश्व रेबीज दिवस-2026 के अवसर पर रेबीज की रोकथाम, पशु टीकाकरण और जिम्मेदार पालतू पशु पालन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पशुपालन विभाग और रोटरी क्लब पांवटा साहिब के संयुक्त सहयोग से किया गया।



कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने किया। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि रेबीज केवल पशुओं से संबंधित बीमारी नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य और सामुदायिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि समय पर टीकाकरण, जिम्मेदार पशु पालन, जनजागरूकता तथा पशु के काटने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना रेबीज नियंत्रण के लिए आवश्यक है। उन्होंने पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभागों, सामाजिक संस्थाओं, पशु प्रेमियों और स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की। उपायुक्त ने रोटरी क्लब पांवटा साहिब की ओर से Rotary Against Rabies E&posure (RARE) Programme के तहत 300 एंटी-रेबीज वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाने की पहल की सराहना की। इनका उपयोग पशुपालन विभाग द्वारा स्ट्रीट और पालतू कुत्तों तथा बिल्लियों के निःशुल्क टीकाकरण में किया जाएगा कार्यक्रम में पशु कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए रोटेरियन अशोक गोयल, प्रबंध निदेशक तिरुपति ग्रुप तथा रोटरी क्लब पांवटा साहिब को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। अन्य पशु प्रेमियों और सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। पशुपालन उपनिदेशक एवं प्रजनन डॉ. राजीव वालिया ने रेबीज संक्रमण, पशुओं के टीकाकरण, जिम्मेदार पशु पालन और पशु के काटने के बाद तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेबीज रोकथाम योग्य, लेकिन गंभीर जूनोटिक बीमारी है। कार्यक्रम में एसडीएम द्विज गोयल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित महाजन, पशु चिकित्सा अधिकारी, रोटरी क्लब सदस्य और स्वयंसेवक मौजूद रहे। लोगों से रेबीज नियंत्रण अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया।

दून पहाड़ी संगठन के चुनाव को लेकर घमासान, नाराज सदस्यों ने खोला मोर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, पांवटा साहिब। दून पहाड़ी संगठन में हाल ही में हुए चुनाव को लेकर संगठन के भीतर मतभेद सामने आए हैं। चुनाव प्रक्रिया से नाराज संगठन के कुछ सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर अपनी आपत्तियां सार्वजनिक कीं। सदस्यों ने चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि संगठन के चुनाव पारदर्शी तरीके से सभी सदस्यों की मौजूदगी में होने चाहिए थे।



उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती उसके सदस्यों की सहभागिता और आपसी विश्वास पर निर्भर करती है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया को लेकर सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाना आवश्यक है। प्रेसवार्ता के दौरान नाराज सदस्यों ने कहा कि दून पहाड़ी संगठन क्षेत्र के लोगों और पहाड़ी समाज से जुड़े मुद्दों को उठाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ऐसे में संगठन के महत्वपूर्ण निर्णयों में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। सदस्यों का कहना था कि संगठन का चुनाव बंद कमरे में नहीं होना चाहिए था। चुनाव की प्रक्रिया खुले तौर पर सभी सदस्यों के समक्ष आयोजित की जानी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी की स्थिति पैदा न हो। सदस्यों ने कहा कि चुनाव को लेकर सामने आए मतभेदों का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन को किसी व्यक्ति विशेष या गुट तक सीमित करने के बजाय सभी सदस्यों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस दौरान यह भी बताया गया कि आगामी दिनों में संगठन की जनरल हाउस की बैठक बुलाई जाएगी।

बैठक में संगठन से जुड़े सभी सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा और चुनाव प्रक्रिया सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सदस्यों के अनुसार जनरल हाउस में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा और आपसी चर्चा के बाद विवाद का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बैठक के माध्यम से संगठन में उत्पन्न मतभेदों को दूर कर सभी सदस्य एकजुट होकर आगे काम करेंगे। वहीं, जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर-6 सतौन से खतरी सिंह ने भी संगठन के विवाद को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दून पहाड़ी संगठन सामाजिक और सामुदायिक हितों से जुड़ा संगठन है। इसलिए संगठन के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संगठन को राजनीति से अलग रखते हुए समाज और क्षेत्र के हितों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रेसवार्ता के दौरान सदस्यों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या गुट का विरोध करना नहीं, बल्कि संगठन की चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी बात रखना है। उन्होंने सभी सदस्यों से आगामी जनरल हाउस में शामिल होकर अपनी बात रखने और आपसी सहमति से समाधान निकालने की अपील की।

एडवोकेट अभिषेक शामा नशा निवारण बोर्ड के सदस्य नियुक्त

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। जिला हमीरपुर से ताल्लुक रखने वाले 30 वर्षीय एडवोकेट अभिषेक शामा को राज्य नशा निवारण बोर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य नियुक्त किया गया है। नियुक्ति पर उन्होंने मुख्यमंत्री एवं नशा निवारण बोर्ड के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू का आभार जताया। अभिषेक शामा ने कहा कि प्रदेश में एंटी ड्रग नीतियों और नए कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान चलाने के साथ अभिभावकों से संवाद और नशे की गिरफ्त में आए लोगों को इससे बाहर निकालने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। अभिषेक शामा छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वह कॉलेज में एनएसयूआई के संयुक्त सचिव रहे हैं। इसके अलावा जिला यूथ कांग्रेस के संयुक्त सचिव और डीसीसी हमीरपुर के महासचिव सहित विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। सामाजिक कार्यों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही है।

वोट चोरी के आरोपों पर तथ्य व आधिकारिक रिकॉर्ड सामने रखे कांग्रेस : विजय अग्निहोत्री

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने जिला कांग्रेस द्वारा कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर किए गए धरना-प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह प्रदर्शन पूरी तरह विफल रहा और कांग्रेस के कई पदाधिकारियों तथा आम लोगों ने भी इससे दूरी बनाए रखी।



विजय अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस को निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक भ्रम पैदा करने के बजाय तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर अपनी बात जनता के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को निर्वाचन आयोग की ओर से जारी स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस के लिए आवश्यक है कि वह अपने आरोपों की पुष्टि ठोस तथ्यों और कानूनी आधार के साथ करे। उन्होंने कहा कि आयोग ने एसआईआर से जुड़े निर्णयों को आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से लिया गया बताया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं से सवाल करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन गंभीर आरोपों के लिए ठोस तथ्य और प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में मतदाता सूचियों की शुद्धता के साथ-साथ दुर्गम क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया तक पह

न्यूज ब्रीफ

जिला व तालुका न्यायालयों में कम खर्च में निपटेंगे मामले

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। लंबे समय से लंबित विवादों के जल्द समाधान के लिए मंडी में 'मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0' अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक चलेगा और लंबित मामलों के निपटारे तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के सहयोग से जिला व तालुका न्यायालयों में यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विवाह व पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, घरेलू हिंसा, मोटर वाहन चालान, वाणिज्यिक व सेवा संबंधी मामले, समझौता योग्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद और ऋण वसूली सहित विभिन्न मामलों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एसीजेएम विवेक कायस्थ ने बताया कि मध्यस्थता गोपनीय, लचीली और कम खर्चीली प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षित मध्यस्थ की सहायता से पक्षकार आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अभियान का लाभ उठाने की अपील की।

कलाग्राम में सजी साहित्यकारों की महफिल



भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। कला ग्राम के रूप में विकसित हो रहे पंजैहठी में कालरू कायथ फाउंडेशन के पोयट्री क्लब की पहली बैठक आयोजित हुई। नैण तारा मात्री निलय परिसर में हुई बैठक में पहाड़ी कविता के अस्तित्व तथा लोकनाट्य और लोककलाओं में काव्यात्मक अनुभूति पर सार्थक चर्चा की गई। साहित्यकार एवं संस्कृति कर्मी मुरारी शर्मा ने लोकनाट्य व लोककलाओं में काव्यात्मक अनुभूति विषय पर प्रपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा कि लोकगीत, लोकगाथाएं, कहावतें व लोकनाट्यों के संवादों में काव्यात्मकता विद्यमान है। वहीं कवि-आलोचक डॉ. विजय विशाल ने मंडी जनपद की हिंदी कविता पर अपना लेख प्रस्तुत किया। दूसरे सत्र में जगदीश कपूर, डॉ. राकेश कपूर, प्रकाश चंद्र धीमान और विनोद गुलेरिया ने अपनी पहाड़ी कविताओं का पाठ किया। प्रस्तुत रचनाओं पर साहित्यकारों ने विचार साझा किए। मुरारी शर्मा ने कहा कि पहाड़ी कविताओं की पर्याप्त आलोचना न होने से उनका समुचित मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। बैठक में सरिता हांडा और युवा कवि अनिल महंत भी उपस्थित रहे।

राजनीतिक शास्त्र शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 94 उम्मीदवार चयनित

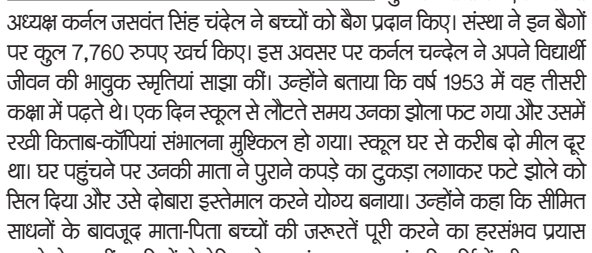
भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में राजनीतिक शास्त्र शिक्षकों के 95 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड-26028 के तहत फिक्स मानदेय आधार पर होने वाली भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद परिणाम जारी किया गया। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती के लिए कुल 3650 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 3002 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी। परीक्षा के आधार पर 239 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था। 17 और 19 सितंबर को दस्तावेजों की जांच के बाद 94 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया। उन्होंने बताया कि पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक पद रिक्त रह गया है। अंतिम परिणाम में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है।

आरसीएफसी बचाओ संघर्ष समिति की भूख हड़ताल जारी



भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। आरसीएफसी बचाओ संघर्ष समिति जोगिंद्रनगर की भूख हड़ताल 40वें दिन में प्रवेश कर गई। ग्राम पंचायत ऐहजू के प्रधान बलबीर वर्मा, उपप्रधान संजय भंगालिया, नेक राम वालिया और संसार चंद भूख हड़ताल पर बैठे। पिछले दिन की टीम ने माला पहनाकर उन्हें अगले 24 घंटे के क्रम की जिम्मेदारी सौंपी। समिति के महासचिव रोटेरियन अजय ठाकुर ने कहा कि जनता का एकजुट आंदोलन जरूर रंग लाएगा और जोगिंद्रनगर का संस्थान यहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में लगातार नए लोग जुड़ रहे हैं और समिति को उम्मीद है कि आरसीएफसी को सोलन स्थान कहा कि अधिसूचना रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संयोजक कुशाल भारद्वाज ने कहा कि समिति और जनता शिफ्टिंग की अधिसूचना रद्द करवाने से कम किसी बात पर सहमत नहीं होगी। इस दौरान समिति के पदांतरित करने की अधिसूचना रद्द होगी। समिति के सलाहकार ज्ञान चंद ठाकुर ने कहा कि अधिसूचना रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। संयोजक कुशाल भारद्वाज ने कहा कि समिति और जनता शिफ्टिंग की अधिसूचना रद्द करवाने से कम किसी बात पर सहमत नहीं होगी। इस दौरान समिति के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

रेबीज से बचाव के प्रति छात्रों को किया जागरूक



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा में विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डॉ. शशी दत्त शर्मा के दिशा-निर्देशों पर हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य सुखदेव जंवाल ने की। मुख्य वक्ता जिला स्वास्थ्य शिक्षक गोपाल कौशल ने विद्यार्थियों को रेबीज के कारण, लक्षण, बचाव और समय पर टीकाकरण के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने पशु के काटने पर बरती जाने वाली सावधानियों के साथ सर्पदंश से बचाव व प्राथमिक उपचार, एचपीवी वैक्सीन तथा बधिरता जागरूकता सप्ताह के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में भाषण और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताएं भी करवाई गईं। भाषण प्रतियोगिता में लक्ष्य प्रथम, सोनाक्षी द्वितीय और प्रियशीं तृतीय रही। पोस्टर मेकिंग में प्ररांसी प्रथम, सानिया द्वितीय और पारुल तृतीय स्थान पर रहीं। विजेताओं व प्रतिभागियों को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में 108 विद्यार्थियों ने भाग लिया और समापन पर बच्चों को फल वितरित किए गए।

कर्नल जसवंत सिंह चंदेल को 1953 की याद ने किया भावुक, 35 बच्चों को बांटे स्कूल बैग



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। मप्जुषा सहायता केंद्र कलोल की ओर से राजकीय प्राथमिक पाठशाला बकैण के 35 विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए गए। मुख्य अतिथि एवं संस्था अध्यक्ष कर्नल जसवंत सिंह चंदेल ने बच्चों को बैग प्रदान किए। संस्था ने इन बैगों पर कुल 7,760 रुपए खर्च किए। इस अवसर पर कर्नल चन्देल ने अपने विद्यार्थी जीवन की भावुक स्मृतियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1953 में वह तीसरी कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय उनका झोला फट गया और उसमें रखी किताब-कॉपियां संभालना मुश्किल हो गया। स्कूल घर से करीब दो मील दूर था। घर पहुंचने पर उनकी माता ने पुराने कपड़े का टुकड़ा लगाकर फटे झोले को सिल दिया और उसे दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बनाया। उन्होंने कहा कि सीमित साधनों के बावजूद माता-पिता बच्चों की जरूरतें पूरी करने का हरसंभव प्रयास करते थे। इन्हीं स्मृतियों से प्रेरित होकर संस्था जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता कर रही है। उन्होंने बताया कि संस्था अब तक 160 से अधिक विद्यार्थियों की पढ़ाई में सहयोग कर चुकी है।

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी शिमला में दिसंबर जैसी ठंड

मानसून में बारिश से जुड़े हादसों में 373 लोगों की मौत, 3,220 करोड़ का नुकसान

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मानसून की विदाई से पहले हिमाचल प्रदेश में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है।



सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से सितंबर के आखिरी दिनों में कई क्षेत्रों में जुलाई-अगस्त जैसी तेज बारिश हुई। शिमला में सोमवार को दिनभर मूसलाधार बारिश हुई और ठंड बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़े और हीटर निकाल लिए। लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ और शाम तक राज्य में 61 सड़कें बंद रहीं। किन्नौर में एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई घंटे बंद रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। शिमला के रोहड़ू में भूस्खलन का मलबा सुंदरू खड्ड में गिरा। मौसम विभाग के अनुसार 29 सितंबर को भी बारिश हो सकती है, जबकि 30 सितंबर से 4 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है।

इसी अवधि में दक्षिण-पश्चिम मानसून के हिमाचल से विदा होने के आसार हैं। इस मानसून सीजन में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 373 लोगों की मौत हुई है और राज्य को करीब 3,220 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। कई दिनों तक शुष्क मौसम रहने के बाद सोमवार को राजधानी शिमला में जोरदार बारिश हुई। सुबह से लेकर शाम तक बारिश का दौर जारी रहा।

तापमान में गिरावट के चलते शहर में ठंड बढ़ गई और लोगों ने गर्म कपड़ों के साथ घरों और दुकानों में हीटर का सहारा लिया। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में भी कई जगह बारिश हुई। वहीं, लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी रहा। बारिश और बर्फबारी के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ गई है।

रोहड़ू में भूस्खलन, सुंदरू खड्ड में गिरा मलबा

शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल में सोमवार को भारी भूस्खलन हुआ। छोहरा विकास खंड के जंगलिख गांव के समीप पहाड़ी से बड़ी मात्रा में मलबा गिरकर सुंदरू खड्ड में जा पहुंचा। भूस्खलन से जंगलिख गांव को जाने वाला पैदल रास्ता भी अवरुद्ध हो गया। मलबा खड्ड में गिरने के बाद कुछ समय के लिए पानी का बहाव प्रभावित हुआ। बाद में पानी का बहाव सामान्य हो गया। प्रशासन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए तहसीलदार चिड़गांव को मौके पर भेजा। एसडीएम रोहड़ू धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि सुंदरू खड्ड में मलबा गिरने से पानी का बहाव थोड़ी देर प्रभावित हुआ था।

सरकार व जनता के बीच मजबूत कड़ी हैं आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता : डॉ. सिकंदर



अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र की ननावां पंचायत में 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने की, जबकि राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. सिकंदर कुमार ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान ननावां, मल्यावर, कुहमझवाड़ और बल्हचुराणी सहित आसपास की पंचायतों की आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट सेवाभाव के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता सरकार व जनता के बीच मजबूत सेतु का कार्य कर रही हैं। सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद वे समाज के अंतिम छोर तक मातृ-शिशु स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और परिवारों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में इन कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसमें नारी शक्ति की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज के प्रति उनकी सेवा प्रेरणादायक है।

वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने हमीरपुर में किया धरना-प्रदर्शन

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। कथित वोट चोरी व निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर ने सोमवार को गांधी चौक पर धरना-प्रदर्शन किया।



जिलाध्यक्ष सुमन भारती शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, हमीरपुर कांग्रेस प्रभारी जीवन ठाकुर, जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीता वर्मा, वरिष्ठ नेता नरेश ठाकुर, डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, राजेश वनियाल, अजय शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रभारी जीवन ठाकुर ने कहा कि मतदाता सूचियों और चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए।

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी कड़ी में हमीरपुर में यह प्रदर्शन किया गया है। जिला अध्यक्ष सुमन भारती शर्मा ने कहा कि 2014 से देश में लोकतंत्र के लिए कठिन समय चल रहा है और केंद्र सरकार की शह पर वोट चोरी का खेल हो रहा है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित होने तक आंदोलन जारी रहेगा। डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी भूमिका में विफल रहे हैं, जबकि अनीता वर्मा ने आरोप लगाया कि जनादेश का अपहरण किया जा रहा है। गांधी चौक पर काफी देर तक नारेबाजी चलने से सियासी माहौल गरमाया रहा।

नूरपुर पुलिस की कार्रवाई, 11.81 ग्राम चिट्टे सहित दो गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। नूरपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11.81 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जिला नूरपुर की एसपी इल्मा अफरोज के दिशा-निर्देशों पर सीआईए टीम ने यह कार्रवाई छतरोली स्थित बाबा दत्ता मल शोरूम के पास की।

एएसपी धर्म चंद वर्मा के अनुसार, पुलिस टीम गश्त पर थी। करीब 3:25 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि सैंट्रो कार में दो व्यक्ति हेरोइन लेकर छतरोली में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर पहुंची। करीब 4:04 बजे वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अंकुश की सीट के अंदर छिपाकर रखा काले रंग का पॉलीथिन लिफाफा बरामद हुआ। इसमें हल्के भूरे रंग का पदार्थ मिला, जिसकी ड्रग डिटेक्शन किट से जांच करने पर हेरोइन/चिट्टा होने के सकारात्मक संकेत मिले। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसकी मात्रा 11.81 ग्राम पाई गई। पुलिस ने मादक पदार्थ और वाहन को कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संदीप कुमार उर्फ सैंडी (36) निवासी बासा, नगरोटा सूरियां और अंकुश (32) निवासी नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सप्लाई से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच कर रही है।



कांगड़ा में आज कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। बिजली उपमंडल नंबर-1 कांगड़ा के अंतर्गत 11 केवी कांगड़ा नंबर-1 फीडर 30 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से कार्य समाप्ति तक बंद रहेगा। सहायक अभियंता ई. पुलकित दीक्षित ने बताया कि फीडर पर आवश्यक रखरखाव तथा बिजली तारों के साथ लगती टहनियों की कटाई का कार्य किया जाना है। इस दौरान घुरकड़ी, वीरता, गर्ग कॉलोनी, तारा मंदिर, फोर्टिस अस्पताल, बालाजी अस्पताल, इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू बस स्टैंड कांगड़ा, पॉलिटेक्निक कांगड़ा, जमानाबाद रोड, कॉलेज रोड, टंडन क्लब, नटेहड़ और जयंती विहार सहित संबंधित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। यदि किसी कारणवश निर्धारित दिन कार्य पूरा नहीं हो पाया तो शेष कार्य अगले दिन किया जाएगा। यह जानकारी वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता, बिजली मंडल कांगड़ा द्वारा दी गई।

युवक मंडल व ग्रामीणों ने श्रमदान कर रास्तों व नालियों की सफाई की

भारतेन्दु संवाददाता, कुल्लू। युवाओं को सेवा, स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित माय भारत सेवा पखवाड़ा के तहत खराहल घाटी के थासीभ्रा गांव में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया।



बिजलेश्वर युवक मंडल थासीभ्रा ने ग्रामवासियों के सहयोग से यह अभियान आयोजित किया। अभियान माय भारत कुल्लू, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में हुआ। अभियान के दौरान युवक मंडल के सदस्यों और ग्रामीणों ने सामूहिक श्रमदान कर गांव के रास्तों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। रास्तों पर फैले कूड़े-कचरे के साथ कांटों व झाड़ियों को हटाया गया। वहीं, कचरे से बंद पड़ी नालियों की सफाई कर पानी की निकासी भी सुचारू की गई। युवक मंडल के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गांव के कई स्थानों पर कूड़ा जमा होने और नालियां बंद होने से ग्रामीणों व राहगीरों को परेशानी हो रही थी।

इसी समस्या के समाधान के लिए अभियान चलाया गया। युवक मंडल सदस्यों ने घर-घर जाकर ग्रामीणों से अभियान में शामिल होने का आग्रह किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया। युवक मंडल ने ग्रामीणों का आभार जताते हुए लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की। अभियान में उपाध्यक्ष रोहित, सचिव पुनीत, वित्त सचिव मोहित सहित उत्तम चंद, नरेंद्र कुमार, सुमित, चुनी लाल, नरेश कुमार, पदम सिंह व निशांत कुमार मौजूद रहे।

नगरोटा बगवां कॉलेज में पीटीए बैठक आज

भारतेन्दु संवाददाता, नगरोटा बगवां। राजकीय महाविद्यालय नगरोटा बगवां में अभिभावक-शिक्षक संघ (पीटीए) की बैठक मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे प्राचार्य कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बैठक में महाविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा के साथ विद्यार्थियों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार सोनी ने सभी अभिभावकों से बैठक में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने विद्यार्थियों से भी अपने अभिभावकों को बैठक की जानकारी देने का आग्रह किया है। प्राचार्य ने बताया कि इससे पहले कोरम पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के साथ-साथ महाविद्यालय की गतिविधियों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

लगदाघाट-सुन सड़क निर्माण कार्य शुरू

ग्रामीणों में खुशी की लहर, मुख्यमंत्री और विधायक अवस्थी का जताया आभार

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड कुनिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत लग के गांव सुन के लोगों का करीब 23 वर्षों से चला आ रहा सड़क का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया।

लगदाघाट से सुन तक सड़क निर्माण कार्य विधिवत रूप से शुरू हो गया। लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग कर रहे ग्रामीणों में निर्माण कार्य शुरू होने से खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। जानकारी के अनुसार, लगदाघाट-सुन सड़क परियोजना की नींव वर्ष 2003 में रखी गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को लंबे समय से आवागमन सहित कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों के अनुसार, कई बुजुर्गों ने अपने जीवनकाल में इस सड़क को बनते देखने का सपना संजोया था, लेकिन उनका यह इंतजार पूरा नहीं हो सका।



ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2026 में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और अर्की के विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करवाया गया है।

सड़क निर्माण शुरू होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और विधायक का आभार व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सड़क सुविधा उपलब्ध होने के बाद क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने भविष्य में खेल मैदान, सामुदायिक भवन सह मैरिज हॉल, श्मशान घाट तक सड़क सुविधा तथा लग पंचायत में पशु चिकित्सालय जैसी अन्य विकास योजनाओं को भी जल्द साकार किए जाने की उम्मीद जताई। ग्रामीणों ने कहा कि इन सुविधाओं के मिलने से क्षेत्र के लोगों, विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग जारी रखने की बात कही। मुख्यमंत्री सुक्खू और विधायक संजय अवस्थी का प्रधान शकुंतला देवी, उपप्रधान अनिल कुमार, बलदेव, दिला राम, शेर सिंह, श्याम लाल, रंजीत सिंह, मोहन लाल, सुरजन सिंह, सुखदेव, रामलोक, प्रेम लाल, मान सिंह, कांशी राम, सूबेदार मदन ठाकुर सहित अन्य ग्रामीणों ने तहेदिल से आभार व्यक्त किया।

बैठक | **बिलासपुर जिले में अब 160 बच्चों को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए हर माह**

मिशन वात्सल्य में 51 नए बच्चों को मदद की मंजूरी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जरूरतमंद व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला बिलासपुर में मिशन वात्सल्य के तहत 51 नए बच्चों को प्रायोजन योजना का लाभ देने की मंजूरी प्रदान की गई है।



इस संबंध में प्रायोजन एवं पालन-पोषण देखभाल स्वीकृति समिति की बैठक उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में महिला व बाल विकास विभाग की ओर से प्रस्तुत मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद जिले के विभिन्न विकास खंडों के 51 बच्चों को योजना में शामिल करने की स्वीकृति दी गई। इनमें सदर विकास खंड के 18, श्री नयना देवी जी के 15, झंडूता के 4 तथा घुमारवीं के 14 बच्चे शामिल हैं। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि बिलासपुर जिले में पहले से 109 बच्चे प्रायोजन योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को प्रतिमाह चार हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 51 नए बच्चों को स्वीकृति मिलने के बाद योजना से लाभान्वित बच्चों की कुल संख्या बढ़कर 160 हो जाएगी। बैठक में बताया गया कि स्वीकृत 51 बच्चों को प्रारंभिक तौर पर मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। मिशन वात्सल्य के लिए धनराशि प्राप्त होने के बाद इन्हें मिशन वात्सल्य की प्रायोजन योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। डीसी ने कहा कि मिशन वात्सल्य का उद्देश्य कठिन और संवेदनशील परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना है, ताकि वे अपने परिवार एवं सामाजिक परिवेश में सुरक्षित रहते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और समुचित विकास के अवसर प्राप्त कर सकें। योजना के तहत पात्र बच्चों और परिवारों को चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्त माताओं के बच्चे, विस्तारित परिवार के साथ रह रहे अनाथ बच्चे, गंभीर बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे तथा आर्थिक या शारीरिक कारणों से बच्चों की देखभाल करने में असमर्थ अभिभावकों के बच्चे योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी, शोषण, दुर्व्यवहार, सड़क पर रहने अथवा अन्य कठिन परिस्थितियों से प्रभावित बच्चों को भी सहायता के लिए चिन्हित किया जा सकता है। डीसी ने अधिकारियों को योजना के लाभार्थी बच्चों की समय-समय पर स्थिति की जांच करने तथा उनके स्वास्थ्य एवं विकास की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाने को भी कहा गया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को ग्राम सभाओं के माध्यम से मिशन वात्सल्य सहित बच्चों से संबंधित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि पात्र बच्चों की समय पर पहचान हो सके और उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। डीसी ने कहा कि बच्चों के संरक्षण और कल्याण के लिए विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पात्र बच्चा सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष तृप्ता ठाकुर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सत्या चंदेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी गैर-संस्थागत शैली गुलरिया, जिला समन्वयक नीलम डोगरा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

खोली में सड़क निर्माण के लिए दूसरे चरण का सर्वे जल्द होगा शुरू : मोंगरा



आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। एपीएमसी के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जिलाध्यक्ष चौधरी नरेंद्र निशु मोंगरा ने 'आपका सेवक आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत खोली का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए निशु मोंगरा ने कहा कि खोली स्कूल से लेकर सिंबल खोला से आगे तक सड़क निर्माण की योजना है। इसके लिए दूसरे चरण का सर्वे जल्द शुरू किया जाएगा, जिसके बाद सड़क निर्माण की दिशा में आगामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने खोली में महिला मंडल भवन के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन भी किया। उन्होंने बताया कि पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 8 में करीब 40 लाख रुपए की लागत से पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही एक वाटर टैंक का भी निर्माण किया जाएगा। इससे दोनों वार्डों में पेयजल समस्या को काफी हद तक दूर करने में मदद मिलेगी। निशु मोंगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 'आपका सेवक आपके द्वार' कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं और मांगों को सीधे सुनकर उनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर पंचायत प्रधान कुलवंत, निशा चौधरी, पूर्व प्रधान केवल चौधरी, संदीप चौधरी, हरविंदर गौरा, अश्वनी चौधरी, प्रकाश चंद भाटिया सहित महिला मंडल की सदस्याएं और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

रोसेला फियामिंगो का अंदाज सबसे अलग

रोसेला फियामिंगो इटली की प्रसिद्ध तलवारबाजी खिलाड़ी हैं। कैटानिया में जन्मी फियामिंगो ने ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने तलवारबाजी में ओलंपिक पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। उनकी मेहनत, तकनीक, अनुशासन और निरंतर अभ्यास ने उन्हें विश्वस्तरीय खिलाड़ी बनाया।

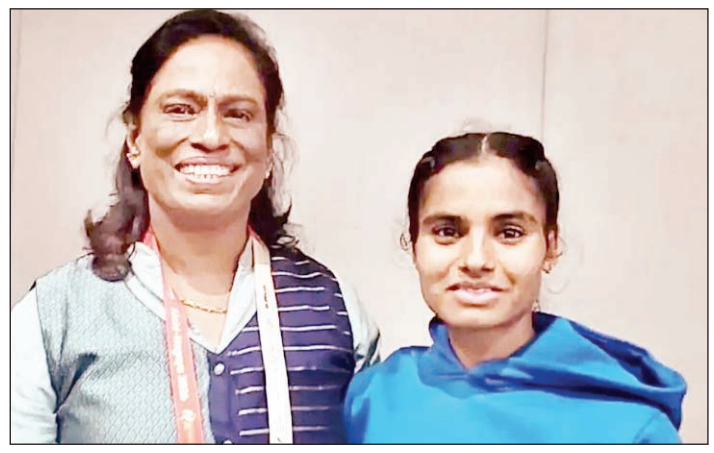


एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता चंबा की सीमा से मिलीं पीटी ऊषा

एजेंसी, नई दिल्ली

हिमाचल प्रदेश की धाविका सीमा के लिए जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेल यादगार बन गए हैं। 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली सीमा को अब भारतीय एथलेटिक्स की दिग्गज पीटी ऊषा का भी आशीर्वाद मिला है। जापान में हुई मुलाकात के दौरान पीटी ऊषा ने सीमा से बातचीत की और उसकी उपलब्धि की सराहना की। दोनों ने साथ में तस्वीर भी खिंचवाई, जिसे पीटी ऊषा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर साझा किया।

बातचीत के दौरान पीटी ऊषा ने सीमा के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए कहा कि उसने शानदार प्रदर्शन कर भारत को 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल बाद एशियाई खेलों का कांस्य पदक दिलाया है। पीटी ऊषा ने सीमा को आने वाली प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने दौड़ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी सीमा के साथ साझा किए, जो आगे की प्रतियोगिताओं में उसके काम आ सकते हैं।



सीमा की निगाहें अब 5000 मीटर पर

सीमा के लिए अगली चुनौती 5000 मीटर दौड़ है। पीटी ऊषा ने उम्मीद जताई कि सीमा इस स्पर्धा में भी मजबूत प्रदर्शन करेगी और देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर नया इतिहास रचेगी। इस मुलाकात के बाद चंबा के खेल प्रेमियों में भी उत्साह है। एक तरफ सीमा की एशियाई खेलों में पदक जीतने की उपलब्धि को हिमाचल और चंबा के लिए गौरव का विषय माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पीटी ऊषा जैसी दिग्गज खिलाड़ी से मिली सराहना ने इस उपलब्धि को और खास बना दिया है। सीमा की सफलता का असर केवल एक पदक तक सीमित नहीं है। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। उनकी उपलब्धि हिमाचल के उन युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बन रही है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद खेलों में आगे बढ़ने का सपना देखते हैं। अब चंबा सहित पूरे हिमाचल के खेल प्रेमियों की नजरें सीमा की आगामी 5000 मीटर स्पर्धा पर टिकी हैं।

ईशा ने 25 मी. पिस्टल में जीता रजत

एशियन गेम्स में पिंकी बलहारा ने कुराश में भारत के लिए कांस्य पदक जीता

एजेंसी, नागोया

भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने सोमवार को यहां एशियाई खेलों की महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में एक गलत निशाने से स्वर्ण पदक गंवाया, लेकिन लगातार पांच शूट-ऑफ के रोमांचक दौर के बाद रजत पदक पक्का करने में सफल रही। वहीं, भारत की पिंकी बलहारा ने एशियाई खेल 2026 में महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कुराश में कांस्य पदक जीता। हैदराबाद की निशानेबाज 21 वर्षीय ईशा अपने वर्ग की मौजूदा विश्व नंबर एक हैं। उन्होंने रजत की दौड़ में बने रहने के लिए तीन शूट-ऑफ जीते। इसके बाद स्वर्ण पदक के मुकाबले में उन्हें चीन की शियाओ जियारुईशुआन के साथ दो और शूट-ऑफ से गुजरना पड़ा।

निर्धारित सीरीज के बाद दोनों के 38-38 अंक थे, लेकिन अंतिम निशाने में ईशा चूक गईं और उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। उत्तर कोरिया की किम ह्योन सुक ने ईशा के खिलाफ शूट-ऑफ में हारने के बाद 34 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। उन्होंने कहा ,'मैं दबाव में थी और यह मेरे





कैरियर का सबसे लंबा मैच था । आखिर में मेरे हाथ दुखने लगे थे।' वहीं, भारत की पिंकी बलहारा ने एशियाई खेल 2026 में महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग के कुराश में कांस्य पदक जीता।

सोमवार को आइची प्रीफेक्चरल मार्शल आर्ट्स हॉल में खेले गए सेमीफाइनल में उन्हें दक्षिण कोरिया की सुमिन मो के खिलाफ 0-5 से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पिंकी ने इससे पहले क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की गारम लिम को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उन्हें राउंड ऑफ 16 में बाई मिली थी। यह पिंकी बलहारा का एशियाई खेलों में दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2018 एशियाई खेलों में महिलाओं के 52 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। उस फाइनल में उन्हें उज्बेकिस्तान की गुलनोर सुलेमानोवा से हार का सामना करना पड़ा था।

महिला 400 मी. बाधा दौड़ में वित्या रामराज ने जीता कांस्य पदक

नागोया। भारत की वित्या रामराज ने महिला 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया है। वित्या ने अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 54.75 सेकेंड का समय लिया और तीसरे स्थान पर रहकर पदक दिलाया। भारत की एक अन्य एथलीट अनु राघवन 55.88 सेकेंड के अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। वहीं, पुरुष 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार तमिलसरन पदक लाने से चूक गए। संतोष ने 49.95 सेकेंड का समय लिया और आठ धावकों में आठवें स्थान पर रहे।



भारतीय पुरुष-महिला टीमों ने स्क्वॉश में चीन को हराया

एजेंसी, नागोया

भारतीय पुरुष स्क्वॉश टीम ने सोमवार को एशियाई खेलों के अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पूल ए में चीन को 3-0 से हराया, जबकि महिला टीम ने शुरुआती झटके से उबरते हुए पूल सी के मुकाबले में चीन को 2-1 से मात दी। पुरुष टीम को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सूरज चंद, वीर चोटरानी और वेलावन सेंथिलकुमार ने अपने-अपने मुकाबले आसानी से जीतकर भारत को लगातार तीन मैचों में जीत दिलाई। सूरज ने 30 मिनट में डू शाओचियान को 11-4, 11-3, 12-10 से हराकर भारत को बढ़त दिलाई। शुरुआती दो गेम आसानी से जीतने के बाद तीसरे गेम में उन्हें कड़ी चुनौती मिली। डू ने गेम प्वाइंट हासिल किया, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने धैर्य बनाए रखते हुए 12-10 से गेम और मैच अपने नाम किया। इसके बाद चोटरानी ने यू हाइजेन को 11-5, 11-5, 11-3 से हराकर भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। वहीं, सेंथिलकुमार ने झोउ पेंगलिन को 11-3, 11-2, 11-4 से हराकर भारत की 3-0 से जीत पूरी की।



महिला टीम को हालांकि शुरुआती झटके के बाद वापसी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। समीना रियाज ने जियुआन यिन के खिलाफ दो गेम की बढ़त गंवा दी और उन्हें पांच गेम के कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारत के पूर्व एशियाई खेल हॉकी स्वर्ण पदक विजेता और ओलंपियन मोहम्मद रियाज की बेटी समीना ने शुरुआती दो गेम जीते, लेकिन मुकाबला अपने पक्ष में नहीं कर सकीं। वह 41 मिनट चले रोमांचक मुकाबले में 11-8, 11-6, 9-11, 9-11, 12-14 से हार गईं। इसके बाद तन्वी खन्ना ने झांग युनिंग को 11-3, 11-5, 11-5 से हराकर भारत की वापसी कराई। इसके बाद अनुभवी जोशना चिनप्पा ने लियू जियी को 22 मिनट में 12-10, 11-4, 11-6 से हराकर भारत को 2-1 से जीत दिला दी।

स्पोर्ट्स विंडो

मनु भाकर बिना पदक के वापस लौटीं

एजेंसी, नागोया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर इस स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद एशियाई खेलों से पदक के बिना लौटेंगी। ईशा ने क्वालीफिकेशन में आठवें स्थान पर रहते हुए फाइनल में पहुंचकर भारत की पदक उम्मीदें कायम रखीं। मनु 579 अंक के साथ 11वें स्थान पर रहीं, जो फाइनल में पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। ईशा ने क्वालीफिकेशन में 580 अंक जुटाए थे। मनु के लिए यह एशियाई खेलों का निराशाजनक अभियान रहा। इससे पहले वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी पदक जीतने में नाकाम रही थीं। भारतीय महिला टीम भी पदक की दौड़ में थी, लेकिन अहम समय पर राही सरनोबत की एक चूक टीम पर भारी पड़ी। सरनोबत ने चौथी सीरीज में 39 अंक का निराशाजनक स्कोर किया। इसके बाद भारत की पदक की उम्मीदें समाप्त हो गईं।



एशियन गेम्स: भारत व पाकिस्तान की टीमें सेमीफाइनल में पहुंची

एजेंसी, निशिन। एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो सकता है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। हालांकि, सेमीफाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने नहीं होंगे। सोमवार को भारत-अफगानिस्तान और पाकिस्तान-हॉन्ग कॉन्ग के बीच क्वार्टर फाइनल खेले जाने थे। लेकिन, बारिश के कारण दोनों मैच रद्द हो गए। इसके बाद बेहतर रैंकिंग के आधार पर भारत और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह मिली। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल तभी होगा, जब दोनों टीमें अपने-अपने सेमीफाइनल मैच जीतेंगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका और नेपाल के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा। वहीं, पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से भिड़ेगी। यानी फाइनल में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला देखने के लिए दोनों टीमों को सेमीफाइनल जीतना होगा। एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीमों में अब तक कोई मैच नहीं हुआ है। भारत 2022 से और पाकिस्तान 2010 से इस टूर्नामेंट में हिस्सा रहे रहा है। भारतीय टीम ने 2022 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। तब अफगानिस्तान के खिलाफ फाइनल मैच रद्द हुआ था और भारत चैंपियन बना था।

मौका गंवाना दुखद, एक नतीजा पूरे सफर को बयां नहीं कर सकता : सिंधु

एजेंसी, नई दिल्ली। एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद पीवी सिंधु ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि वह हार से दुखी हैं, लेकिन एक दर्दनाक नतीजा उनके 12 साल के एशियन गेम्स सफर को तय नहीं कर सकता। दो बार की ओलिंपिक मेडलिस्ट 27 सितंबर को विमेंस सिंगल्स के क्वार्टरफाइनल में चीन की चेन यूफेई से 21-11, 18-21, 10-21 से हार गई थीं। सिंधु ने लिखा, 'मुझे इसे शब्दों में कहने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। मेरा एशियन गेम्स अभियान खत्म हो गया है और मैं दुखी हूं। क्वार्टरफाइनल में जीत से सिर्फ तीन अंक दूर थी। मैं बार-बार उन्हीं तीन अंकों के बारे में सोच रही हूं।' सिंधु ने कहा कि चीन में खेले हालिया मुकाबले की तरह इस मैच में भी अहम मौकों पर लंबी और कड़ी रैलियां निर्णायक साबित हुईं। उन्होंने कहा, 'मेरे पास मौका था, लेकिन उसे गंवाना दुख देता है।' सिंधु ने कहा कि उनकी टीम पहले ही उन मौकों पर काम कर रही है, जहां मैच को अपने पक्ष में खत्म करने में चूक हुई।



पूर्व क्रिकेटर डेविड बून ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंतरिम चेयरमैन नियुक्त

एजेंसी, मेलबर्न। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड बून को अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। वह 28 अक्टूबर से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन माइक बेयर्ड के बोर्ड की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के बाद पद छोड़ने के फैसले के बाद बून को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है। बेयर्ड पिछले छह वर्षों से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड में शामिल थे और फरवरी 2023 से चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्होंने बोर्ड को बताया कि वह दोबारा नियुक्ति के लिए अपना नाम नहीं देंगे और एजीएम के बाद पद से हट जाएंगे। बून ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कहा, 'क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। यह क्रिकेट के लिए बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण समय है। मैं बोर्ड का नेतृत्व करते हुए ऐसे फैसले लेने के लिए उत्सुक हूं, जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और विकास को सुनिश्चित करें तथा वैश्विक स्तर पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के हितों को आगे बढ़ाएं।' बून फरवरी 2025 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड में शामिल हुए थे। इससे पहले वह नौ वर्षों तक क्रिकेट तस्मानिया के निदेशक रहे, जिसमें तीन वर्ष उन्होंने चेयरमैन के रूप में भी काम किया।



भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन सेमीफाइनल में पहुंचीं

एजेंसी, नागोया

भारत की स्टार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई खेल 2026 में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाकर भारत का एक और पदक पक्का कर दिया है। सोमवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने दक्षिण कोरिया की 2010 एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता सियोंग सुयोन को 5-0 से हराया। लवलीना ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहले राउंड में दोनों मुक्केबाजों के बीच जमकर प्रहार हुए, लेकिन लवलीना ने बेहतर मुक्केबाजी करते हुए सभी जजों का फैसला अपने पक्ष में किया। दूसरे राउंड में सियोंग ने आक्रामक होकर वापसी की कोशिश की, लेकिन लवलीना ने अपने फुटवर्क और काउंटर अटैक से उनके हमलों का जवाब दिया। उन्होंने लगातार जैब लगाते हुए यह राउंड भी 5-0 से अपने नाम किया।



तीसरे राउंड में लवलीना ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया।

टेनिस महिला युगल स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त

एजेंसी, नागोया। एशियाई खेलों की टेनिस महिला युगल स्पर्धा में भारत का अभियान खत्म हो गया जब अंकिता रैना और रूतुजा भोसले की जोड़ी कजाखस्तान की यूलिया पुतिनत्सेवा और अन्ना दानिलिना से हारकर बाहर हो गई। भारतीय जोड़ी को 7 . 5, 3 . 6, 5 . 10 से पराजय का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल में भारत के सुमित नागल दक्षिण कोरिया के होंग सियोंगचान के खिलाफ पहले सेट में 3 . 2 से आगे थे जब बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा। मैच अब मंगलवार को शुरू होगा। वहीं, भारतीय टीम एशियाई खेलों की महिला युगल सेपकटेकरा स्पर्धा के ग्रुप चरण में बाहर हो गई।

मेसी ने किया हैरतअंगेज गोल, फिर भी हारी इंटर मियामी की टीम

एजेंसी, कोलंबस

लियोनल मेसी ने इंटर मियामी के लिए एक और करिश्माई प्रदर्शन करते हुए कोलंबस क्रू के खिलाफ एक असंभव सा दिखने वाला फ्री-किक गोल दागा। हालांकि वह अपनी टीम को मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) के इस मुकाबले में 1-2 की हार से नहीं बचा सके। मेसी के गोल के बावजूद उनकी टीम हार टाल नहीं सकी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले मेसी का ये गोल देखकर दर्शक भी चौंक गए। कोलंबस क्रू ने मैच के 28वें मिनट में पेनल्टी के जरिए पहला गोल कर बढ़त बना ली।



कोलंबस ने स्टॉपेज टाइम में किया निर्णायक गोल

दूसरे हाफ में इंटर मियामी की ओर से एक खिलाड़ी ने डेब्यू किया। हाल ही में टीम से जुड़े ब्राजील के विंगर रिकेल्मे फिलिपी 71वें मिनट में फाकुंडो मुरा की जगह मैदान पर उतरे और क्लब के लिए अपना पहला मैच खेला। मैच के आखिरी पलों में कोलंबस क्रू ने स्टॉपेज टाइम में गोल करते हुए मैच में 2-1 की बढ़त बनाई और जीत दर्ज की। इस हार के बावजूद, इंटर मियामी का इस एमएलएस रेगुलर सीजन में प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है।

अगस्त में एक्सईवी 9एस बनी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार

एजेंसी, मुंबई। अगस्त 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में महिंद्रा एक्सईवी 9एस ने डीलरशिप तक भेजी गई 4,508 इकाइयों के साथ पहला स्थान हासिल किया। इस दौरान टाटा पंच ईवी की 4,430 इकाइयां भेजी गईं। दोनों मॉडलों के बीच महज 78 इकाइयों का अंतर रहा। जुलाई में एक्सईवी 9एस की 4,131 इकाइयों की तुलना में अगस्त में इसकी डिलीवरी के लिए भेजी गई संख्या करीब 9.1 प्रतिशत बढ़ी। जनवरी 2026 में ग्राहकों को डिलीवरी शुरू होने के बाद से इस मॉडल की मांग में लगातार मजबूती देखी जा रही है। कंपनी एक्सईवी 9एस को 59, 70 और 79 किलोवाट-घंटे के तीन बैटरी विकल्पों के साथ पेश करती है। संस्करण के अनुसार इसकी दावा की गई अधिकतम दूरी 521 से 679 किलोमीटर तक है।



◆पंच ईवी से 78 यूनिट आगे रही एक्सईवी 9एस

इसकी शुरुआती कीमत 20.65 लाख रुपये है। दूसरी ओर, पंच ईवी ने भी सालाना आधार पर मजबूत वृद्धि दर्ज की। अगस्त 2025 में इसकी 1,476 इकाइयां भेजी गई थीं, जो अगस्त 2026 में बढ़कर 4,430 हो गईं। इसकी शुरुआती कीमत 9.79 लाख रुपये है।

भारत में पुनः उपयोगी रॉकेट विकसित करेगा अग्निकुल कॉसमॉस

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका के बीच अग्निकुल कॉसमॉस को पुनः उपयोगी प्रक्षेपण यान विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता मिली है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और अग्निकुल कॉसमॉस के बीच इस परियोजना के लिए समझौता हुआ है। यह राशि अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। प्रस्तावित प्रक्षेपण यान का नाम 'अग्निबाण आरएलवी' रखा गया है। इसका उद्देश्य ऐसा स्वदेशी रॉकेट विकसित करना है, जिसे उपग्रह प्रक्षेपित करने के बाद वापस धरती पर लाया जा सके और आवश्यक परीक्षण तथा रखरखाव के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। पुनः उपयोगी प्रक्षेपण यान से भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की लागत और प्रक्षेपण में लगने वाला समय कम करने में मदद मिल सकती है। इस परियोजना को भारत में निजी अंतरिक्ष उद्योग और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अमेरिका-चीन के बीच '30-फॉर-30' व्यापार समझौते का एलान

एजेंसी, वाशिंगटन

अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से जारी व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में दोनों देशों ने महत्वपूर्ण समझौता किया है। नए '30-फॉर-30' ढांचे के तहत दोनों पक्ष 30 अरब डॉलर मूल्य के गैर-संवेदनशील सामान पर सीमा शुल्क कम करने की सिफारिश करेंगे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने इसकी घोषणा की। यह फैसला चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद सामने आया है।



77 श्रेणियों की चीनी वस्तुओं पर अमेरिका घटाएगा आयात शुल्क

समझौते के तहत दोनों देशों ने कुछ उत्पादों के लिए अलग-अलग सूचियां तैयार की हैं। अमेरिका से चीन को निर्यात होने वाले कृषि उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों को कम शुल्क पर चीनी बाजार में पहुंच देने की बात कही गई है। इनमें अनाज, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं। इसके बदले अमेरिका चीन से आयात होने वाली 77 श्रेणियों की उपभोक्ता वस्तुओं पर शुल्क घटाने पर सहमत हुआ है।

एक अक्टूबर से महंगी होंगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

एजेंसी, नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। एक अक्टूबर से एसी, टीवी, फ्रिज और वाशिंग मशीन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख घरेलू उपकरण कंपनियां कीमतों में करीब चार से 10 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकती हैं। वहीं, कुछ उत्पादों के दाम पांच से आठ प्रतिशत तक बढ़ने की बात सामने आई है। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी होगी। कंपनियों के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, धातुओं के महंगे होने, ईंधन की लागत बढ़ने और ढुलाई खर्च में इजाफे का असर उत्पादों की कीमतों पर पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण आपूर्ति व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ा है। त्योहारों के दौरान लोग नए टीवी, फ्रिज, एसी और अन्य घरेलू उपकरण खरीदते हैं। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी से त्योहारी खरीदारी का बजट प्रभावित हो सकता है।

शेयर बाजार एफआईआई बिकवाली और महंगे कच्चे तेल से शेयर बाजार में भारी गिरावट

सेंसेक्स 1124 अंक टूटा, निफ्टी 22800 के नीचे बंद

एजेंसी, मुंबई

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 28 सितंबर को भारी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और रुपये में कमजोरी के बीच घरेलू बाजार में चौतरफा दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,124.02 अंक यानी 1.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 72,771.72 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 360.25 अंक यानी 1.56 प्रतिशत टूटकर 22,780.25 अंक पर पहुंच गया। इस गिरावट के साथ निफ्टी 22,800 के स्तर से नीचे बंद हुआ। बाजार में बिकवाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीएसई पर कारोबार करने वाले 4,717 शेयरों में से 3,100 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 1,367 शेयरों में बढ़त रही। 250 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।



मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक भी फिसले

निफ्टी के प्रमुख गिरने वाले शेयरों में जियो फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स शामिल रहे। दूसरी ओर डॉ. रेड्डीज लैब्स और इंफोसिस के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। बाजार में किसी भी क्षेत्रीय सूचकांक को राहत नहीं मिली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सूचकांक में करीब तीन प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि दूरसंचार सूचकांक दो प्रतिशत नीचे रहा। ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, एफएमसीजी, रियल्टी, निजी बैंक, धातु और तेल एवं गैस क्षेत्र के सूचकांकों में भी एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी मिडकैप सूचकांक 1.7 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक 1.8 प्रतिशत फिसल गया।

बाजार की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रही। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 2.27 प्रतिशत बढ़कर 106.70 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण निवेशकों की चिंता बढ़ी हुई है। इसके अलावा एशियाई बाजारों में भी कमजोरी का असर घरेलू बाजार पर पड़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्की 225 और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक दबाव में रहे। अमेरिकी शेयर बाजार के वायदा कारोबार में भी कमजोरी रही, जिससे वैश्विक स्तर पर निवेशकों का रुख सतर्क बना रहा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। उन्होंने शुक्रवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में बिकवाली करते हुए 3,696 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे।